● वर्ष-5

● अंक-159

रायपुर, मंगलवार
17 फरवरी 2026

● पृष्ठ-8

● मूल्य-3 रु.

।। संगच्छध्वम् संवदध्वम् ।।

समाचार पचीसा

राजनीति का जनपक्षकार

पेज-8› महिला स्व सहायता समूहों ने ...

एआई बनेगा भारत की नई शक्ति

एआई समिट का पीएम मोदी ने किया उद्घाटन

नईदिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज (16 फरवरी) राजधानी राजधानी के भारत मंडपम में इंडिया एआई इम्पैक्ट एक्सपो 2026 का उद्घाटन किया। यह एक्सपो 16 से 20 फरवरी तक इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट के साथ आयोजित किया जाएगा और इसे कृत्रिम बुद्धिमत्ता के व्यावहारिक उपयोग को प्रदर्शित करने वाले एक राष्ट्रीय मंच के रूप में देखा जा रहा है, जो नीति निर्माण, नवाचार और व्यापक कार्यान्वयन को एक ही मंच पर लाएगा। 70,000 वर्ग मीटर से अधिक क्षेत्र में फैले 10 क्षेत्रों में आयोजित होने वाले इस कार्यक्रम में वैश्विक प्रौद्योगिकी कंपनियां, स्टार्टअप, शैक्षणिक और अनुसंधान संस्थान, केंद्रीय मंत्रालय, राज्य सरकारें और अंतर्राष्ट्रीय भागीदार भाग ले रहे हैं।

इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 के दौरान जियो एआई पवेलियन में जियो के चेयरमैन आकाश अंबानी ने माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा, संस्कृति और स्मार्ट होम सॉल्यूशंस के क्षेत्र में कंपनी के एआई-आधारित परिवर्तन का प्रदर्शन किया। 20

से अधिक राष्ट्राध्यक्ष, 60 मंत्री और 500 वैश्विक एआई नेता एआई इम्पैक्ट समिट 2026 के लिए नई दिल्ली में एकत्रित हुए। एआई इम्पैक्ट समिट तीन मूलभूत स्तंभों या %सूत्रों% पर आधारित है- लोग, ग्रह और प्रगति। इंडिया एआई इम्पैक्ट एक्सपो में 30 देशों के 300 से अधिक प्रदर्शकों के 10 से अधिक विषयगत पवेलियनों में भाग लेने की उम्मीद है। भारत-एआई इम्पैक्ट समिट 2026 का उद्देश्य कृत्रिम बुद्धिमत्ता के लिए प्रभाव-उन्मुख और जन-केंद्रित दृष्टिकोण को बढ़ावा देना है, जिसमें मापने योग्य सामाजिक और आर्थिक परिणामों को प्राप्त करने पर जोर दिया गया है। यह शिखर सम्मेलन तीन मूलभूत स्तंभों पर आधारित है। जिन्हें सूत्र कहा जाता है - एक संस्कृत शब्द जिसका अर्थ है मार्गदर्शक सिद्धांत या आवश्यक सूत्र जो ज्ञान और कर्म को आपस में जोड़ते हैं।

ये सूत्र परिभाषित करते हैं कि किस प्रकार बहुपक्षीय सहयोग के माध्यम से सामूहिक लाभ के लिए एआई का उपयोग किया जा सकता है।

इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के अनुरूप केंद्रित और परिणामोन्मुखी परिणाम दे रहा है। यह समिट सरकार और उद्योग जगत में प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए व्यावहारिक एआई तैनाती, नीतिगत सामंजस्य और संस्थागत समन्वय को बढ़ावा दे रहा है। यह शासन और नियामक ढांचों को मजबूत कर रहा है, एआई-आधारित औद्योगिक विकास के लिए क्षेत्रीय तैयारियों का आकलन कर रहा है और कौशल विकास एवं कार्यबल परिवर्तन को गति दे रहा है। यह समिट एआई अनुप्रयोगों के बारे में जागरूकता बढ़ा रहा है और एआई पारिस्थितिकी तंत्र के जिम्मेदार, समावेशी और नवाचार-संचालित विकास को बढ़ावा देने के लिए सरकार, शिक्षा जगत, स्टार्टअप और उद्योग के बीच स्थायी साझेदारी को बढ़ावा दे रहा है।

दिल्ली पुलिस की 10 योजनाएं शुरु कर बोले शाह

आतंकवाद और नक्सलवाद के खिलाफ केंद्र की नीति 'जीरो टॉलरेंस' की

नई दिल्ली। नई दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने लाल किले के पास हुए आतंकी हमले और देश में नक्सलवाद के मुद्दे पर महत्वपूर्ण बयान दिया है। केंद्रीय मंत्री शाह ने कहा कि चाहे संसद पर हमला रहा हो या कुछ दिनों पहले लाल किले के पास हुआ आतंकी हमला, हर चुनौती के सामने दिल्ली पुलिस ने अत्यंत कौशल और तत्परता का परिचय दिया है। उन्होंने कहा कि सभी मामलों में आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई सुनिश्चित हुई है। केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि कानून व्यवस्था से किसी भी तरह का समझौता नहीं होगा। केंद्रीय मंत्री शाह ने बताया कि देश से नक्?सलवाद का खात्?मा अब बहुत करीब पहुंच चुका है।

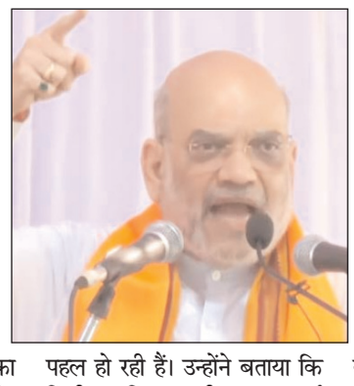

केंद्रीय गृह मंत्री शाह ने दिल्ली पुलिस की सराहना कर कहा कि राजधानी की सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत बनाने के लिए कई नई पहल हो रही हैं। उन्होंने बताया कि दिल्ली पुलिस की 10 नई परियोजनाओं का शिलान्यास किया है। इसके तहत दिल्ली को 10 हजार नए सीसीटीवी कैमरों से जोड़ने की योजना पर काम शुरू हो चुका है। पहले चरण में 2100 कैमरे लाइव हो चुके हैं, जबकि पहले से लगे 15 हजार से अधिक कैमरों को भी इस नेटवर्क से जोड़ने का काम पूरा किया है। उन्होंने विश्वास जताया कि 'सेफ सिटी' योजना आने वाले समय में दिल्ली की सुरक्षा को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाएगी और अपराध नियंत्रण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।

शाह ने नक्सलवाद के मुद्दे पर बड़ा दावा कर कहा कि केंद्र माओवादी हिंसा से देश को पूरी तरह मुक्त कराने के लक्ष्य के बहुत करीब पहुंच चुकी है। मोदी सरकार की सख्त नीति, सुरक्षा बलों की रणनीतिक कार्रवाई और विकास कार्यों के कारण नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में हिंसा में लगातार कमी आई है। उन्होंने भरोसा जताया कि 31 मार्च 2026 तक भारत को माओवादी हिंसा से मुक्त होगा।

केंद्रीय गृह मंत्री शाह ने दो टूक कहा कि आतंकवाद और नक्सलवाद के खिलाफ केंद्र सरकार की नीति 'जीरो टॉलरेंस' की है। उन्होंने कहा कि देश की आंतरिक सुरक्षा को मजबूत करना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है और इसके लिए आधुनिक तकनीक, खुफिया तंत्र और सुरक्षा बलों के बीच बेहतर समन्वय पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है।

रायपुर। महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े के मुख्य आतिथ्य में सूरजपुर जिले के तिलसिंवा स्थित ऑडिटोरियम में श्रमिक जन संवाद एवं सम्मेलन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य श्रमिकों, दिहाड़ी मजदूरों एवं असंगठित क्षेत्र के कामगारों को शासन की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं से जोड़ना तथा उन्हें सामाजिक सुरक्षा एवं आर्थिक सहयोग उपलब्ध कराना रहा।

गवर्नर के अभिभाषण पर शुक्ला का पलटवार

आरडीजी हिमाचल का हक है, कोई भीख नहीं

नईदिल्ली। हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ला द्वारा विधानसभा में पूर्ण भाषण न देने के फैसले के बाद मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सोमवार को कहा कि यह कदम कोई अपवाद नहीं है और उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि राजस्व घाटा अनुदान (आरडीजी) का मामला राज्य के अधिकारों से संबंधित है। हिमाचल प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र के पहले दिन शिमला में मीडियाकर्मियों से बात करते हुए सुक्खू ने कहा कि अतीत में भी राज्यपालों ने भाषण के कुछ हिस्सों को छोड़ दिया था। उन्होंने कहा कि राज्यपाल का भाषण न देना कोई अपवाद नहीं है। पहले भी राज्यपालों ने भाषण नहीं दिया है।

मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि यह मुद्दा राज्य सरकार द्वारा सहायता मांगने का नहीं, बल्कि हिमाचल प्रदेश के वित्तीय अधिकारों की रक्षा करने का है। यह सरकार का मामला नहीं है। आरडीजी हमारा अधिकार है। हम कोई दान नहीं मांग रहे हैं। राज्य के अधिकारों का हनन न करें। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि हिमाचल प्रदेश एक पहाड़ी राज्य होने के कारण राजस्व सृजन क्षमता के मामले में

बड़े राज्यों से तुलना नहीं की जा सकती। उन्होंने हिमाचल प्रदेश की अनूठी वित्तीय चुनौतियों पर प्रकाश डालते हुए कहा कि एक पहाड़ी राज्य होने के नाते, इसकी राजस्व सृजन क्षमता बड़े राज्यों की तुलना में सीमित है।

आप 17 राज्यों की बात करते हैं, लेकिन हिमाचल की तुलना उनसे नहीं की जा सकती। उन राज्यों में बड़ी परियोजनाएं और मजबूत राजस्व आधार हैं। हिमाचल एक पहाड़ी राज्य है जहां प्राकृतिक संसाधनों और भौगोलिक बाधाओं के कारण राजस्व सृजन स्वाभाविक रूप से सीमित है। 16वें वित्त आयोग की सिफारिशों के बाद आरडीजी (अंतर्राष्ट्रीय विकास योजना) को समाप्त किए जाने का जिक्र करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने मुख्य रूप से इस मुद्दे पर विचार-विमर्श करने के लिए तीन दिवसीय विधानसभा सत्र बुलाया है। उन्होंने आगे कहा कि हमने आरडीजी पर चर्चा करने के लिए यह तीन दिवसीय सत्र बुलाया है। मुझे उम्मीद है कि भाजपा दलीय भेदभाव से ऊपर उठकर राज्य के अधिकारों की बहाली के लिए केंद्र सरकार से संपर्क करने में हमारा साथ देगी।

प्रमुख समाचार

भारत को फाइटर जेट इंजन देने के लिए भिड़े फ्रांस-ब्रिटेन

नईदिल्ली। भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हाल ही में कहा था कि इंडीजीनियस फाइटर जेट इंजन का उत्पादन अगले साल से भारत में शुरू होगा। यह बयान सामान्य नहीं था। यह संकेत था कि भारत अब जेट इंजन टेक्नोलॉजी के सबसे कठिन और विशिष्ट क्लब में प्रवेश करने जा रहा है। यूके की 240 के एन डील क्या है और एमका को इससे कितना बड़ा बूस्ट मिलेगा और कावेर इंजन प्रोग्राम का भविष्य क्या होगा।

दरअसल फाइटर जेट बनाना कठिन है लेकिन जेट इंजन बनाना उससे भी ज्यादा कठिन है। एक आधुनिक टर्बो फैन इंजन में लगभग 3000 से अधिक प्रसीजन कॉम्पोनेंट होते हैं। इनमें से कई पार्ट्स 1500 डिग्री सेल्सियस से भी ज्यादा तापमान पर काम करते हैं। सुपर एलॉय मटेरियल सिंगल क्रिस्टल ब्लेड टेक्नोलॉजी, एडवांस कूलिंग सिस्टम यह सब मिलाकर जेट इंजन बनता है। दुनिया में बहुत कम देश हैं जो यह क्षमता रखते हैं। अमेरिका, रूस, फ्रांस, यूके और चीन। अब भारत इस सूची में शामिल होने की तैयारी कर रहा है।

पवन खेड़ा प्रवक्ता नहीं बल्कि एक तोता है: मणिशंकर

तिरुवनंतपुरम। केरल के मुख्यमंत्री पिनरई विजयन की तारीफ करने और फिर से सीएम बनने का दावा करके कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री मणिशंकर अय्यर अपनी ही पार्टी के निशाने पर आ चुके हैं। तिरुवनंतपुरम में रविवार को एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम विजयन की मौजूदगी उन्होंने कहा कि पिनरई विजयन केरल के मुख्यमंत्री बने रहेंगे। उनके इस

बयान के बाद सियासी भूचाल आ गया, जिसके बाद पार्टी नेताओं ने उनके इस बयान की आलोचना की। अय्यर के बयान के बाद कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा और महासचिव व संचार प्रभारी जयराम रमेश की प्रतिक्रिया आई। जिस पर अब मणिशंकर अय्यर ने तीखा पलटवार किया है। कांग्रेस नेता अय्यर ने पवन खेड़ा को आड़े हाथों लेते हुए उनको कठपुतली करार दिया, साथ ही कहा कि वो पार्टी के अधिकृत प्रवक्ता नहीं हैं। उन्होंने दो टूक पवन खेड़ा को एक कठपुतली बताया, जो पार्टी महासचिव जयराम रमेश के कहे अनुसार ही काम करता है।- यूज एजेंसी एएनआई से बात करते हुए मणिशंकर अय्यर ने कहा कि पवन खेड़ा प्रवक्ता नहीं बल्कि एक तोता है।

भारतीय किसानों का हित खतरे में : सुरजेवाला

नईदिल्ली। भारत और अमेरिका के बीच हाल ही में हुए व्यापार समझौते को लेकर देशभर में चर्चा तेज है। एक तरफ सत्ता पक्ष इसे भारत सरकार की बड़ी उपलब्धि बता रही है। वहीं दूसरी ओर विपक्ष इसे भारत की नहीं अमेरिका की जीत बता रहा है। इसी बीच अब कांग्रेस सांसद रणदीप सुरजेवाला ने इस व्यापार समझौते को लेकर केंद्र सरकार पर बड़ा हमला बोला है। भारत और अमेरिका के बीच हुए अंतरिम व्यापार समझौते ने भारतीय किसानों, ऊर्जा सुरक्षा और डिजिटल स्वतंत्रता को अमेरिका के हितों के लिए खतरे में डाल दिया है। एक सम्मेलन में बोलते हुए सुरजेवाला ने सवाल किया कि क्या आत्मनिर्भर भारत का नारा अब अमेरिका-निर्भर भारत बन गया है। इस व्यापार समझौते में प्रधानमंत्री मोदी सरकार ने किसानों और कृषि भूमि के मालिकों के हितों का बलिदान किया। सुरजेवाला ने कहा कि भारतीय ऊर्जा सुरक्षा और डिजिटल स्वतंत्रता पर गंभीर सवाल उठते हैं। मजबूत होने के बजाय सरकार ने भारतीय हितों और डेटा गोपनीयता पर समझौता किया। जनता पूछ रही है कि विदेश मंत्रालय की प्रतिक्रिया की भी आलोचना कीइस दौरान सुरजेवाला ने विदेश मंत्रालय की प्रतिक्रिया की भी आलोचना की।

मोदी के आने से पहले इजरायल का भारत पर बड़ा ऐलान

नईदिल्ली। भारत और इजराइल के संबंध बेहद अच्छे हैं और इसी पर बात करते हुए इजराइली प्रधानमंत्री भारत और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ कर रहे हैं। अपने इस भाषण में नेतन्याहू बात करते दिख रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इसी महीने होने वाली इजराइल यात्रा की। दरअसल , नेतन्याहू का यह वीडियो सामने आया है जिसमें वह मन से कहते हुए सुनाई दे रहे हैं कि अगले हफ्ते यहां कौन आ रहा है? नरेंद्र मोदी इजराइल और भारत के बीच जबरदस्त गठबंधन है। भारत में इजराइल बेहद लोकप्रिय है। आपको याद दिला दें 2017 में पीएम मोदी की ऐतिहासिक इजराइल यात्रा ने दोनों देशों के रिश्तों को नई ऊंचाई दे दी थी। अब नेतन्याहू ने अपने बयान में यह भी कहा है कि कई देश हैं जो इजराइल के साथ रक्षा और तकनीक के क्षेत्र में निवेश करना चाहते हैं। जहां वो जर्मनी का जिक्र भी करते हैं। लेकिन जिस अंदाज में उन्होंने भारत का नाम लिया उससे यह साफ है कि भारत उनके लिए सिर्फ एक साझेदार नहीं बल्कि एक स्ट्रेटेजिक पिलर बन चुका है।

लड़का-लड़की सावधानी बरतें: सुप्रीम कोर्ट

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कहा कि शादी से पहले लड़का और लड़की एक-दूसरे के लिए पूरी तरह से अजनबी होते हैं। इसलिए, उन्हें शादी से पहले शारीरिक संबंध बनाते समय सावधानी बरतनी चाहिए। शीर्ष अदालत ने यह टिप्पणी शादी का झूठा वादाकर दुष्कर्म करने के आरोपी एक व्यक्ति की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए की।

यह मामला उस व्यक्ति से जुड़ा है जिस पर आरोप है कि उसने महिला को शादी का भरोसा देकर शारीरिक संबंध बनाए। बाद में महिला को पता चला कि वह पहले से शादीशुदा है और उसने दूसरी शादी भी कर ली है। इसके बाद महिला ने उसके खिलाफ दुष्कर्म का मामला दर्ज कराया था। जस्टिस बी.वी. नागरत्ना और उज्जल भुइयां की पीठ ने कहा कि अगर कोई महिला शादी को लेकर गंभीर है तो उसे शादी से पहले इस तरह के संबंध बनाने में सावधानी बरतनी चाहिए। पीठ ने महिला से पूछा कि वह दुबई तक क्यों गई, जहां उन्होंने शारीरिक संबंध बनाए। पीठ ने कहा कि यह सहमति से होता है।

दलित विमर्श

मोहल्ले का झगड़ा नहीं, लोकतंत्र की बुनियादी आवाज

यौराज सिंह बेचैन

विगत माह हैदराबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय में 'हिंदी साहित्य समकालीन विमर्श' विषय पर आयोजित राष्ट्रीय संगोष्ठी में साहित्य, सिनेमा, सांस्कृतिक और राजकीय सेवाओं में वंचितों के प्रतिनिधित्व पर चर्चा हुई। इन पंक्तियों के लेखक द्वारा बीज वक्तव्य देने के बाद हिंदू कॉलेज से सेवानिवृत्ती प्रोफेसर राय साहब ने हिंदी साहित्य में चार दशकों से चल रहे विमर्शों को इन मुहावरों में समेट दिया, स्त्री विमर्श घरों के झगड़े हैं और दलित-आदिवासी विमर्श मोहल्लों के झगड़े हैं।% इसलिए संवाद स्त्री, दलित और आदिवासी विमर्श की पृष्ठभूमि से ही शुरू करना पड़ा।

विविधता पूर्ण अभिव्यक्तियां विमर्शों की आत्मा हैं। दलित-विमर्श समकालीन विमर्शों का मूल है। सभी विमर्शों को मिला कर देखें, तो यह देश की अस्सी फीसदी से अधिक आबादी की रचनात्मक अभिव्यक्ति है। हालांकि संत साहित्य में जन्म-जाति को लेकर समता, स्वतंत्रता मूलक मूल्यों की पृष्ठभूमि है, जिसमें ईश्वर की दृष्टि से समानता की बात होती है। यह विमर्श अमेरिका और अफ्रीका के 'ब्लैक पैंथर से मराठी के %दलित पैंथर% में आया और हिंदी पर इसका गहरा प्रभाव पड़ा। इसका उद्देश्य मनुष्य से मनुष्य की मुक्ति के लिए अन्याय और अपमान का अंत कर आधुनिक लोकतांत्रिक मूल्यों पर आधारित समता मूलक सभ्य समाज बनाना है।

आज से ठीक तीस साल पहले 25 फरवरी, 1996 को संपादक मूलचंद गौतम की पत्रिका की ओर से ओम प्रकाश वाल्मीकि को 'परिवेश सम्मान दिया गया था। तब मुख्य अतिथि काशीनाथ सिंह ने कहा था- यदि दलितों द्वारा लिखा हुआ ही दलित साहित्य माना जाएगा, तो घोड़े पर लिखने के लिए घोड़ा होना पड़ेगा। यह सुनकर वाल्मीकि विचलित थे। इसे परंपरा से चले आ रहे हिंदी लेखकों के संस्कारों में समाई वर्चस्व की भावना या सामंती स्वभाव की ठसक भी कह सकते हैं।

डॉ. आंबेडकर ने अपनी पुस्तक अनटचेबल्स में अशरीरी अस्पृश्यता को रेखांकित किया। यह दासप्रथा से भी अधिक अमानवीय और अन्यायपूर्ण है।

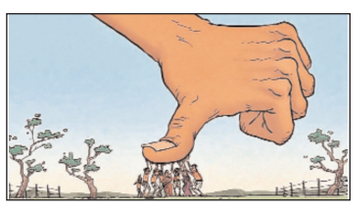

संविधान ने अस्पृश्यता निवारक कानून अमल में लाकर ऐसी कुप्रथाओं का अंत कर दिया। लोकतांत्रिक स्वभाव के अनुसार, नैतिक उपक्रम करने की वंचितों की दस्तक एक जैसी रही है। विमर्श का विस्तार साहित्य और सिनेमा में एक जैसा दिखाई पड़ता है। गांधीवादी प्रभाव में बनी अछूत कन्या जैसी फिल्में संविधान और आंबेडकर के प्रभाव तक आते-आते आयुष्मान खुराना की 'आर्टिकल 15', अमिताभ बच्चन और मनोज वाजपेई की 'आरक्षण' तक आया दिखता है। कालांतर में मराठी दलित निर्देशकों ने सिनेमा में अपनी उपस्थिति दर्ज की। नागराज मंजुले की 'सैराट' (2016) और 'फंद्री' फिल्म के बाद 'नीरज घेवान' के निर्देशन में आई 'होम बाउंड' ऑस्कर तक पहुंची है। लेकिन नीरज कहते हैं, आज भी किरदारों के नाम उच्च जाति सूचक ही होते हैं। दलित-आदिवासियों को लेकर मुस्लिम निर्देशकों के नजरिये में भी कोई अंतर नहीं है, उन्हें भी दलितों में नायक दिखाई नहीं पड़ते। वे भी 'लगान' में 'कचरा' के दम पर ऑस्कर पाना चाहते हैं।

साहित्य और सिनेमा की जो प्रवृत्तियां लोकतंत्र की प्रक्रिया में आड़े आती हैं, उनमें खास है परंपरागत जाति पूर्वाग्रह। यह इस हद तक गहरे पैठा कि, न केवल नीरज, बल्कि दलित प्रतिभाएं पहले भी जाति छिपाने को विवश होती रही हैं। डॉ. आंबेडकर को जातिगत पूर्वाग्रह का दंश झेलना पड़ा था। 1960 में 'दया पवार' ने %अछूत% आत्मकथा में हिकारत के प्रसंगों की भरमार कर दी। 'सारिका' मई 1975 में कमलेश्वर ने बाबूराव बागुल का लेख छाप कर हिंदी मानस की गहरी तंद्रा तोड़ दी थी। जब नीरज घेवान कहते हैं कि सिनेमा जगत में मैंने 35 साल तक अपनी जाति छिपा कर काम किया, तो लगता है हम फिर वहीं खड़े हैं। डॉ. आंबेडकर के आधुनिक विचारों ने मनुष्य को मनुष्य की दृष्टि और स्थिति में भी समान होने का प्रश्न बनाया। एक बार अब्राहम लिंकन ने कहा था, %मेरा अनुभव कह रहा है कि जिन लोगों में कोई दुर्गुण नहीं होता, उनमें सद्गुण भी बहुत कम होते हैं।% लिंकन के अनुभव की रोशनी में देखें, तो इतिहास के कई किरदार स्मरण हो आते हैं।

हिंसक अंगुलिमाल डाकू बुद्ध की शिक्षाएं पाकर हिंसा-डकैती छोड़कर भिक्षु 'अर्हत' हो जाता है, 'रत्नाकर' लुटेरे से महर्षि-आदिकवि हो जाते हैं। सम्राट अशोक कलिंग युद्ध में हजारों योद्धाओं की लाशों पर से गुजर कर प्रायश्चित करते हैं और अंतत: 'बुद्ध' की शरण में जाकर उनकी शिक्षाओं के प्रचारक बन जाते हैं। पर क्या हम आज यह सोच सकते हैं कि यूक्रेन-रूस युद्ध पुतिन और जेलेंस्की को बौद्ध बना देगा।

नक्सलगढ़ में एआई टेक्नीक, सुकमा के बच्चे बनेंगे टेक स्मार्ट

■ सुकमा में नक्सल प्रभावित क्षेत्रों के बच्चों को आधुनिक शिक्षा से जोड़ा जा रहा है। पोटाकेबिन में पढ़ने वाले बच्चे एआई की शिक्षा हासिल करेंगे।

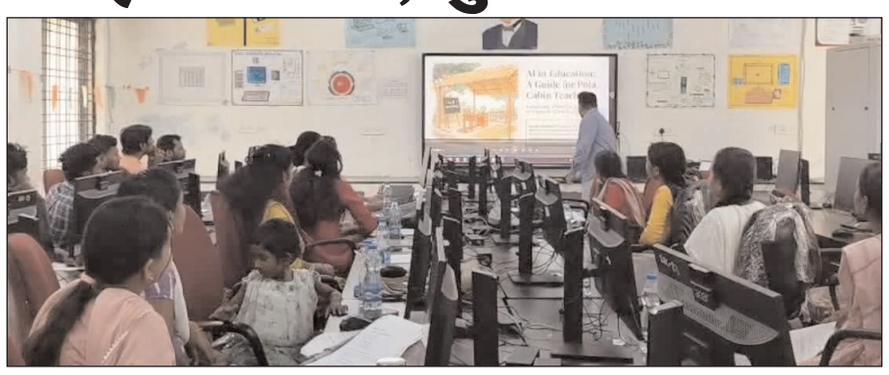

सुकमा। बस्तर के जंगलों, ऊबड़ खाबड़ पगडंडियों और गोलियों की गूंज से थर्राते इलाकों में अब एक नई आवाज सुनाई देने वाली है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) की। यह केवल तकनीक की दस्तक नहीं, बल्कि उम्मीद, बदलाव और नए सवेरे की आहट है। सुकमा का नाम आते ही बरसों तक दिमाग में बारूदी सुरंगें, मुठभेड़ और शहादत की खबरें तैर जाती थीं। गांवों के बच्चे स्कूल से ज्यादा डर की कहानियां सुनते बड़े हुए। कई इलाकों में स्कूल भवन क्षतिग्रस्त हुए, तो कहीं पढ़ाई सुरक्षा बलों की निगरानी में चलती रही। ऐसे माहौल में पोटाकेबिन स्कूल बच्चों के लिए सुरक्षित आश्रय बने जहां वे पढ़ सकें, खेल सकें और सपने देख सकें। अब इन्हीं पोटाकेबिन में तकनीक का प्रवेश उस बदलाव की कहानी लिखने जा रहा है, जिसकी कल्पना कुछ वर्ष पहले तक असंभव लगती थी।

इस पहल को जमीन पर उतारने के लिए जिला प्रशासन ने लाइवलीहुड कॉलेज सुकमा में पोटाकेबिन स्कूलों के शिक्षकों के लिए विशेष कार्यशाला का आयोजन किया है। इस कार्यशाला में शिक्षकों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के मूल सिद्धांत, आधुनिक टूल्स, डिजिटल कंटेंट निर्माण और बच्चों के लिए सरल प्रोजेक्ट आधारित शिक्षण पद्धति से परिचित कराया जा रहा है। यहां प्रशिक्षण पा रहे शिक्षक अब केवल पाठ्यपुस्तकों तक सीमित नहीं रहेंगे, बल्कि डिजिटल बोर्ड, स्मार्ट एप्लिकेशन और एआई आधारित लर्निंग मॉडल के माध्यम से पढ़ाई को रोचक बनाएंगे।

कार्यशाला का उद्देश्य स्पष्ट है पहले शिक्षक सशक्त, फिर छात्र समर्थ। प्रशिक्षण के बाद यही शिक्षक अपने-अपने पोटाकेबिन स्कूलों में जाकर बच्चों को एआई की बुनियादी समझ देंगे। बच्चों को सिखाया जाएगा कि एआई क्या है, यह कैसे काम करता है, और रोजमर्रा की जिंदगी में इसका उपयोग कैसे किया जा सकता है। जहां कभी बच्चे जंगल की पगडंडियों से गुजरते हुए स्कूल पहुंचते थे, वहीं अब वे डिजिटल दुनिया की पगडंडियों पर चलना सीखेंगे। यह बदलाव केवल शिक्षा का नहीं, बल्कि सोच का है। सुकमा के कई गांव ऐसे रहे हैं जहां विकास की रफ्तार नक्सली गतिविधियों के कारण थमी रही। इंटरनेट और तकनीकी संसाधनों की कमी ने बच्चों को मुख्यधारा से दूर रखा। लेकिन अब जब पोटाकेबिनों में एआई की पढ़ाई शुरू होगी, तो यह संदेश जाएगा कि शिक्षा सबसे बड़ी ताकत है। जहां कभी हथियारों की भाषा हावी थी, वहां अब कोडिंग और नवाचार की भाषा बोलेगी। नई पीढ़ी की यह पहल यह भी दर्शाती है कि विकास और शिक्षा ही किसी भी संघर्षग्रस्त क्षेत्र में स्थायी शांति का मार्ग प्रशस्त कर सकते हैं।

इस पूरी पहल में वेनिक किरो संस्था का भी महत्वपूर्ण योगदान है। संस्था के एआई प्रशिक्षक शिरीन कुणाल और उनकी टीम शिक्षकों को आधुनिक तकनीक से परिचित करा रहे हैं। उनका मानना है कि अगर सही दिशा और अवसर मिले तो सुकमा के बच्चे किसी से कम नहीं है।शिरीन कुणाल कहते हैं कि उनका उद्देश्य केवल तकनीक सिखाना नहीं, बल्कि आत्मविश्वास जगाना है। सुकमा के बच्चों ने बहुत कुछ देखा और सहा है, लेकिन उनमें सीखने की अद्भुत क्षमता है। एआई की शिक्षा उन्हें भविष्य के लिए तैयार करेगी। जब ये बच्चे अपने गांव में रहकर डिजिटल प्रोजेक्ट बनाएंगे, तब असली बदलाव दिखाई देगा।

शहरों से मुकाबला, अवसरों का विस्तार इस पहल के कई सकारात्मक प्रभाव होंगे -

शहरी बराबरी, सुदूर वनांचल के बच्चे भी अब तकनीक के मामले में महानगरों के छात्रों के साथ प्रतिस्पर्धा कर सकेंगे। रोजगार की नई राहें एआई डेटा एनालिटिक्स, रोबोटिक्स और डिजिटल कंटेंट निर्माण जैसे क्षेत्रों में भविष्य के अवसर खुलेंगे। तार्किक सोच का विकास एआई आधारित लर्निंग से बच्चों की विश्लेषणात्मक और रचनात्मक क्षमता बढ़ेगी। डिजिटल आत्मविश्वास, तकनीक का भय खत्म होगा और आत्मविश्वास बढ़ेगा। पोटाकेबिन में बदलेगी पढ़ाई की सूरत, अब पोटाकेबिनों में केवल ब्लैकबोर्ड और किताबें नहीं होंगी। डिजिटल कंटेंट, प्रोजेक्टर, इंटरएक्टिव मॉडल और एआई टूल्स के माध्यम से कठिन विषयों को सरल बनाया जाएगा।

बच्चे छोटे-छोटे प्रोजेक्ट्स बनाएंगे जैसे मौसम का डेटा विश्लेषण, स्थानीय कृषि समस्याओं के समाधान, या गांव की जरूरतों के अनुसार डिजिटल मॉडल तैयार करना। यह शिक्षा केवल परीक्षा पास करने के लिए नहीं, बल्कि जीवन की समस्याओं को हल करने के लिए होगी। जिन बच्चों ने बचपन में संघर्ष और असुरक्षा देखी, उनके लिए यह पहल उम्मीद की किरण है। अब वे डॉक्टर, इंजीनियर या पुलिस अधिकारी ही नहीं, बल्कि डेटा साइंटिस्ट, एआई डेवलपर और टेक्नोलॉजी इनोवेटर बनने का सपना भी देख सकते हैं। एक शिक्षक ने कहा, पहले हमारे बच्चे शहरों के बच्चों को देखकर ही प्रेरित होते थे, अब वे खुद प्रेरणा बनेंगे।

सुकमा में नक्सलियों पर बड़ी कार्रवाई, चार नक्सल स्मारक किए गए ध्वस्त

जगदलपुर। नक्सल उन्मूलन अभियान के तहत सुकमा जिले में सुरक्षा बलों की कार्रवाई लगातार जारी है। इसी क्रम में नक्सलियों के प्रभाव और प्रचार के प्रतीक माने जाने वाले स्मारकों को ध्वस्त किया गया है। पातादुलेर गांव में स्थित दो नक्सल स्मारक तथा एर्राबोर (छोटा कंचला) गांव में मौजूद दो नक्सल स्मारकों को मिलाकर कुल चार स्मारकों को केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की सेकेंड बटालियन के जवानों ने कार्रवाई करते हुए नष्ट किया। यह पूरी कार्रवाई कमांडेंट कमलेश कुमार के निर्देशन में योजनाबद्ध ढंग से की गई। अभियान के दौरान किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना नहीं हुई। सुरक्षा बलों ने क्षेत्र में सघन तलाशी अभियान चलाया और हालात पर पूरी तरह नियंत्रण बनाए रखा। प्रशासन का मानना है कि इस कार्रवाई से नक्सलियों के मनोबल पर गहरा असर पड़ा है और क्षेत्र में शांति स्थापना की दिशा में यह एक महत्वपूर्ण कदम है। इलाके में सुरक्षा व्यवस्था और कड़ी कर दी गई है तथा नक्सल विरोधी अभियान आगे भी जारी रहेगा।

देश के नक्सल प्रभावित जिलों की सूची जारी, बस्तर संभाग के सबसे ज्यादा जिले

■ भारत सरकार ने देश के नक्सल प्रभावित जिलों की सूची जारी की है.जिसमें से तीन जिले बस्तर संभाग के हैं.इन जिलों में फोर्स एक्टिव है.

जगदलपुर। भारत से नक्सलवाद के खात्मे की तारीख तय है।31 मार्च 2026 तक देश से नक्सलवाद के खात्मे को लेकर काउंटडाउन जारी है। जैसे-जैसे नक्सलवाद के खात्मे की तारीख पास आते जा रही है, वैसे वैसे फोर्स का दायरा नक्सल प्रभावित क्षेत्रों तक बढ़ता जा रहा है।ऐसे में कई बड़े नक्सलियों ने पुनर्वास का रास्ता अपनाया है।वहीं दूसरी ओर जो नक्सली अब भी हथियार नहीं छोड़ रहे हैं,उनके खिलाफ फोर्स की कार्रवाई जारी है। देश के गृहमंत्री अमित शाह ने 31 मार्च 2026 तक देश से नक्सलवाद के सफाए होने का दावा किया है। इसके बाद से ही नक्सल प्रभावित राज्यों में फोर्स का ऑपरेशन तेज हुआ। बात यदि नक्सलवाद की करें तो देश में अब केवल 6 जिले ही इससे प्रभावित हैं। इनमें से तीन जिले बस्तर संभाग के हैं। इन तीन जिलों में फोर्स नई रणनीति बनाकर काम कर रही है। पुलिस और सरकार के मुताबिक अभी भी इन जिलों में नक्सलियों की मौजूदगी है। सूचना तंत्र ने इन जिलों में नक्सल मूवमेंट की जानकारी दी है। बस्तर आईजी सुंदरराज पी ने बताया कि समय-समय पर भारत सरकार सूची जारी करती है। इसी कड़ी में भारत सरकार ने एक और सूची जारी की है, जिसमें नक्सल प्रभावित जिलों का आंकड़ा बताया गया है। बस्तर आईजी सुंदरराज पी ने बताया कि इन इलाकों में काफी फोकस के साथ नक्सलियों के खिलाफ कार्रवाई जारी है। इसके साथ ही अन्य जिलों में भी सर्चिंग सहित अन्य कार्रवाई जारी है। पूरे बस्तर संभाग के 7 जिलों में नक्सल विरोधी कार्रवाई जारी है। लेकिन हाई अलर्ट के साथ सुकमा, बीजापुर, नारायणपुर और गरियाबंद जिले में ज्यादा तैनाती की गई है।

मृतधारा महोत्सव में बवाल : नपाध्यक्ष और विधायक प्रतिनिधि नाराज होकर कार्यक्रम से निकले

मनेन्द्रगढ़। अमृतधारा महोत्सव के दौरान उस समय अप्रत्याशित स्थिति बन गई, जब नगरपालिका अध्यक्ष प्रतिमा यादव और उनके पति व विधायक प्रतिनिधि सरजू यादव नाराज होकर कार्यक्रम स्थल से बाहर निकल गए। इस घटना के बाद कुछ देर के लिए कार्यक्रम स्थल पर अफरा-तफरी और तनाव का माहौल बन गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार, महोत्सव में जनप्रतिनिधियों और अतिथियों की उपस्थिति में मंचीय कार्यक्रम जारी था। इसी दौरान मंच से विधायक प्रतिनिधि सरजू यादव का नाम पुकारा गया, लेकिन नगरपालिका अध्यक्ष प्रतिमा यादव का नाम नहीं लिया गया। बताया जा रहा है कि नाम पुकारे जाने के बावजूद सरजू यादव मंच पर नहीं गए और इसके बाद दोनों कार्यक्रम स्थल से बाहर चले गए। विवाद की एक वजह कार्यक्रम स्थल पर वाहन रोके जाने की घटना भी बताई जा रही है। विधायक प्रतिनिधि सरजू यादव के अनुसार, कार्यक्रम स्थल पर पुलिस द्वारा सुरक्षा के मद्देनजर बैरिकेडिंग की गई थी। इसी दौरान नगरपालिका अध्यक्ष प्रतिमा यादव और विधायक प्रतिनिधि सरजू यादव के वाहन को प्रवेश द्वार पर रोक दिया गया।

आरोप है कि वाहन पर नेम प्लेट लगी होने और मौके पर परिचय देने के बावजूद उन्हें आगे नहीं जाने दिया जा रहा था। इस बात से दोनों जनप्रतिनिधि नाराज हो गए। बताया जाता है कि बार-बार रोके जाने और पहचान बताने के बाद भी प्रवेश न मिलने पर विधायक प्रतिनिधि सरजू यादव ने गुस्से में आकर गाड़ी में लगा नगरपालिका अध्यक्ष का बोर्ड तोड़कर कार्यक्रम स्थल पर फेंक दिया।

इस घटना के बाद वहां मौजूद लोगों के बीच यह चर्चा का विषय बन गया। घटना के बाद कार्यक्रम स्थल पर कुछ देर के लिए तनावपूर्ण माहौल रहा। हालांकि, पुलिस और आयोजन समिति के सदस्यों ने स्थिति को संभालने का प्रयास किया। इसके बाद दोनों जनप्रतिनिधि कार्यक्रम स्थल से बाहर चले गए। घटना के बाद अमृतधारा महोत्सव की आयोजन समिति की व्यवस्था और पुलिस की भूमिका पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं।

पाली महोत्सव : मंत्री लखन लाल देवांगन हुए शामिल

कोरबा। ऐतिहासिक नगरी पाली में रविवार को महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर पाली महोत्सव 2026 का शुभारंभ शिव आरती, दीपोत्सव और भव्य आतिशबाजी के साथ हुआ। हजारों श्रद्धालुओं की उपस्थिति में शाम लगभग 7 बजे पाली शिव मंदिर घाट में शिव आरती और दीपोत्सव ने समां बांध दिया। पाली के ऐतिहासिक शिव मंदिर और सरोवर के चारो ओर दीपों की जगमगाती रोशनी और शांत माहौल में धार्मिक आस्था, सांस्कृतिक विरासत का मेल दिखाई दिया। आयोजन 15 और 16 फरवरी को ग्राम पंचायत केराझरिया स्थित पाली महोत्सव मैदान में किया जा रहा है। दो दिवसीय महोत्सव में धार्मिक आस्था, सांस्कृतिक विरासत और आधुनिक संगीत का भव्य संगम प्रस्तुत होगी।

शुभारंभ अवसर पर बॉलीवुड के लोकप्रिय गायक मीत ब्रदर्स, खुशबू ग्रेवल और सलमान अली ने अपने गीतों से समां बांधा। वहीं, कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ी कलाकार दीपक साहू और छत्तीसगढ़ी गायक ऋषिराज पांडेय द्वारा छत्तीसगढ़ी कार्यक्रमों की प्रस्तुति दी जाएगी। इस दौरान कठपुतली नृत्य भी आकर्षण का केंद्र रहेगा। पाली महोत्सव के अवसर पर युवाओं के उत्साह को प्रोत्साहित करने के लिए जिला प्रशासन द्वारा 15 फरवरी को साइकिल रेस प्रतियोगिता का भी आयोजन किया गया।

मुख्य अतिथि के रूप में उद्योग मंत्री लखन लाल देवांगन शामिल हुए। इस दौरान गंगा आरती, धूप आरती के साथ धार्मिक माहौल दिखाई दिया। मंत्री देवांगन सहित अन्य अतिथियों ने पाली के ऐतिहासिक मंदिर में पूजा अर्चना की और सभी के सुख समृद्धि की कामना की।

छत्तीसगढ़ प्रमुख समाचार

भाटापारा में नाबालिगों से अवैध शराब कारोबार का भंडाफोड़

भाटापारा। भाटापारा और बलौदाबाजार जिले में पुलिस ने अवैध शराब के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए संगठित गिरोह का भंडाफोड़ किया है। भाटापारा शहर थाना क्षेत्र में पेट्रोलिंग के दौरान पुलिस ने तीन नाबालिगों को 72 पाव देसी मसाला शराब के साथ पकड़ा गया है। शराब की कीमत लगभग 7200 रुपये बताई गई है। परिवहन में इस्तेमाल की जा रही मोटरसाइकिल भी जब्त की गई है। पूछताछ में खुलासा हुआ कि वयस्क आरोपी नाबालिगों को लालच देकर शराब की ढुलाई और बचने का काम करा रहे थे, ताकि कानून से बचा जा सके। इसके बाद दो आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। इसी तरह सिटी कोतवाली क्षेत्र में समाधान सेल हेल्पलाइन से मिली सूचना पर डमरू-मेढ़ रोड में घेराबंदी कर दो लोगों को 40 पाव देसी और अंग्रेजी शराब के साथ पकड़ा गया। करीब 4400 रुपये की शराब और एक स्कूटी जब्त की गई। पुलिस ने दोनों मामलों में आबकारी अधिनियम और किशोर न्याय अधिनियम के तहत प्रकरण दर्ज कर कुल 7 आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया है।

प्रेमी पर पेट्रोल डालकर जिंदा जलाने की कोशिश

कोरबा। जांजगीर-चांपा जिले के कटओथ गांव में एक युवक को जिंदा जलाकर हत्या की कोशिश करने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। गनीमत रही कि युवक किसी तरह अपनी जान बचाने में कामयाब रहा, जिसके बाद उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मामले में जिला अस्पताल की चौकी पुलिस ने अपराध दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी है। जानकारी के मुताबिक, पीड़ित युवक का कोरबा जिले के कनकी का रहने वाला है। उसकी प्रेमिका ने उसे फोन कर अपने गांव कटओथ में मेला देखने के बहाने मिलने के लिए बुलाया था। युवक जब वहां पहुंचा, तो युवती के भाई ने उस पर पेट्रोल डालकर उसे आग के हवाले कर दिया। इस दौरान युवक ने तुरंत तालाब में कूदकर अपनी जान बचाई। गंभीर हालत में युवक को कोरबा जिला मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मामले में जिला अस्पताल की चौकी पुलिस ने युवक से बयान दर्ज किया है और आगे की जांच में जुट गई है। पुलिस ने बताया कि आरोपी युवती का भाई है।

सीआईएसएफ जवान गुलमी वाटरफॉल में डूबा, तलाश जारी

जगदलपुर। जगदलपुर के नगरनार एनएमडीसी कंपनी में तैनात सीआईएसएफ जवान आकाश चौधरी अपने साथियों के साथ ओडिशा सीमा स्थित गुलमी वाटरफॉल पहुंचे, जहां नहाने के दौरान पानी में डूब गए। कोटपाड़ पुलिस और गोताखोरों की टीम रविवार दोपहर से लगातार तलाश कर रही है, लेकिन अब तक जवान का पता नहीं चला, परिजनों को सूचना दे दी गई है। छत्तीसगढ़ और ओडिशा की सीमा पर स्थित गुलमी वाटरफॉल में महाशिवरात्रि के अवसर पर घूमने गए एनएमडीसी कंपनी के सीआईएसएफ के एक जवान के पानी में डूब जाने की खबर है। रविवार दोपहर से जवान की लगातार तलाश की जा रही है, लेकिन अभी तक उसका कोई पता नहीं चल सका है। पुलिस ने इस मामले में साथ गए अन्य जवानों से पूछताछ शुरू कर दी है। नगरनार एनएमडीसी कंपनी में पदस्थ सीआईएसएफ कंपनी के पांच से छह जवान महाशिवरात्रि पर ओडिशा सीमा में स्थित गुलमी वाटरफॉल घूमने गए थे। वहां खाना खाने के बाद 28 वर्षीय जवान आकाश चौधरी नहाने के लिए पानी में उतरा था।

मोहदी जया केमिकल फैक्ट्री में भीषण आग, ईलाके में हड़कंप

राजनांदगांव। जिले के घुमका थाना क्षेत्र अंतर्गत जालबांधा के मोहंदी गांव में स्थित जया केमिकल फैक्ट्री में अचानक भीषण आग लग गई है। कुछ ही मिनटों में आग ने भयंकर रूप ले लिया है और फैक्ट्री परिसर में अफरा-तफरी का माहौल पैदा कर दिया है। घटना की सूचना मिलते ही घुमका थाना पुलिस और फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां मौके पर मौजुद है। दमकल कर्मी आग पर काबू पाने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं। जानकारी के मुताबिक, घटना के बाद प्रशासन ने फैक्ट्री परिसर को तुरंत खाली कराया और आसपास के क्षेत्र को सुरक्षा घेरे में ले लिया है। आग की लपटें इतनी तेज़ हैं कि दूर से भी दिखाई दे रही हैं। धुएं का गुबार आसमान तक फैल गया है, जिससे इलाके में भय का माहौल है। ग्रामीणों और कर्मचारियों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाया गया। घुमका थाना प्रभारी विजय कुमार मिश्रा ने बताया कि आग लगने के स्पष्ट कारणों का पता अभी नहीं चल पाया है। प्रारंभिक जांच में शॉर्ट सर्किट या किसी रासायनिक प्रतिक्रिया की संभावना जताई जा रही है।

इंडस्ट्रियल एरिया में पेंट-पुट्टी फैक्ट्री में लगी भीषण आग

बिलासपुर। जिले के सिरगिट्टी थाना क्षेत्र के तिफरा इंडस्ट्रियल एरिया में स्थित अनव इंडस्ट्री नामक फैक्ट्री में आज अचानक भीषण आग लग गई। फैक्ट्री में वॉल पेंट, पुट्टी और टाइल्स बनाए जाते हैं। आग ने कुछ ही मिनटों में पूरी फैक्ट्री को अपनी चपेट में ले लिया। घटना की सूचना मिलते ही सिरगिट्टी थाना पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची है। दमकल कर्मी आग पर काबू पाने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि आग की लपटें फैक्ट्री के अंदर रखे केमिकल्स, पेंट और पुट्टी के कारण तेजी से भड़क गईं। देखते ही देखते आग ने पूरे परिसर को घेर लिया और धधकने लगी। फैक्ट्री से उठते धुएं का गुबार दूर-दूर तक दिखाई दे रहा था, जिससे आसपास के इलाके में भय और अफराङ्गतफरी का माहौल बन गया। अधिकारियों ने फैक्ट्री परिसर को तुरंत खाली कराया और आसपास के क्षेत्र को सुरक्षा घेरे में ले लिया ताकि किसी भी प्रकार की जनहानि से बचा जा सके। स्थानीय प्रशासन और पुलिस अधिकारी घटना पर लगातार नजर रखे हुए हैं।

मारपीट-लूट मामले में 5 आरोपियों की, एफआईआर की रद्द

बिलासपुर। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने एक अहम फैसले में पुलिस थाना सिरगिट्टी में दर्ज मारपीट और लूट से जुड़ी एफआईआर को निरस्त कर दिया है। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि आरोपों में प्रथम दृष्टया अपराध के आवश्यक तत्व नहीं बनते और कार्रवाई जारी रखना न्याय प्रक्रिया का दुरुपयोग होगा। यह आदेश मुख्य न्यायाधीश रमेश सिन्हा एवं न्यायमूर्ति रविंद्र कुमार अग्रवाल की खंडपीठ ने पारित किया। याचिकाकर्ता सुमन यादव, इंदु चंद्रा, नंद राठौर, मोहम्मद इस्लाम और राहुल जायसवाल के विरुद्ध 7 सितंबर 2024 को अपराध दर्ज किया गया था। शिकायतकर्ता के अनुसार 6 सितंबर की रात ग्रामीण बैंक, तिफरा के पास आरोपियों ने गाली-गलौज, मारपीट कर सोने की चेन छीन ली। इसके आधार पर भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धाराओं 115(2), 296, 3(5) और 304(1) के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया। याचिकाकर्ताओं की ओर से दलील दी गई कि एफआईआर दर्ज करने में करीब 13 घंटे की देरी है, जो संदेह पैदा करती है। घटना के पहले याचिकाकर्ताओं ने 112 नंबर पर सूचना दी थी और अभिव्यक्ति ऐप के माध्यम से भी शिकायत की गई थी। सीसीटीवी फुटेज भी उनके पक्ष में होने का दावा किया गया। याचिकाकर्ताओं ने इसे प्रतिशोध में दर्ज काउंटर ब्लास्ट एफआईआर बताया। वहीं राज्य की ओर से कहा गया कि, एफआईआर में संज्ञेय अपराध बनता है, जांच पूर्ण हो चुकी है और चालान पेश किया जा चुका है। ऐसे में एफआईआर रद्द करने का कोई आधार नहीं है। हाईकोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के पूर्व निर्णयों का हवाला देते हुए कहा कि यदि एफआईआर के आरोपों को पूरी तरह स्वीकार भी कर लिया जाए, तब भी अपराध के आवश्यक तत्व सिद्ध नहीं होते। एफआईआर में देरी, याचिकाकर्ताओं की पूर्व शिकायतें और रिकॉर्ड पर उपलब्ध सामग्री अभियोजन की कहानी पर गंभीर संदेह उत्पन्न करती है। अदालत ने माना कि इस स्थिति में आपराधिक कार्रवाई जारी रखना न्याय का उद्देश्य पूरा नहीं करता, बल्कि प्रक्रिया का दुरुपयोग होगा। हाईकोर्ट ने याचिका स्वीकार करते हुए थाना सिरगिट्टी, जिला बिलासपुर में दर्ज अपराध क्रमांक 624/2024 को सभी पांचों याचिकाकर्ताओं के विरुद्ध पूरी तरह निरस्त कर दिया।

धमतरी के सिविल अस्पताल में रात को न डॉक्टर रहते हैं न स्टाफ, धरने पर बैठे ग्रामीण

■ सड़क दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल व्यक्ति को बोरई सिविल अस्पताल ला गया लेकिन स्वास्थ्य सुविधा नहीं होने के कारण उसकी मौत हो गई.

धमतरी। स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही के कारण जिले में एक व्यक्ति की मौत हो गई। जिसके बाद आक्रोशित ग्रामीण रातभर सिविल अस्पताल के बाहर धरने पर बैठ गए और नारेबाजी करने लगे।

पूरा मामला बोराई क्षेत्र का है। रविवार रात बोरई घुटकेल मार्ग में एक सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्ति बेहोशी की हालत में सड़क पर पड़ा हुआ था। मामले की सूचना मिलते ही बोराई पुलिस और ग्रामीण मौके पर पहुंचे और घायल को बोराई सिविल अस्पताल लेकर गए। लेकिन अस्पताल में आपातकालीन स्वास्थ्य सेवा ठप मिली। अस्पताल में न डॉक्टर मौजूद था न स्टाफ नर्स और ना ही कोई कर्मचारी। जिसके बाद ग्रामीणों ने संबंधित अधिकारियों को फोन पर सूचना दी लेकिन घायल को इलाज नहीं मिला और उसने दम तोड़ दिया।

घटना के बाद बोरई क्षेत्र के ग्रामीण आक्रोशित हो गए। अस्पताल के मुख्य द्वार पर वे धरने पर बैठ गए और जमकर विरोध प्रदर्शन करने लगे। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि यदि घायल को समय पर इलाज मिल जाता तो उसकी जान बच सकती थी।

ग्रामीणों का आरोप है कि क्षेत्र में स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी लंबे समय से बनी हुई है, कई बार ज्ञापन और आंदोलन के बावजूद व्यवस्था में सुधार नहीं हुआ। ग्रामीणों का कहना है कि जब तक अस्पताल में 24 घंटे डॉक्टरों की तैनाती और जवाबदेही तय नहीं की जाती, आंदोलन जारी रहेगा।

ग्रामीणों के हंगामे के बाद ईटीवी भारत संवाददाता ने धमतरी कलेक्टर अबिनाश मिश्रा से फोन पर बात की और मामले की जानकारी दी। जिस पर कलेक्टर ने कहा कि जो भी दोषी पाए जाएंगे उनपर कार्रवाई की जाएगी।

प्रधानमंत्री मोदी की एक और गारंटी हुई पूरी

महिला स्व सहायता समूहों ने शुरू किया रेडी-टू-ईट का उत्पादन

रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य में कुपोषण दूर करने और महिला सशक्तिकरण के लिए रेडी-टू-ईट फूड निर्माण का काम महिला स्व-सहायता समूहों को सौंपते हुए 6 जिलों में पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया है। इस पहल के तहत रायगढ़, बस्तर, दंतेवाड़ा, बलौदाबाजार, कोरबा, और सूरजपुर जिलों में आंगनबाड़ियों के लिए पौष्टिक आहार निर्माण का कार्य महिला समूहों को मिला है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि राज्य सरकार ने आंगनबाड़ी केंद्रों के लिए पूरक पोषण आहार (रेडी टू ईट) के निर्माण और वितरण का कार्य महिला स्वसहायता समूहों को सौंपने का फैसला किया। राज्य के 6 जिले के 42 महिला स्व-सहायता समूहों को रेडी टू ईट के निर्माण और वितरण का कार्य सौंपा गया है।

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में महिला सशक्तिकरण और कुपोषण मुक्ति के इस मिशन को प्रथम चरण में प्रदेश के 6 जिलों - बस्तर, दंतेवाड़ा, बलौदाबाजार, कोरबा, रायगढ़ एवं सूरजपुर में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में लागू किया जा रहा है। वहीं रायगढ़ प्रदेश का पहला जिला बन गया है, जहां महिला समूहों ने 'रेडी-टू-ईट' उत्पादन प्रारंभ किया है। यह पहल महिलाओं की आर्थिक समृद्धि और बच्चों के स्वास्थ्यकृदोनों को नई दिशा प्रदान करेगी। महिला एवं बाल विकास विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार कोरबा-10 स्व-सहायता समूह को रेडी-टू-ईट निमाण का कार्य सौंपा जा चुका है। इसी प्रकार रायगढ़-10 स्व-सहायता समूह, सूरजपुर और बलौदाबाजार-भाठापारा जिला में 7-7 स्व- सहायता समूह को, बस्तर जिले में 6 स्व-सहायता समूह और दंतेवाड़ा में 2 महिला स्व-सहायता समूह को रेडी-टू-ईट निमाण का कार्य सौंपा जा चुका है। न स्व-सहायता समूहों के द्वारा आंगनबाड़ी केंद्रों के लिए पूरक पोषण आहार का निर्माण और वितरण का कार्य किया जा रहा है। महिला एवं बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े ने कहा कि इन समूहों की बहनें अब आंगनबाड़ी के बच्चों को पौष्टिक आहार उपलब्ध कराने के साथ-साथ इस कार्य से अपनी आमदनी भी बढ़ाएंगी, जिससे वे आर्थिक रूप से सशक्त बनेंगी। यह योजना महिलाओं को स्व-रोजगार के साथ-साथ सामाजिक और आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में भी एक बड़ा कदम है।

प्रख्यात कलाकार अरुण गोविल ने दी सुनो श्री राम कहानी की भावपूर्ण प्रस्तुति

■ आस्था, संस्कृति और रामकथा से आलोकित हुआ राजिम कुंभ कल्प 2026

रायपुर । छत्तीसगढ़ के प्रयाग राजिम की पावन धरा पर आयोजित राजिम कुंभ कल्प 2026 में आस्था, संस्कृति और अध्यात्म का अद्भुत संगम देखने को मिला। त्रिवेणी संगम के पावन तट पर आयोजित सांस्कृतिक संध्या में सुप्रसिद्ध कलाकार एवं भगवान श्रीराम की भूमिका से जनमानस में विशेष पहचान रखने वाले श्री अरुण गोविल ने सुनो श्री राम कहानी की भावपूर्ण प्रस्तुति दी, जिससे संपूर्ण परिसर भक्ति और श्रद्धा के दिव्य वातावरण से ओतप्रोत हो उठा।

इस अवसर पर श्री अरुण गोविल ने मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय से आत्मीय भेंट की तथा राजिम कुंभ कल्प के भव्य आयोजन और उत्कृष्ट व्यवस्थाओं की सराहना की। मुख्यमंत्री श्री साय ने उन्हें स्मृति-चिह्न भेंट कर सम्मानित किया। श्री गोविल ने कहा कि छत्तीसगढ़ की सांस्कृतिक विरासत, जनआस्था और लोगों का आत्मीय स्नेह उनके लिए अविस्मरणीय अनुभव रहा।

मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने कहा कि राजिम कुंभ कल्प केवल धार्मिक आयोजन नहीं, बल्कि हमारी सनातन परंपरा, सांस्कृतिक विरासत और आध्यात्मिक चेतना का जीवंत उत्सव है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार आस्था, संस्कृति और पर्यटन के संरक्षण-संवर्धन के लिए निरंतर प्रतिबद्ध है तथा ऐसे आयोजनों के माध्यम से छत्तीसगढ़ की पहचान राष्ट्रीय स्तर पर और सशक्त हो रही है।

कार्यक्रम में खाद्य मंत्री श्री दयाल दास बघेल, संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री श्री राजेश अग्रवाल, महासमुंद सांसद श्रीमती रूपकुमारी चौधरी, राजिम विधायक श्री रोहित साहू सहित अनेक जनप्रतिनिधियों, संत-महात्माओं एवं श्रद्धालुओं की गरिमामयी उपस्थिति थी।

मुख्यमंत्री साय ने लोकतंत्र सेनानी से की मुलाकात

रायपुर। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय आज बैकुंठपुर निवासी 92 वर्षीय लोकतंत्र सेनानी डॉ. निर्मल घोष के निवास पहुंचे और उनसे सौजन्य भेंट कर उनका कुशलक्षेम जाना। मुख्यमंत्री साय ने डॉ. घोष का शॉल और फल से सम्मानित किया। साथ ही उनके परिजनों से आत्मीय चर्चा की। मुख्यमंत्री साय ने कहा डॉ. घोष का संघर्ष, राष्ट्रप्रेम और जीवटता आज भी हमारे लिए प्रेरणादायी है। इस आयु में भी उनकी स्मरण शक्ति और ज्ञान हम सभी के लिए अनुकरणीय है। लोकतंत्र सेनानी से मिलना और उनका आशीर्वाद प्राप्त करना मेरे लिए सौभाग्य की बात है।

इस अवसर पर डॉ. घोष ने वर्ष 1975 में लगाए गए आपातकाल के दौरान के अपने अनुभव मुख्यमंत्री से साझा किए। उन्होंने बताया कि आपातकाल के समय उन्हें लगभग 19 माह तक विभिन्न जेलों में निरुद्ध रखा गया था। डॉ. घोष ने अपने छात्र जीवन की स्मृतियों को साझा करते हुए बताया कि उन्होंने मिशन स्कूल, माधव राव सप्रे स्कूल तथा नागपुर में अध्ययन किया। वर्ष 1955 में वे आयुर्वेदिक कॉलेज में प्रवेश लिए और सागर विश्वविद्यालय से बीएमएस की डिग्री प्राप्त की। सरकारी सेवा में न जाकर उन्होंने वर्ष 1960 में बैकुंठपुर में निजी चिकित्सालय प्रारंभ किया और लंबे समय तक जनसेवा करते रहे। इस मौके पर कृषि मंत्री राम विचार नेताम, स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल, भइया लाल राजवाड़े सहित अन्य जनप्रतिनिधिगण उपस्थित थे।

मुख्य सचिव ने मंत्रालय महानदी भवन में नवा अंजोर विजन 2047 मॉनिटरिंग पोर्टल की समीक्षा की

रायपुर। मुख्य सचिव श्री विकासशील ने आज मंत्रालय महानदी भवन में आयोजित बैठक में छत्तीसगढ़ नवा अंजोर विजनञ्ज 2047 मॉनिटरिंग पोर्टल की विस्तृत समीक्षा की। बैठक में राज्य शासन के विभिन्न विभागों के सचिव उपस्थित रहे।

मुख्य सचिव ने नवा अंजोर विजनञ्ज 2047 के अंतर्गत निर्धारित इंडिकेटर्स की राज्य स्तरीय समीक्षा करते हुए सभी विभागीय सचिवों को निर्देशित किया कि वे अपने-अपने विभाग से संबंधित योजनाओं एवं कार्यक्रमों की प्रगति, निर्धारित लक्ष्यों की नियतकालिक उपलब्धि तथा अद्यतन जानकारी मॉनिटरिंग पोर्टल में समय-समय पर दर्ज करना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि पोर्टल के माध्यम से योजनाओं की प्रगति की प्रभावी निगरानी एवं मूल्यांकन संभव है, जिससे राज्य के विकास लक्ष्यों की प्राप्ति में गति आएगी।

मुख्य सचिव ने सभी विभागीय सचिवों को अपने विभागीय डैशबोर्ड पर ऑनलाइन प्रगति की नियमित समीक्षा करने तथा निर्धारित इंडिकेटर्स के अनुरूप कार्यों में तेजी लाने के निर्देश भी दिए।बैठक में विजन 2047 के लक्ष्यों की समयबद्ध पूर्ति हेतु समन्वित एवं परिणामोन्मुख कार्यवाही पर विशेष जोर दिया गया।

भाजपा के लिए राजनीति केवल सत्ता का साधन नहीं: पारख

रायपुर। भारतीय जनता पार्टी के मुख्य प्रवक्ता और सांसद संतोष पाण्डेय ने कहा है कि भाजपा में नए पदाधिकारियों के निर्वाचन और नियुक्ति के बाद उन्हें पार्टी की कार्यशैली से अवगत कराना एक अनिवार्य प्रक्रिया है। पार्टी हर स्तर पर पदाधिकारियों को चुस्त-दुरुस्त और प्रशिक्षित करने के लिए निरंतर कार्यशालाएँ आयोजित करती है। इन प्रशिक्षणों का मुख्य उद्देश्य डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी के राष्ट्रवाद के विचारों और पंडित दीनदयाल उपाध्याय के अंत्योदय के संकल्प को बूथ स्तर तक ले जाना है। इन प्रशिक्षण कार्यशालाओं में कार्यकर्ताओं को बताया जाता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक कैसे प्रभावी ढंग से पहुँचाया जाए? श्री पाण्डेय सोमवार को कुशाभाऊ ठाकरे परिसर स्थित भाजपा प्रदेश कार्यालय में पत्रकारों से चर्चा कर रहे थे।

पाण्डेय ने कहा कि भाजपा के लिए राजनीति केवल सत्ता का साधन नहीं, बल्कि विचारधारा के विस्तार और जनसेवा का माध्यम है। मिशन 2028 और चुनावी तैयारियों को लेकर श्री पाण्डेय ने कहा कि भाजपा एक जीवंत संगठन है। हमारे यहाँ एक चुनाव संपन्न होने के अगले ही दिन से आगामी चुनाव की तैयारी शुरू हो जाती है। यह कहना गलत नहीं होगा कि भाजपा केवल युद्ध काल में ही सक्रिय नहीं रहती, बल्कि हम शांति काल में भी युद्ध (संगठनात्मक समर) की पूरी तैयारी रखते हैं। बलरामपुर की घटना के परिप्रेक्ष्य में कांग्रेस के आरोपों पर पलटवार कर श्री पाण्डेय ने कहा कि सरकार और प्रशासन पूरी संवेदनशीलता के साथ इस मामले की जाँच कर रहे हैं।

छत्तीसगढ़/राजधानी

प्रमुख समाचार

भाजपा सरकार में प्रशासनिक आतंकवाद चरम पर: बैज

रायपुर। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने बलरामपुर जिला के कुसमी के मृतक किसान को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि एसडीएम सहित सभी दोषियों पर हत्या का मुकदमा दर्ज करने एवं मृतक किसान के परिवार को एक करोड़ रुपया मुआवजा देने एवं घायलों का उचित ईलाज कराने व घटना की उच्चस्तरीय जांच की मांग की। उन्होंने कहा भाजपा सरकार में प्रशासनिक आतंकवाद चरम पर है।

खनिज तस्करों को भाजपा सरकार का खुला संरक्षण है। प्रशासनिक अधिकारी तस्करों को रोकने के बजाय खनिज तस्करी का विरोध कर रहे लोगों के साथ मारपीट कर रहे है, उन्हें जख्मी कर रहे है, उनकी हत्या कर दी जा रही है। ये घटना सरकार और तस्करों की सांठगांठ का परिणाम है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि भाजपा सरकार बनने के बाद प्रदेश खनिज तस्करों का गढ़ बन गया है। सरकार के संरक्षण में खुलेआम बॉक्ससाईड, आयरन ओर, कोयला, रेत की तस्करी हो रही है। प्रदेश की खनिज संपदा को लूटा जा रहा है जिसका विरोध जनता लगातर कर रही है। दुर्भाग्य की बात है सरकार तस्करों पर कार्यवाही करने के बजाय तस्करी रोकने वाली जनता पर लाठियां भांज रही है, फर्जी मुकदमे दर्ज कर रही है। एक ओर तस्करों के गुर्गे जनता को अवैध हथियार से गोली चलाकर डरा रही है।

शिक्षा स्वास्थ रोजगार की दुर्गति हो गई कर्ज बढ़ा: ठाकुर

रायपुर। कांग्रेस ने प्रदेश में आने वाले बजट में जनता को भ्रमित करने वाला भारी भरकम आधारहीन आंकड़ो की जादूगरी वाला छद्म बजट के अलावा कुछ नही होगा। प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर ने कहा कि वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने पिछली दो बार के बजट को ज्ञान और गति नाम दिया था, लेकिन ज्ञान और गति कही दिखा नही। उल्टा बजट के बाद प्रदेश की विकास

थम गई, शिक्षा, स्वास्थ, रोजगार कानून व्यवस्था की दुर्गति हो गई। स्थिति यह है सरकार को 3500 करोड़ रुपया प्रति महीना कर्ज लेना पड़ रहा है। प्रदेश पर 1 लाख 25 हजार करोड़ से अधिक का कर्ज चढ़ गया। प्रत्येक नागरिक 65 हजार रु के कर्जदार बन गये। बजट में खर्च करने लायक राशि भी नहीं दी गई। प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर ने कहा वित्त मंत्री बताये पिछली बजट में जो घोषणाये हुई थी वो पूरा क्यो नही हुई? 20 हजार शिक्षकों की भर्तियां क्यो नही हुई। मोदी की गारंटी 18 लाख नया पीएम आवास देने की थी उसमें से एक भी आवास स्वीकृत क्यो नही हुई? जिन पीएम आवास का निर्माण कांग्रेस सरकार में शुरू हो चुका था उसकी दूसरी तीसरी क़िस्त क्यो नही दिया गया? किसानों को बोवाई के समय पर्याप्त मात्रा में मंगनुसार खाद क्यो नही दिया गया।

पूरक पोषण आहार यूनिट का शुभारंभ

रायपुर। महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े ने आज सूरजपुर जिले के विकासखंड ओड़गी अंतर्गत ग्राम पालदनौली में पूरक पोषण आहार निर्माण यूनिट का विधिवत शुभारंभ किया। इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार बच्चों, गर्भवती महिलाओं एवं धात्री माताओं के बेहतर स्वास्थ्य और पोषण सुरक्षा के लिए सतत रूप से कार्य कर रही है। यह यूनिट कुपोषण उन्मूलन की दिशा में एक महत्वपूर्ण और परिणामोन्मुखी पहल है। मंत्री राजवाड़े ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के सुपोषित भारत के संकल्प तथा मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ सरकार कुपोषण के विरुद्ध व्यापक अभियान चला रही है। पालदनौली में स्थापित यह यूनिट स्थानीय स्तर पर ताजा, गुणवत्तापूर्ण एवं पोषक आहार की उपलब्धता सुनिश्चित करेगी, जिससे बच्चों और माताओं के स्वास्थ्य में सकारात्मक सुधार आएगा। इस यूनिट में मीठा शक्ति आहार एवं नमकीन पौष्टिक दलिया का निर्माण किया जाएगा। यूनिट का संचालन राधे महिला स्वयं सहायता समूह, पालदनौली द्वारा किया जाएगा। स्थानीय स्तर पर उपलब्ध पौष्टिक सामग्रियों से तैयार आहार आंगनबाड़ी केंद्रों के माध्यम से 6 माह से 6 वर्ष तक के बच्चों, गर्भवती महिलाओं एवं धात्री माताओं को नियमित रूप से उपलब्ध कराया जाएगा।

मिड डे मील योजना बंद होने के कगार पर : वंदना राजपूत

रायपुर। कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता वंदना राजपूत ने भारतीय जनता पार्टी सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि मिड डे मील योजना को बंद करने का भाजपा सरकार षड्यंत्र कर रही है। पिछले 40 दिनों से बच्चों को पोषण आहार नहीं मिल रहा है जिसके कारण बच्चों की स्कूलों में उपस्थिति कम होती जा रही है। मिड डे मील योजना स्कूली बच्चों में कुपोषण, भूख और शिक्षा की कमी जैसे समस्याओं

के समाधान के लिए शुरू किया गया था, जिसमें सरकार को सफलता भी मिल रही थी लेकिन वर्तमान भाजपा के सरकार में स्पष्ट नीति नहीं होने के कारण मध्यान भोजन बंद होने के कगार पर आ गया है। पिछले लगभग 40 दिनों से बच्चों को मध्यान्ह भोजन नहीं मिल पा रहा है। कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता वंदना राजपूत ने कहा कि रसोईया संघ प्रदेश व्यापी हड़ताल पर पिछले लगभग 40 दिनों से है। हड़ताल के दौरान दो महिलाओं की मौत हो जाती है, कई महिलाओं की स्थिति भी चिंताजनक बताई जा रही है। भाजपा, भाषण में महिला सशक्तिकरण पर बड़ी-बड़ी और लुभावने बातें करते हैं लेकिन धरातल पर महिलाएं अपने अधिकार की लड़ाई लड़ते-लड़ते मर रही है। दो महिलाओं की मौत के बाद भी सरकार नींद से नहीं जागी और न जाने कितने मौत का इंतजार कर रही है।

भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाने से घबराई सरकार: साहू

रायपुर। आम आदमी पार्टी, नारायणपुर के जिला अध्यक्ष एवं विधानसभा के पूर्व प्रत्याशी नरेंद्र नाग लंबे समय से क्षेत्र के लोगों के हक और अधिकारों के लिए निरंतर संघर्ष कर रहे हैं। इसके बावजूद प्रशासन द्वारा लगातार उपेक्षा और दमनात्मक रवैया अपनाया जा रहा है। आज पार्टी के कई नेताओं को घर से उठाकर हिरासत में लिया गया है, परंतु उन्हें कहां रखा गया है इसकी स्पष्ट

जानकारी तक नहीं दी जा रही है, जो लोकतांत्रिक मूल्यों के विरुद्ध है। आम आदमी पार्टी के नेता समीर खान ने कहा कि यदि सरकार और प्रशासन अपनी-अपनी जिम्मेदारियों का ईमानदारी से निर्वहन करें तो क्षेत्र की समस्याओं का समाधान संभव है। परंतु बस्तर संभाग में स्थिति इसके विपरीत दिखाई दे रही है। जब भी कोई व्यक्ति या संगठन भ्रष्टाचार और जनहित के मुद्दों को उजागर करता है, तो उसे परेशान किया जाता है और आंदोलनों को दबाने का प्रयास किया जाता है। पार्टी का स्पष्ट मत है कि लोकतंत्र में प्रत्येक नागरिक और राजनीतिक दल को शांतिपूर्ण आंदोलन एवं धरना-प्रदर्शन करने का संवैधानिक अधिकार है। किंतु दक्षिण बस्तर में पुलिस प्रशासन की दमनकारी नीति के कारण लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन हो रहा है।

राजधानी रायपुर में पुलिस आयुक्त प्रणाली की शुरुआत

रायपुर पुलिस कमिश्नरेट में शुरू हुई कोर्ट की प्रोसिडिंग

रायपुर। रायपुर में पुलिस आयुक्त प्रणाली की शुरुआत होने के साथ ही अब दंडाधिकारी शक्तियां कमिश्नरी में निहित हो गई हैं। अब कार्यपालिका दंडाधिकारियों की जगह पुलिस कमिश्नरेट के सहायक आयुक्त अधिकारी कोर्ट की शुरुआत करेंगे। सेंट्रल जोन डीपी उमेश गुप्ता के मार्गदर्शन में आज से कमिश्नरी व्यवस्था में न्यायालयीन सख्ती की दमदार शुरुआत हो गई है। पहले दिन एसीपी कोतवाली और एसीपी सिविल लाइन कोर्ट का प्रथम दिवस रहा।

रायपुर में कमिश्नरी व्यवस्था लागू होने के पश्चात सेंट्रल जोन अंतर्गत न्यायालयीन कार्यवाही का प्रभावी शुभारंभ आज 16 फरवरी से किया गया। इस अवसर पर सहायक पुलिस आयुक्तों द्वारा कार्यपालक दंडाधिकारी की शक्तियों का प्रयोग करते हुए लोक शांति एवं कानून-व्यवस्था बनाए रखने की दिशा में त्वरित एवं सख्त कदम उठाए गए।

इसी क्रम में सहायक पुलिस आयुक्त कोतवाली दीपक मिश्रा द्वारा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 170, 126 एवं 135(3) के अंतर्गत एक प्रकरण में 02 अनावेदकों के विरुद्ध कार्यवाही करते हुए जेल वारंट तैयार किए गए। साथ ही दोनों अनावेदकों को कारण बताओ नोटिस विधिवत तामील कराए गए। इसके अतिरिक्त धारा 126 एवं 135(3) भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के अंतर्गत 05 प्रकरणों में कुल 13 अनावेदकों को कारण बताओ नोटिस एवं समन जारी किए गए, जिन्हें कमिश्नरी प्रणाली के तहत त्वरित रूप से तामील कराया गया।

वहीं सहायक पुलिस आयुक्त सिविल लाइन रमाकांत साहू द्वारा भी लोक शांति भंग होने की आशंका के दृष्टिगत धारा 126 एवं 135(3) भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के तहत 06 अनावेदकों को कारण बताओ नोटिस जारी किए गए। कमिश्नरी प्रणाली के अंतर्गत की गई इस कार्यवाही में सभी समन एवं नोटिस समयबद्ध रूप से तामील कराए गए। कमिश्नरेट व्यवस्था के अंतर्गत यह न्यायालयीन कार्यवाही कानून-व्यवस्था को सुदृढ़ करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है, जिससे यह स्पष्ट संदेश गया है कि सार्वजनिक स्थानों पर उपद्रव, झगड़ा अथवा लोक शांति भंग करने वालों के विरुद्ध अब त्वरित, विधिसम्मत एवं सख्त कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।

परीक्षा को बनाये मन की इच्छा परिणाम इच्छानुसार मिलेंगे : चोपड़ा

रायपुर। जैन संवेदना ट्रस्ट द्वारा बच्चों से बच्चों की बात कार्यशाला का आयोजन श्री आदिश्वर जैन माध्यमिक शाला व वर्धमान इंग्लिश मीडियम स्कूल सदर बाजार में किया गया। ट्रस्ट के अध्यक्ष महेन्द्र कोचर ने बताया कि बच्चों के मन में वार्षिक परीक्षा के डर को दूर करने व परीक्षा में सफलता के लक्ष्य निर्धारण हेतु मोटिवेशनल कार्यशाला आयोजित की जा रही है। आज की कार्यशाला में प्रसिद्ध शिक्षाविद विजय चोपड़ा ने कैसी हो भयमुक्त परीक्षा की तैयारी विषय पर बच्चों को मोटिवेशनल स्पीच देते हुए कहा कि परीक्षा में अच्छे परिणाम के लिए सही प्लानिंग, व्यवस्थित प्रिपरेशन व कड़ा परिश्रम बहुत जरूरी है। चोपड़ा ने अच्छे परिणाम के लिये प्लानिंग , प्रिपरेशन व परिश्रम को विस्तारित करते हुए कहा कि प्रिपरेशन के पूर्व अच्छी प्लानिंग करें। कुल विषयों को परीक्षा के बचे दिन से भाग देकर प्रत्येक विषय के लिये दिन निर्धारित करें। प्रत्येक विषय को तीन श्रेणी में बांट लें। वस्तुनिष्ठ प्रश्न , मन पसंद सरल प्रश्न व कठिन प्रश्न। तैयारी करते समय सरल प्रश्न से आरम्भ कर आगे बढ़ेंगे तो आत्मविश्वास भी बढ़ेगा। कठिन प्रश्नों की तैयारी के लिए प्रातः काल ब्रम्हमुहूर्त का समय बेहतर होगा। इस तरह के प्रयास अच्छे परिणाम देंगे।

परीक्षा की तैयारी को स्वयं की इच्छा बनाएं फिर सफलता सौ प्रतिशत तय है। परीक्षा को बोझ या हव्वा न मानें बल्कि परीक्षा पर हावी होकर तैयारी में जुट जाएं। लगन , मेहनत , अनुशासन व आत्मविश्वास से ही पूर्ण सफलता प्राप्त होती है। इसे मूलमंत्र बनाएं , पूर्ण मनोभावों से किये परिश्रम से ही अच्छे परिणाम सामने आते हैं। अभी परीक्षा में एक पखवाड़े का समय शेष है , एक बात तय है कि सफलता का कोई शॉर्टकट नही होता सो विषयों के अनुसार टाईम टेबल सेट करें , ऊँचा लक्ष्य निर्धारित करें अपनी क्षमता पर विश्वास करें व प्लानिंग से तैयारी आरम्भ कर देवें।

आर.एन.आई.रजि. क्र. CHHHIN/2021/80529, स्वत्वाधिकारी, मुद्रक एवं प्रकाशक- शशांक शर्मा द्वारा मिशन मीडिया प्रा. लि., प्रेस कॉम्प्लेक्स, रजबंधा मैदान, रायपुर (छ.ग.) 492001 से मुद्रित एवं 29/1110, सेवती स्मृति, आजाद चौक, रायपुर (छ.ग.) 492001 से प्रकाशित। संपादक-शशांक शर्मा, मो. 94255-20531.

संक्षिप्त समाचार

राज्यपाल के गोद ग्राम टेमरी के ग्रामीणों ने किया लोकभवन का भ्रमण

रायपुर। राज्यपाल रमेन डेका की पहल पर

लोकभवन की गतिविधियों से जनसामान्य को जोड़ने के उद्देश्य से लोकभवन का भ्रमण कराया जा रहा है। इसी कड़ी में बेमेतरा जिले के ग्राम टेमरी के जनप्रतिनिधियों, स्व सहायता समूहों के सदस्यों और अन्य ग्रामीणों ने सरपंच श्री शिवमूर्ति कोसले और विहान स्व सहायता समूहों की प्रमुख सुश्री गीता बंजारे के साथ आज लोकभवन का भ्रमण किया। उन्हें लोकभवन परिसर स्थित छत्तीसगढ़ मंडपम, उदंती परिसर, कन्हार परिसर, डिस्पेंसरी, सचिवालय की विभिन्न शाखाओं और हरे-भरे उद्यान का भ्रमण कराया गया और इन स्थानों के संबंध में विस्तृत जानकारी भी प्रदान की गई। ग्रामीणों ने परिसर में स्थापित तोप का भी अवलोकन किया यह वर्ष 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान उपयोग में लाया गया था। भ्रमण एवं अवलोकन के बाद ग्रामीणों ने बताया कि लोकभवन में आकर उन्हें बहुत आनंद का अनुभव हो रहा है। उल्लेखनीय है कि इस ग्राम को राज्यपाल श्री डेका ने गोद लिया है।

पंडरी इलाके में पिस्टल लेकर घूम रहा युवक गिरफ्तार

रायपुर। पंडरी थाना इलाके में पुलिस ने

पिस्टल लेकर घूम रहे एक युवक को गिरफ्तार किया है। उसके कब्जे से एक पिस्टल और खाली मैग्जीन बरामद हुआ है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। गिरफ्तार आरोपी का नाम पुरानी बस्ती निवासी नंदू शर्मा बताया जा रहा है। नॉर्थ जोन पुलिस उपायुक्त मयंक गुर्जर ने बताया कि, 15 फरवरी को सूचना मिली थी कि पंडरी इलाके के भिक्षुक केंद्र के पास एक युवक पिस्टल लेकर घूम रहा है। हुलिए के आधार पर युवक को रोका गया। पूछताछ और तलाशी लेने के दौरान पिस्टल, खाली मैगजीन मिली। पुलिस की पूछताछ में नंदू शर्मा ने कचरे के ढेर से पिस्टल मिलने की बात स्वीकार की है। पुलिस अधिकारियों के अनुसार, युवक आदतन अपराधी है। पहले भी हत्या करने और मारपीट केस में जेल जा चुका है। पुलिस अब आरोपी के खिलाफ आगे की कार्रवाई कर रही है।

कुशालपुर चौक के पास गंदगी, दुकान व ठेला संचालकों पर जुर्माना

रायपुर। नगर निगम स्वास्थ्य विभाग की टीम

शिकायत मिलने पर सोमवार की सुबह कुशालपुर चौक पहुंची और संबंधित क्षेत्र का जायजा लेने पर वहां उन्हें गंदगी मिली जिस पर स्वास्थ्य विभाग की टीम ने तत्काल कार्रवाई करते हुए चाय दुकान और फल ठेले वालो से जुर्माने के तौर पर 1700 रुपये वसूल किए। उल्लेखनीय है कि नगर निगम रायपुर के अंतर्गत आने वाले सभी जोन क्षेत्रों में इन दिनों सफाई और अवैध कब्जो को लेकर मिल रही शिकायतों पर तत्काल कार्रवाई की जा रही है। जिससे कि स्थानीय नागरिको को किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना ना करना पड़े। इसी कड़ी में नगर निगम द्वारा आज जोन क्रमांक 5 के अंतर्गत आने वाले कुशालपुर चौक के पास ठेला लगाकर फलो का व्यवसाय करने वालों के साथ अमृततुल्य चाय दुकान द्वारा गंदगी फैलाने की शिकायत मिलने पर निगम का अमला वहां पर पहुंचा और त्वरित कार्रवाई करते हुए अमृततुल्य दुकान के संचालक पर 500 रूपये और 6 फल ठेला संचालकों अण्डा ठेला संचालकों पर 1200 रू. उन्हें भविष्य के लिए कड़ी कार्यवाही की चेतावनी देते हुए कुल 1700 रूपये जुर्माना किया गया एवं प्राप्त जनशिकायत का त्वरित निदान किया गया।

केंदा व्यपवर्तन और सल्का नवागांव उद्वहन सिंचाई योजना के लिए राशि स्वीकृत

रायपुर। छत्तीसगढ़-शासन, जल संसाधन विभाग द्वारा बिलासपुर जिले के विकासखण्ड-कोटा अंतर्गत केंदा व्यपवर्तन योजना की नहरों सुदृढ़ीकरण एवं लाईनिंग कार्य के लिए 3 करोड़ 22 लाख 73 हजार रुपये स्वीकृत किये गये हैं। योजना के प्रस्तावित कार्यों के पूर्ण होने पर योजना का रूपांकित सिचांई क्षेत्र 1093 हेक्टेयर में 663 हेक्टेयर की हो रही कमी की पूर्ति सहित पूर्ण रूपांकित क्षेत्र में सिंचाई सुविधा उपलब्ध होगी। विकासखण्ड-कोटा के अंतर्गत सल्का नवागांव उद्वहन सिंचाई योजना के मुख्य नहर के जीर्णोद्धार एवं माईनर नहरों में सीमेंट कांक्रीट लाईनिंग कार्य हेतु 3 करोड़ 92 लाख 48 हजार रुपये स्वीकृत किये गये हैं। इस योजना के प्रस्तावित कार्यों के पूर्ण होने पर रूपांकित सिंचाई क्षेत्र 1214 हेक्टेयर में 836 हेक्टेयर की हो रही कमी की पूर्ति सहित पूर्ण रूपांकित क्षेत्र में सिंचाई सुविधा उपलब्ध हो जायेगी। सिंचाई सुविधा के कार्यों को पूर्ण कराने मुख्य अभियंता हसदेव कछार जल संसाधन विभाग को प्रशासकीय स्वीकृति दी गई है।

मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े ने 18.38 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का किया भूमिपूजन

■ भटगांव में अधोसंरचना सुदृढ़ीकरण को मिली गति

रायपुर। प्रदेश में संतुलित एवं समावेशी विकास को गति देने की दिशा में राज्य सरकार द्वारा अधोसंरचना सुदृढ़ीकरण के कार्य निरंतर जारी हैं। इसी क्रम में महिला एवं बाल विकास और समाज कल्याण मंत्री तथा भटगांव विधायक श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े ने सूरजपुर जिले के भटगांव विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत लगभग 18.38 करोड़ रुपए की लागत से स्वीकृत विभिन्न विकास कार्यों का विधिवत भूमिपूजन एवं प्रारंभ पूजन किया।

मंत्री श्रीमती राजवाड़े ने ग्राम शिवनंदनपुर स्थित हनुमान मंदिर प्रांगण में अधोसंरचना मद अंतर्गत 3.41 करोड़ रुपए की लागत से विभिन्न निर्माण कार्यों का भूमिपूजन किया। इनमें नकना तालाब घाट निर्माण, फुटपाथ निर्माण, अटल परिसर निर्माण, आर.सी.सी. नाली निर्माण तथा बी.टी. रोड निर्माण कार्य शामिल हैं।

मंत्री श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े एक अन्य भूमिपूजन एवं प्रारंभ पूजन कार्यक्रम में भी सम्मिलित हुईं, जिसमें लोक निर्माण विभाग अंतर्गत 14.97 करोड़ रुपए (लगभग 15 करोड़ रुपए) की लागत से दो महत्वपूर्ण सड़क निर्माण एवं चौड़ीकरण कार्य शामिल हैं। इनमें भटगांव से अनरगवा मार्ग (6.00 किमी) के चौड़ीकरण एवं निर्माण हेतु 878.50 लाख रुपए तथा पकनी से चेन्द्रा मार्ग (5.60 किमी) के चौड़ीकरण एवं निर्माण हेतु 618.63 लाख रुपए की स्वीकृति सम्मिलित है।

इन सड़कों के निर्माण एवं उन्नयन से क्षेत्र में आवागमन की सुविधा में उल्लेखनीय सुधार होगा तथा व्यापारिक, शैक्षणिक एवं सामाजिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा। साथ ही ग्राम स्तर पर आधारभूत सुविधाओं का सुदृढ़ीकरण होगा और स्थानीय नागरिकों को सुव्यवस्थित, सुरक्षित एवं सुगम अधोसंरचना उपलब्ध हो सकेगी।

इस अवसर पर मंत्री श्रीमती राजवाड़े ने कहा कि विष्णु देव साय के नेतृत्व में राज्य सरकार द्वारा ग्रामीण एवं दूरस्थ क्षेत्रों में अधोसंरचना विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जा रही है। शासन का उद्देश्य नागरिकों के जीवन स्तर में गुणात्मक सुधार लाना तथा विकास का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना है। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को सभी कार्यों का गुणवत्तापूर्ण एवं समयबद्ध क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

कार्यक्रम में वन विकास निगम अध्यक्ष श्री रामसेवक पैकरा सहित जनप्रतिनिधिगण, विभागीय अधिकारी एवं बड़ी संख्या में स्थानीय नागरिक उपस्थित रहे।

सरकारी दफ्तरों में कार रेंट पर लगवाने का दिया झांसा

रायपुर। राजधानी रायपुर में सरकारी विभागों में वाहन किराए पर लगाने का झांसा देकर करोड़ों रुपये की धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। एक शातिर दलाल ने करीब 25 से अधिक वाहन मालिकों को झांसे में लेकर उनकी गाड़ियां हड़प लीं और अब उनका कहीं पता नहीं चल रहा है। मामले की गंभीरता को देखते हुए पीड़ितों ने कांग्रेस नेता पंकज शर्मा और बिरगांव महापौर नंदलाल देवांगन के साथ रायपुर पुलिस कमिश्नर कार्यालय पहुंचकर न्याय की गुहार लगाई है।

पीड़ित वाहन मालिकों का आरोप है कि प्रेम साहू, शशिकांत यादव और रोहित सरोज नामक व्यक्तियों ने उनसे संपर्क किया था। उन्होंने दावा किया था कि उनकी गाड़ियां सरकारी विभागों और प्राइवेट कंपनियों में अच्छे किराए पर लगाई जाएंगी। भरोसे में आकर मालिकों ने विधिवत एग्रीमेंट कर अपनी नई गाड़ियां उन्हें सौंप दीं।

शिकायतकर्ताओं के अनुसार, पिछले कई महीनों से उन्हें किराए का भुगतान नहीं मिला है। जब उन्होंने अपनी गाड़ियों की लोकेशन चेक करनी चाही, तो पता चला कि गाड़ियों में लगे जीपीएस सिस्टम को भी बंद या हटा दिया गया है। आरोपी 'आज-कल' का बहाना बनाकर समय टालते रहे और अब गाड़ियां लेकर फरार हैं। पीड़ितों को डर है कि उनकी गाड़ियां कहीं गिरवी रख दी गई हैं या बेच दी गई हैं। सोमवार को बड़ी संख्या में वाहन मालिक कमिश्नर कार्यालय पहुंचे।

आर्थिक सर्वेक्षण पेश करने के साथ 23 से शुरू होगा विस का बजट सत्र

■ 24 को पेश करेंगे वित्त मंत्री बजट

रायपुर। छत्तीसगढ़ विधानसभा का बजट सत्र 23 फरवरी को राज्यपाल के अभिभाषण और राज्य के आर्थिक सर्वेक्षण पेश करने के साथ शुरू होने जा रहा है। सत्र के दूसरे ही दिन, 24 फरवरी को साय सरकार का तीसरा बजट वित्त मंत्री ओपी चौधरी पेश करेंगे। बजट के बाद बुधवार से अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा होगी।

इस बीच वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने पत्रकारों से चर्चा करते हुए बताया कि 24 जनवरी को वे राज्य का बजट पेश करेंगे। यह सरकार का तीसरा बजट होगा, जो नई थीम और नए विजन के साथ प्रस्तुत किया जाएगा। बजट की रणनीति 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य के अनुरूप तैयार की गई है। विकसित छत्तीसगढ़ विजन डॉक्यूमेंट की दिशा में यह महत्वपूर्ण कदम होगा। 2047 के लॉन्ग टर्म प्लान और शॉर्ट टर्म प्लानिंग के तहत बजट में स्पष्ट रोडमैप देखने को मिलेगा।

बजट को लेकर कांग्रेस द्वारा उठाए जा रहे सवालों पर चौधरी ने कहा कि पूर्व में राजीव गांधी योजना के तहत चार किस्तों में राशि दी जाती थी, जबकि भाजपा सरकार हर साल उससे अधिक राशि दे रही है। उन्होंने दावा किया कि कांग्रेस पांच वर्षों में जितनी राशि नहीं दे पाई, उससे अधिक उनकी सरकार दे रही है। हर वर्ष 8000 करोड़ रुपए माता-बहनों के खातों में ट्रांसफर किए जा रहे हैं। विपक्ष केवल आरोप-प्रत्यारोप की राजनीति कर रहा है।

पुराने वाहनों की बिक्री पर 1 प्रतिशत टैक्स हटाने का आश्वासन

रायपुर। अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत, रायपुर द्वारा प्रदेश में पुराने वाहनों की बिक्री पर लगाए गए 1 प्रतिशत अतिरिक्त टैक्स से आम ग्राहकों को हो रही परेशानियों को लेकर यह विषय परिवहन मंत्री केदार कश्यप के संज्ञान में लाया गया था। ग्राहक पंचायत द्वारा अवगत कराया गया कि यह नियम मध्यम एवं निम्न वर्ग के उपभोक्ताओं पर अनावश्यक आर्थिक बोझ डाल रहा है तथा पुराने वाहनों की खरीद-बिक्री को प्रभावित कर रहा है। इस पर संज्ञान लेते हुए परिवहन मंत्री ने उक्त नियम को समाप्त करने का आश्वासन दिया है। अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत रायपुर के जिला अध्यक्ष आशीष अग्रवाल ने बताया कि अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत का मानना है कि ग्राहक किसी भी राष्ट्र की अर्थव्यवस्था की रीढ़ होता है।

स्व. राजो देवी साहू स्मृति बैडमिंटन प्रतियोगिता का फाइनल आज

रायपुर। चैलेंज कप बैडमिंटन प्रतियोगिता डाईट शंकर नगर रायपुर में खेली जा रही है। उद्घाटन कार्यक्रम में उप प्राचार्य श्रीमती अर्चना पाठक एवं ज्ञान सिंह साहू के मुख्य अतिथि में तथा डॉ सुशील जैन एवं ज्योति के विशेष आथित्य में संपन्न हुआ। इस प्रतियोगिता में डाइट की व्खायाता नीरजा सातपुते ने भी भाग लिया है।

उल्लेखनीय है कि प्रतियोगिता डाईट, सीटीई, एनआईओएस, एससीईआरटी एवं अवंती विहार के खिलाड़ियों के बीच खेली जा रही है। अब तक महिला वर्ग में कु. वैष्णवी सामी एवं श्रीमती अन्नपूर्णा वर्मा के बीच फाइनल खेली जाएगी तथा पुरुष वर्ग में श्री धर्मवीर वर्मा एवं श्री ऋषभ शर्मा के बीच फाइनल खेला जाएगा तथा महिला वर्ग एवं पुरुष वर्ग के युगल मैच के सेमीफाइनल आज खेले जाएंगे। पुरुषों में विवेक एवं प्रवीण की जोड़ी सेमीफाइनल पहुंच चुकी है। इस प्रतियोगिता का फाइनल 17 तारीख को होगा, जिसके मुख्य अतिथि जुगल किशोर अग्रवाल एवं अध्यक्षता श्री ज्ञान सिंह साहू विशेष अतिथि के रूप में श्री तोरण लाल साहू ,श्री बी एल. देवांगन उपसंचालक लोक शिक्षण छत्तीसगढ़,श्री प्रहलाद दमाहे उप- संपादक स्वदेश ज्योति होंगे। इस प्रतियोगिता के संयोजक प्राचार्य युगल किशोर साहू एवं आयोजक छबिराम ज्ञान सिंह साहू ,भारतीय शिक्षा बोर्ड के राज्य प्रभारी एवं रिटायर्ड असिस्टेंट प्रोफेसर डाइट है जिनके मार्गदर्शन में 9 महिलाओं एवं 25 पुरुषों ने भाग लिया है। 17 फरवरी को फाइनल के पश्चात पुरस्कार वितरण किया जाएगा। एवं सभी खिलाडियों को प्रमाण पत्र एवं प्रोत्साहन के अलावा आयोजको की ओर से खिलाडिओ को नि:शुल्क शर्ट भी दी जा रही है।

छत्तीसगढ़ में अब बार-क्लब खोलना हुआ आसान

सरकार ने लाइसेंस फीस और बैंक गारंटी में की भारी कटौती, एयरपोर्ट पर भी मिलेगी शराब

रायपुर। छत्तीसगढ़ की विष्णुदेव साय सरकार ने प्रदेश की नई आबकारी नीति में बड़े बदलाव करते हुए होटल, रेस्टोरेंट और क्लब संचालकों को बड़ी राहत दी है। सरकार ने नए व्यापार को बढ़ावा देने के उद्देश्य से लाइसेंस फीस में भारी कमी की है, जिससे अब राज्य में बार खोलना पहले के मुकाबले काफी सस्ता हो जाएगा।

इन बड़े बदलावों पर एक नजर-

लाइसेंस फीस में 6 लाख की बचत: राज्य सरकार ने उन शहरों के लिए बड़ा फैसला लिया है जिनकी आबादी 7 लाख से अधिक है। यहां एफएल-2 (क) और एफएल-3 (क) श्रेणी के बार के लिए लाइसेंस शुल्क को 24 लाख रुपये से घटाकर 18 लाख रुपये कर दिया गया है।

बैंक गारंटी में भी राहत: केवल लाइसेंस फीस ही नहीं, बल्कि सरकार ने अनिवार्य बैंक गारंटी की राशि को भी कम कर दिया है। इससे नए कारोबारियों पर शुरुआती वित्तीय बोझ कम होगा और इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा।

3-स्टार होटलों को फायदा: क्लबों के साथ-साथ थ्री-स्टार और उससे ऊपर की श्रेणी वाले होटलों की लाइसेंस फीस में भी रियायत दी गई है।

इस नई नीति का सबसे चर्चित हिस्सा राजधानी रायपुर का स्वामी विवेकानंद हवाई अड्डा है। साल 2026-27 के लिए एक पायलट प्रोजेक्ट के तहत एयरपोर्ट पर बार खोलने की अनुमति दे दी गई है। एयरपोर्ट अथॉरिटी से अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) मिलने के बाद अब यात्री वहां के रेस्टोरेंट्स में विदेशी शराब का आनंद ले सकेंगे। माना जा रहा है कि इस फैसले से पर्यटकों और यात्रियों के अनुभव में सुधार होगा।

भले ही फीस और नियमों में ढील दी गई है, लेकिन बार संचालन के समय को लेकर सख्ती बरकरार है। पूरे प्रदेश में बार पहले की तरह ही सुबह 11 बजे से रात 11 बजे तक ही संचालित किए जा सकेंगे। समय-सीमा में किसी भी तरह का विस्तार नहीं किया गया है। सरकार के इस कदम को व्यापारिक दृष्टिकोण से 'Ease of Doing Business' को बढ़ावा देने वाला माना जा रहा है, जिससे पर्यटन और आबकारी राजस्व दोनों में बढ़ोतरी की उम्मीद है।

तंजानिया में गोल्ड माइन्स के नाम पर ठगी का मास्टरमाइंड गिरफ्तार

रायपुर। तंजानिया के गोल्ड माइन्स में निवेश के नाम पर राजधानी के कारोबारियों से करोड़ों की ठगी करने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। लगभग 2 करोड़ की ठगी करने वाले मुख्य आरोपी यश राजेश शाह को रायपुर पुलिस ने मुंबई एयरपोर्ट पर धर दबोचा है।

जानकारी के अनुसार, आरोपी यश शाह की जमानत अर्जी कोर्ट से खारिज हो चुकी थी, जिसके बाद वह देश छोड़कर फरार होने की योजना बना रहा था। वह मुंबई एयरपोर्ट से वियतनाम के लिए उड़ान भरने वाला था, लेकिन रायपुर पुलिस की मुस्तैदी और लुकआउट नोटिस के कारण उसे रंगे हाथों पकड़ लिया गया।

ऐसे बिछाया था ठगी का जाल

यश शाह ने रायपुर के कारोबारी समर्थ बरडिया को ऑनलाइन संपर्क किया था और गोल्ड माइन में 50 प्रतिशत हिस्सेदारी का लालच दिया।

पीड़ित समर्थ बरडिया और उनके जीजा को तंजानिया बुलाया। वहां उसने अब्दुल्लाह किलियावापे न्युजे नामक व्यक्ति को अपना पार्टनर बताया और कारोबारियों को एक खदान दिखाकर भरोसा जीता।

हिस्सेदारी का लालच देकर आरोपियों ने 2 करोड़ रुपये से अधिक की रकम डकार ली।

मामले का दूसरा अहम आरोपी अब्दुल्लाह किलियावापे न्युजे फिलहाल फरार बताया जा रहा है, जिसकी तलाश जारी है।

रायपुर के सिविल लाइन थाना पुलिस ने समर्थ बरडिया की शिकायत पर यश शाह और उसके साथियों के खिलाफ धोखाधड़ी (धारा 420) और साजिश रचने (120बी) सहित भारतीय न्याय संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया था।

पुलिस अब आरोपी को रायपुर लाकर रिमांड पर लेगी, जिससे इस अंतरराष्ट्रीय गिरोह के अन्य सदस्यों और ठगी की गई रकम की रिकवरी के बारे में पूछताछ की जा सके।

एसजीपीसी के प्रधान हरजिंदर सिंह धामी करेंगे रावांभाठा गुरुद्वारे का उद्घाटन

रायपुर। सिक्ख पंथ की सर्वोच्च संस्था के अध्यक्ष, एसजीपीसी के प्रधान हरजिंदर सिंह धामी का एक दिवसीय प्रवास छत्तीसगढ़ में मंगलवार, 17 फरवरी को होने जा रहा है। वे विमान द्वारा सुबह अमृतसर से रायपुर पहुंचेंगे। उनके भव्य स्वागत की तैयारी की जा रही है। स्वागत उपरांत वे होटल बेबीलॉन इंटरनेशनल में छत्तीसगढ़ की सभी गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी, सामाजिक संस्थानों के पदाधिकारियों के साथ छत्तीसगढ़ में चल रही सिक्ख समाज की गतिविधियों पर चर्चा करेंगे। इसके बाद वे बिलासपुर रोड रांवाभाठा में निर्मित भव्य ऐतिहासिक गुरुद्वारे का उद्घाटन करेंगे। शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी अमृतसर के मार्गदर्शन में भव्य गुरमत संगीत विद्यालय का भी यहां शुभारंभ होगा। इस गुरुद्वारे की साज-सज्जा आधुनिक और आकर्षक शैली में की गई है, जिसकी भव्यता देखते ही बन रही है।

इस पूरे आयोजन को मूर्त रूप प्रदान कर रहे समाजसेवी जगजीत सिंघ खनूजा, जी.एस. भाम्बरा व रावांभाठा के नवीनीकृत गुरुद्वारे के प्रभारी अजीत सिंग ने सर्व सिक्ख समाज से अपील की है कि पंथ की सर्वोच्च संस्था के अध्यक्ष श्री धामी के भव्य स्वागत के लिए सभी माना विमानतल पहुंचकर और गुरुद्वारे के उद्घाटन समारोह में अधिकाधिक संख्या में सम्मिलित होकर गुरु घर की खुशियां प्राप्त करें। इस कार्यक्रम में दरबार साहिब के रागी जत्थे सिक्ख गुरु गाथा का गुणगान कर गुरु नाम लेवा संगत को निहाल करेंगे। उद्घाटन के पश्चात् श्री धामी, अमरजीत सिंग छाबड़ा के विशेष आग्रह पर अपने पूरे काफिले के साथ राज्य अल्पसंख्यक आयोग के कार्यालय भी पहुंचेंगे। जहां भी वे सिक्ख पंथ की गतिविधियों एवं विकासपरक योजनाओं पर चर्चा कर अपनी राय व मार्गदर्शन देंगे। इस पूरे कार्यक्रम में सिक्ख फोरम के अध्यक्ष बलदेव सिंग भाटिया, राज्य अल्पसंख्यक आयोग अध्यक्ष अमरजीत सिंग छाबड़ा समेत सिक्ख समाज के गणमान्यजन व सभी गुरुद्वारों के प्रधान प्रमुख रूप से सम्मिलित होंगे।

भाठागांव में गुरुद्वारा गुरु नानक साहिब के नवीनीकरण के बाद मंगलवार को उद्घाटन होगा। संगत के सहयोग से इस गुरुद्वारे का जीर्णोद्धार कराया गया है। नवीनीकरण के बाद मंगलवार की सुबह 10 बजे श्रीगुरुग्रंथ साहिब का पहला प्रकाश होगा। दरअसल यह गुरुद्वारा 2004 में बनाया गया था। जीर्ण-शीर्ण अवस्था में होने के कारण इसका रिनोवेशन कराया गया। इसके तहत दरबार हॉल में नई पालकी साहिब बनवाई गई है। इंटीरियर के काम कराए गए हैं। साथ ही बेल्जियम से मंगाई कालीन लगाई गई है, जिसकी कीमत करीब 4 लाख रुपए है। गुरुद्वारे के भवन में भी रंग-रोगन किया गया है। बाहर पंजाब से मंगाया गया स्टील का खंडा स्थापित किया गया। वहीं 100 फीट लंबा व 40 फीट चौड़ा लंगर भवन भी तैयार किया गया है। गुरुद्वारे के इंचार्ज अजीत सिंह ने बताया कि दोपहर 3 बजे तक गुरमत समागम में श्रीदरबार साहिब के हजूरी रागी भाई स्वरूप सिंह कीर्तन करेंगे, जबकि भाई गुरसेवक जीत सिंह का ढाढ़ी जत्था गुरु इतिहास का वाचन करेगा।

गुरुद्वारे के उद्घाटन के बाद वहां गुरमत संगीत विद्यालय शुरू किया जाएगा। यहां बच्चों को निःशुल्क संगीत सिखाया जाएगा। हर समाज के बच्चे इसमें शामिल हो सकेंगे। इसके अलावा वहां जरूरतमंदों के लिए 8 कमरों की सराय बनाई गई है। जहां रात्रि विश्राम की व्यवस्था रहेगी।

भारतीय अर्थव्यवस्था को लेकर केंद्र पर भूपेश बघेल का हमला

■ कहा- 2014 से पहले जितना कर्ज, अब उससे 3 गुना ज्यादा

रायपुर। भारत की मौजूदा अर्थव्यवस्था को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने हमलावर होते हुए कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के कार्यकाल में भारत कितना कर्जा था और मौजूदा समय में यह कितना है, इसकी तुलना कर लें। दावा करते हुए कहा कि देश पर 2014 से पहले जितना कर्ज था, वह अब तीन गुना ज्यादा है। भाजपा को पहले अर्थव्यवस्था कैसी है वह देख लेनी चाहिए। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि वह केवल अपने मित्रों के लिए व्यवस्था कर रहे हैं।

डिप्टी सीएम साव के कांग्रेस जिला अध्यक्षों की परफॉर्मेंस को लेकर दिए बयान पर पूर्व सीएम बघेल ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि अरुण साव अपने प्रदेश अध्यक्ष के रूप में जो-जो वादे किए थे सभी की समीक्षा करें। पहले देख लें कि वह कितने वादों पर खरा उतरे और क्या नहीं कर पाए। कांग्रेस को सीख देने की कोशिश न करें।

पंजाब कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी भूपेश बघेल आज चंडीगढ़ पहुंचेंगे। उन्होंने अपने दौरे को लेकर जानकारी दी कि चंडीगढ़ में प्रदेश कांग्रेस कमेटी की बैठक है, जिसमें वह शामिल होंगे। मनरेगा बचाओ महासंग्राम, अमेरिका टैरिफ जैसे मुद्दों पर सरकार के खिलाफ लड़ाई शुरू की जाएगी।

एआई समिट के नीतिगत-समूहगत वैश्विक मायने

कमलेश पांडे

एआई इम्पैक्ट समिट 2026 भारत सरकार द्वारा नई दिल्ली में 16-20 फरवरी 2026 को आयोजित एक प्रमुख वैश्विक आयोजन है, जो कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) के जिम्मेदार और समावेशी विकास पर केंद्रित है। यह समिट ग्लोबल साउथ के लिए पहला बड़ा एआई शिखर सम्मेलन है, जो 100+ देशों से 35,000+ प्रतिनिधियों को एकजुट कर रहा है। देखा जाए तो यह समिट इंडिया एआई मिशन के तहत आयोजित हो रहा है, जिसमें राष्ट्राध्यक्ष, मंत्री, उद्योग नेता, शोधकर्ता और सिविल सोसाइटी शामिल होंगे। वास्तव में यह आयोजन यूके एआई सेफ्टी समिट, सिओल एआई समिट जैसे पूर्व आयोजनों की निरंतरता में वैश्विक एआई सहयोग को मजबूत करेगा। जिसका मुख्य थीम पीपुल, प्लैनेट, प्रोग्रेस है। ये नीतियों को व्यावहारिक प्रभाव में बदलने पर जोर देता है। इस समिट का वैश्विक महत्व यह है कि एआई इम्पैक्ट समिट एआई के लोकतंत्रीकरण पर फोकस करता है, विशेष रूप से वैश्विक दक्षिण के देशों के लिए संसाधनों को सुलभ बनाने हेतु सक्रिय किया गया है। वहीं, भारत की पूरक नवाचार क्षमता ग्लोबल एआई नेतृत्व स्थापित करने में मदद करेगी, साथ ही जिम्मेदार एआई शासन के मानकों को आकार देगी। इसमें 16 देशों के राष्ट्राध्यक्षों की भागीदारी आर्थिक कूटनीति और विकासशील राष्ट्रों की आवाज को मजबूत करेगी। इसकी प्रमुख पहलें इस प्रकार हैं जो डेमोक्रेटाइजिंग एआई रिसोर्सेज वर्किंग ग्रुप (भारत, मिस्र, केन्या सह-अध्यक्ष) सार्वजनिक एआई संसाधनों को किफायती बनाने पर काम कर रहा है। जहां तक इसके वैश्विक प्रभाव की बात है तो इससे जुड़ीं चुनौतियां समावेशी एआई नवाचारों को प्रोत्साहित करेंगी। लिहाजा यह समिट एआई को आर्थिक-रणनीतिक शक्ति के रूप में स्थापित कर वैश्विक विभाजन को पाटेगा। दरअसल, एआई इम्पैक्ट समिट 2026 का मुख्य एजेंडा एआई को जिम्मेदार, समावेशी और प्रभावी बनाने पर केंद्रित है, जो तीन सूत्रों—लोग, ग्रह, और प्रगति —पर आधारित है। यह एजेंडा एक्शन से इंपैक्ट की ओर बढ़ने पर जोर देता है, जिसमें नीतियों को व्यावहारिक बदलावों में बदलना शामिल है। इस आयोजन का मुख्य सूत्र ,निम्नवत है- पहला, लोग यानी एआई का समावेशी विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक न्याय में उपयोग। दूसरा, ग्रह यानी पर्यावरण संरक्षण, जलवायु परिवर्तन से लड़ाई और सतत विकास। और तीसरा, प्रगति यानी आर्थिक विकास, उत्पादकता वृद्धि और नवाचार को बढ़ावा। इसके दृष्टिगत ही प्रमुख सत्र और चक्र को निर्धारित किया गया है। एआई इम्पैक्ट समिट को सात चक्रों%(फोकस एरियाज) में बांटा गया है, जो कार्यशालाओं, पैनल चर्चाओं और उच्च-स्तरीय बैठकों के रूप में आयोजित होंगे। पहला, डेमोक्रेटाइजिंग एआई रिसोर्सेज यानी सार्वजनिक एआई संसाधनों को किफायती बनाना (भारत, मिस्र, केन्या सह-अध्यक्ष)। दूसरा, वैश्विक प्रभाव चुनौतियां यानी समावेशी एआई नवाचारों को प्रोत्साहन। तीसरा, अन्य सत्र जैसे वैज्ञानिक शोध में एआई (डॉ. अर्चना शर्मा जैसे विशेषज्ञ), उद्योग नेताओं के साथ नीति चर्चा, और टेक दिग्गजों की भागीदारी। जहां तक इसके अपेक्षित परिणाम की बात है तो ये सत्र 100+ देशों के नेताओं, वैज्ञानिकों और उद्योगपतियों को जोड़कर वैश्विक एआई शासन के मानक स्थापित करेंगे। यह समिट 16-20 फरवरी को नई दिल्ली में चल रहा है, जो ग्लोबल साउथ की प्राथमिकताओं को मजबूत करेगा। दरअसल एआई इम्पैक्ट समिट 2026 से अपेक्षित प्रमुख परिणाम जिम्मेदार एआई के वैश्विक मानकों को मजबूत करना और ग्लोबल साउथ के लिए समावेशी विकास को बढ़ावा देना हैं।

सेवा तीर्थ से उपजते सवालों के जवाब कब तक मिलेंगे?

कमलेश पांडे

कहते हैं कि शब्द ब्रह्म है और हर शब्द अपने मंत्रमय भावमय अस्तित्व से आकार ग्रहण करते हुए देर-सबेर साकार होता है। इस दृष्टिकोण से दूरद्रष्टा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नाम परिवर्तन द्वारा जनमानस की सोच में बदलाव की जो मुहिम चलाई है, वह सुसंस्कृत भारत के निमित्त नाम/विचार परिवर्तन यात्रा अनवरत रूप से जारी है। इसी कड़ी में हमारा गवर्नमेंट ऑफ भारत अपने लोककल्याण मार्ग (सेवन रेस कोर्स) व कर्तव्य पथ (राजपथ) होते हुए अब सेवा तीर्थ (पीएमओ) तक के अपने वैचारिक सफर को पूरा कर चुका है।

पहले नया संसद भवन और अब कर्तव्य भवन 1 और 2 इसकी बानगी भर हैं जबकि अन्य बदलाव भी प्रक्रियाधीन हैं और नाम-भवन परिवर्तन द्वारा, भाव परिवर्तन यात्रा गतिमान है। वास्तव में, यह नया बदलाव नया भारत यानी गवर्नमेंट ऑफ भारत (गवर्नमेंट ऑफ इंडिया) के मार्फ़त लिए हुए फैसलों में सिर्फ मिल का पत्थर भर है, और विगत लगभग एक दशक में हमलोग ऐसे ही कुछेक महत्वपूर्ण मिल के पत्थरों को पार करते हुए इस अहम मुकाम तक चुके हैं।

देखा जाए तो अमृत भारत और विकसित भारत के दृष्टिगत ये नाम, विचार व भवन बदलाव यात्रा गतिमान है, जिसके नीति आयोग (योजना आयोग) जैसे अहम सियासी व प्रशासनिक मायने हैं। लिहाजा, विपक्ष इस आधुनातन सोच-समझ की आलोचना अपने तरीके से कर रहा है, लेकिन यहां हम मीडिया यानी चौथे स्तम्भ के नाते इस अहम निर्णय से जुड़े जनपक्ष को लेकर कुछ सवाल उठाएंगे और जवाब भी मिले, इसकी प्रतीक्षा करेंगे।

यह ठीक है कि प्रधानमंत्री कार्यालय का पता औपनिवेशिक दौर की साउथ ब्लॉक इमारत से बदलकर अब सेवा तीर्थ परिसर हो गया है। प्रधानमंत्री ने अपने नए ऑफिस से महिलाओं, किसानों और युवाओं से जुड़े कई अहम फैसले भी लिए। इससे मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि, सेवा परमो धर्म की भावना ही नए सेवा तीर्थ परिसर की आत्मा है। यह केवल भवन नहीं, बल्कि सेवा और समर्पण के संकल्प का प्रतीक है। आज का संकल्प और परिश्रम ही आने वाली पीढ़ियों का भविष्य तय करेगा। चूंकि शासन का केंद्र अब नागरिक हैं। इस भवन में

लिया गया हर निर्णय 140 करोड़ देशवासियों के जीवन को बेहतर बनाने के उद्देश्य से होना चाहिए।

इसी दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दो टूक कहा कि आजादी के बाद नार्थ ब्लॉक और साउथ ब्लॉक जैसी इमारतों से देश के लिए नीतियां बनीं, कई निर्णय हुए। यह भी सच है कि ये पुरानी इमारतें ब्रिटिश हुकूमत का, गुलामी का प्रतीक थी। गुलामी की इस मानसिकता से बाहर निकलना जरूरी था। साल 2014 में देश ने यह तय किया कि गुलामी की मानसिकता और नहीं चलेगी। हमारे इन फैसलों के पीछे हमारी सेवा भावना है।

यदि उनके नजरिए से देखा जाए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेवा तीर्थ जैसे लोकतांत्रिक तीर्थ के उद्घाटन के मौके पर यह कहकर बौद्धिक हलचल मचा दी है कि पुरानी इमारतें ब्रिटिश हुकूमत का, गुलामी का प्रतीक थी। गुलामी की इस मानसिकता से बाहर निकलना जरूरी था। साल 2014 में देश ने यह तय किया कि गुलामी की मानसिकता और नहीं चलेगी। हमारे इन फैसलों के पीछे हमारी सेवा भावना है।

ऐसे में यह सवाल उठना लाजिमी है कि आखिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुलामी के किन-किन प्रतीकों को बदलेंगे और कब तक बदलेंगे? और क्या इसकी कोई समय सारणी तय हुई है या फिर इनमें भी वह ईसाइयों द्वारा निर्मित भवन को पहले और मुस्लिम शासकों द्वारा निर्मित भवन को बाद में बदलेंगे? क्योंकि बहुमत प्राप्ति के दृष्टिगत सियासत भी जरूरी है और गुलामी के प्रतीकों से मुक्ति भी! क्योंकि भारत तो इस्लामिक आक्रमणकारियों और ईसाई कारोबारियों दोनों का 800 वर्षों तक गुलाम रहा है।

वहीं खास बात तो यह कि देश को गुलाम बनाए रखने का बौद्धिक हथियार यानी फूट डालो और शासन करो (डिवाइड एंड रूल) जैसे गुलामी मंत्र जाति आधारित आरक्षण और धर्म आधारित अल्पसंख्यक वाले सोच को प्रधानमंत्री कब तक बदलेंगे? या फिर हिंदुओं व मुस्लिमों में कभी फूट डालने और कभी एक जुट करने के ये हथियार अकसर नया धार पाते रहेंगे?

साथ ही, मुगलिया दस्ता के प्रतीक और मुगल बादशाह शाहजहां द्वारा निर्मित उस लालकिला परिसर को कब तक बदलेंगे, जहां पर स्वतंत्रता दिवस पर प्रधानमंत्री हर वर्ष राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा फ़हराते हैं और राष्ट्रीय हित व जनहित से जुड़े अपने महत्वपूर्ण सम्बोधन देते आये हैं। जी हां, देशवासी पूरी राम कथा जानना चाहते हैं! क्योंकि कुछ तो उनके शागिर्दों के सियासी हथियार तक बन चुके हैं।

यह ठीक है कि राम मंदिर निर्माण (कथित बाबरी मस्जिद के भग्नावशेष पर) करके और नया संसद भवन व कर्तव्य भवन 1 और 2 (ब्रिटिश शासकों द्वारा निर्मित भवनों के बगल में या उनकी जगह पर) का निर्माण करके, जिसमें सेवा तीर्थ भी शामिल है, प्रधानमंत्री ने यादगार शुरुआत कर दी है, लेकिन आगे कहां तक, कब तक यह प्रक्रिया जारी रहेगी, लोगों में जानने की उत्सुकता है, क्योंकि गुलामी की दासता के ढेर से प्रतीक अब भी हमारे शासन प्रतिष्ठान और जनमानस को मुंह चिढ़ाते प्रतीत हो रहे हैं, जिन्हें अविलंब बदला जाना चाहिए।

बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को पहले अपने नए पीएम ऑफिस %सेवा तीर्थ% की शुरुआत की। फिर शाम को कर्तव्य भवन 1 और 2 का लोकार्पण किया। इस मौके पर प्रधानमंत्री के साथ केंद्रीय मंत्रियों मनोहर लाल खट्टर और डॉ. जितेंद्र सिंह, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल, प्रधान सचिव पी. के. मिश्रा और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों की उपस्थिति भी रही, जिनकी अहम मौजूदगी में प्रधानमंत्री ने इन नवनिर्मित परिसरों का लोकार्पण किया।

अब यहां पर सरकार के कई बड़े दफ्तर और मंत्रालय एक ही जगह पर होंगे। चूंकि पहले ये दफ्तर अलग-अलग जगहों पर, पुराने भवनों में चलते थे। इसलिए काम में देरी होती थी, क्योंकि अफसरों को एक-दूसरे से मिलने में परेशानी होती थी और आम लोगों को भी अलग-अलग दफ्तरों के चक्कर लगाने पड़ते थे। लेकिन अब सेवा तीर्थ परिसर में प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ), राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय और कैबिनेट सचिवालय एक साथ काम करेंगे। यानी देश के बड़े फैसलों से जुड़े दफ्तर एक ही जगह होगे, जिससे फैसले जल्दी होंगे और कामकाज में तालमेल बेहतर रहेगा।

यही नहीं, चूंकि कर्तव्य भवन-1 और 2 में कई अहम मंत्रालयो को जगह दी गई है। इनमें वित्त, रक्षा, स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि, कानून, सूचना एवं प्रसारण, संस्कृति, रसायन एवं उर्वरक, जनजातीय कार्य और कॉरपोरेट कार्य जैसे मंत्रालय शामिल है। इसका फायदा यह होगा कि लोगों को अलग-अलग काम के लिए अलग-अलग जगह भटकना नहीं पड़ेगा।

पीएम नरेंद्र मोदी ने सेवा तीर्थ के उद्घाटन के बाद महिलाओं, युवाओं, किसानों और कमजोर वर्गों के कल्याण से जुड़ी महत्वपूर्ण फाइलों पर हस्ताक्षर किए। उनके प्रमुख फैसले में पीएम राहत योजना के तहत दुर्घटना पीड़ितों को 1.5 लाख रुपये तक कैशलेस इलाज की सुविधा, ताकि तत्काल चिकित्सा सहायता से जान बचाई जा सके। और लखपति दीदी लक्ष्य के अंतर्गत महिलाओं के लिए लक्ष्य को दोगुना कर 6 करोड़ करना, आर्थिक सशक्तिकरण को बढ़ावा देना शामिल है।

वहीं अन्य निर्णय के तहत कृषि अवसंरचना निधि को दोगुना बढ़ाकर 2 लाख करोड़ रुपये करना, किसानों को मजबूत समर्थन देना शामिल है। जबकि स्टार्टअप इंडिया फंड ऑफ फंड्स 2.0 को मंजूरी, युवाओं और उद्यमियों के लिए नई संभावनाएँ खोली जाएंगी। इस प्रकार ये फैसले सेवा तीर्थ के नागरिक देवो भव मंत्र को साकार करते हैं, जो 12-13 फरवरी 2026 को लिए गए।

हालांकि कुछ आलोचक लोग तो यहां तक कह रहे हैं कि सेवा तीर्थ द्वारा अब आरक्षण जैसे मेवा का प्रसाद मुंह देखकर बांटा जाएगा और कथित सामाजिक न्याय आधारित हिंदुत्व के जयकारे चटखारे पूर्वक लगते रहें, इसके मुकम्मल इंतजाम किए जाएंगे। इस प्रकार यह एक नया राजनीतिक-सामाजिक तीर्थ बना दिया जाएगा। शायद भारत इसी कोशिश से विश्व गुरु बन जाये।

पुराण दिग्दर्शन ....

सन्देहाभासनिकारणाध्यायः (नौवां अध्याय)

(गतांक से आगे...)

मोहनी को देखकर वीर्यपात

श्रीमद्भागवत (8।12। 1-47) में लिखा है कि- %विष्णु भगवान् के मोहिनी रूप को देखकर शिव जी मुग्ध हो गए और उसे पकड़ने के लिये बेतहाशा भागते फिरे । इस दौड़ धूप में जब कुछ भी हाथ न लगा तो बंभोले जी का वीर्य स्खलित हो गया। जहाँ जहाँ वह वीर्य गिरा उसी उसी स्थान में सोने चाँदी आदि धातुओं की खानें बन गई इत्यादि कथा पर भी दयानन्दी लोग खूब कहकहे लगाया करते हैं और अश्लीलता तथा असं-भवता की दुहाई देकर आसमान को सर पर उठाया करते हैं। इसलिय हम इस आख्यान पर भी क्रमागत शैली के अनुसार कुछ विशेष विचार करना चाहते हैं। तद्यथा-

वैदिक स्वरूप

(क) (प्रजापतिः) अप्सरो रूपं कृत्वा पुरस्तात्प्रत्युदैत्।

(ख) तदस्य (विष्णोः) एतस्या रम्यायां तन्वां देवा अरभन्त तस्माद्धि रम्य हिरण्य ह वै तद् हिरण्यमित्याचक्षते परोक्षम् । (शतपथ 7।4।1।16)

(ग) अग्निर्हवाऽअपोऽभिदध्यौ मिथुनान्याभिः स्यामिति ताः सम्बभुवुः तासु रेतः प्रासिञ्चत् तद्धिरण्यमभवत् ।

(शतपथ 2 । 1 । 15)

(घ) तस्य रेतः परापतत् । तद्धिरण्यमभवत् ।

(तैत्तिरीय 1 । 1 । 3।8)

(ङ) त्रेधा जातं जन्मनेदं हिरण्य-मग्निरेकं प्रियतमं बभूव।

सोमस्येकं हिंसितस्य परापतत्, अपामेकं बेधसां रेत आहुः ।।

(अथर्व 5 । 28 । 1)

(च) अग्ने रेतो हिरण्यम् ।

(शतपथ 2 । 2।3।18)

क्रमशः...

सशस्त्र क्रांति की पहली ज्वाला थे वासुदेव बलवंत फड़के

गौरव काला

ब्रिटिश हूकूमत के खिलाफ पहला सशस्त्र विद्रोह करने वाले पहले क्रांतिकारी थे बलवंत फड़के। किसानों की दयनीय दशा ने उन्हें विचलित कर दिया था। वो कहते थे कि स्वराज ही इसकी एकमात्र दवा है।

देश को आजादी दिलाने में हजारों क्रांतिकारियों ने अपने लहू का कतरा-कतरा बहा दिया। हम सभी जानते हैं कि अंग्रेजों के खिलाफ हल्ला बोल का आगाज 1857 की क्रांति से शुरू हुआ था। लेकिन, पहली क्रांति की विफलता के बाद जब देश के क्रांतिवीर नये तरीके से आजादी की तैयारी कर रहे थे तब तक महाराष्ट्र के रायगढ़ में एक वीर सपूत जन्म ले चुका था। वो थे- वासुदेव बलवंत फड़के। उन्हें सशस्त्र क्रांति का जनक भी कहा जाता है।

ब्रिटिश हूकूमत के खिलाफ पहला सशस्त्र विद्रोह करने वाले पहले क्रांतिकारी थे बलवंत फड़के। किसानों की दयनीय दशा ने उन्हें विचलित कर दिया था। वो कहते थे कि स्वराज ही इसकी एकमात्र दवा है।

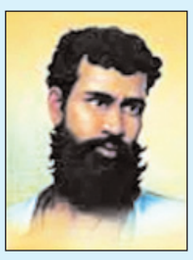

आज वासुदेव बलवंत फड़के की पुण्यतिथि है। बलवंत फड़के स्वतंत्रता संग्राम के क्रांतिकारी थे। उन्हें आदि क्रांतिकारी कहा जाता है। वे ब्रिटिश काल में किसानों की दयनीय दशा को देखकर विचलित हो उठे थे। उनका दृढ विश्वास था कि स्वराज ही इस रोग की दवा है। उन्होंने ज्योतिबा फुले और लोकमान्य तिलक के साथ मिलकर हथियार चलाने का अभ्यास किया। उनके नाम से ही अंग्रेज थर-थर कांपते थे। उनके सिर पर 50 हजार रुपये जिंदा या मुर्दा पकड़ने का इनाम रखा था।

महाराष्ट्र के रायगढ़ में 4 नवंबर 1845 को जन्मे वासुदेव बलवंत फड़के बचपन से ही कुछ बड़ा करने के सपने देखते थे। उनके पिता ने उन्हें दुकान चलाने को कहा लेकिन, उन्होंने पिता की बात नहीं मानी और मुंबई चले गए। फिर उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। उन्होंने किसानों की आवाज बुलंद करते हुए अंग्रेजों के खिलाफ आवाज उठाना शुरू किया। भील और धांगड़ जातियों को इकट्ठा किया और रामोशी नाम का क्रांतिकारी संगठन खड़ा किया। 1879 में विद्रोह का आगाज करते हुए अंग्रेजों के खिलाफ मुक्ति संग्राम में धन एकत्र करने के लिए उन्होंने धनी अंग्रेज साहूकारों को लूटना शुरू किया। अंग्रेजों के दिल में उनके नाम का इस कदर खौफ था कि वासुलेव बलवंत का नाम सुनकर ही अंग्रेज थर-थर कांपते थे। वो ज्योतिबा पुले और लोकमान्य तिलक के भी साथी थे। वासुदेव बलवंत को सशस्त्र संग्राम का जनक भी कहा जाता है। उन्होंने अपने संगठन के युवाओं को हथियारों की ट्रेनिंग दी और अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने को तैयार किया। कहा जाता है कि अंग्रेजों की नाक पर दम कर देने के बाद उनके सिर 50 हजार का ईनाम घोषित हुआ। उन्हें जिंदा या मुर्दा पकड़ने का फरमान जारी हुआ लेकिन, अंग्रेज उन्हें पकड़ नहीं सके। वो अंग्रेजों के हाथ तब आए जब वो बीमार अवस्था में एक मंदिर में आराम कर रहे थे। उन्हें कालापानी की सजा हुई और इलाज न मिल पाने की वजह से देश का यह वीर सपूत 17 फरवरी 1883 को कालापानी की सजा काटते हुए शहीद हो गया।

बांग्लादेश में सत्ता परिवर्तन की वैचारिक क्रांति

ललित गर्ग

बांग्लादेश की राजनीति एक बार फिर इतिहास के मोड़ पर खड़ी है। लगभग दो दशकों के लंबे अंतराल के बाद यदि बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (बीएनपी) स्पष्ट बहुमत के साथ सत्ता में लौटती है और तारिक रहमान प्रधानमंत्री पद की दावेदारी तक पहुंचते हैं, तो यह केवल सत्ता परिवर्तन नहीं, बल्कि राजनीतिक दिशा परिवर्तन का संकेत होगा। 299 सीटों में से 212 पर विजय का दावा इस बात का प्रमाण है कि मतदाता लंबे समय से चली आ रही अस्थिरता, अंतरिम व्यवस्थाओं और वैचारिक ध्रुवीकरण से बाहर निकलकर एक निर्णायक जनादेश देना चाहता है। छात्र आंदोलन से उपजी नेशनल सिटीजन पार्टी का मात्र छह सीटों पर सिमटना भी इस तथ्य को पुष्ट करता है कि जनभावना प्रयोगधर्मिता से आगे बढ़कर स्थायित्व की ओर झुक रही है। लगभग अठारह महीने से चल रही अंतरिम व्यवस्था के अवसान के साथ बांग्लादेश एक नए अध्याय में प्रवेश करने जा रहा है, पर प्रश्न यह है कि यह अध्याय उदार लोकतंत्र का होगा या किसी नए प्रकार के वैचारिक वर्चस्व का?

बांग्लादेश का इतिहास संघर्ष, त्याग और पहचान की जिजीविषा से निर्मित हुआ है। 1971 के मुक्ति संग्राम में भारत की निर्णायक भूमिका केवल सैन्य सहायता तक सीमित नहीं थी, वह सांस्कृतिक और मानवीय सहयोग का भी प्रतीक थी। परंतु पिछले कुछ वर्षों में राजनीतिक ध्रुवीकरण, कट्टरवादी विमर्श और बाहरी प्रभावों ने उस ऐतिहासिक आत्मीयता पर धुंध डालने का प्रयास किया। अंतरिम सरकार के दौरान जिस प्रकार वैचारिक कठोरता और प्रशासनिक असमंजस दिखा, उसने अर्थव्यवस्था और सामाजिक ताने-बाने दोनों को प्रभावित किया। ऐसे समय में स्पष्ट जनादेश को स्थिरता का अवसर माना जा सकता है, बशर्ते सत्ता इसे प्रतिशोध का माध्यम न बनाए, बल्कि पुनर्निर्माण का औजार बनाए।

तारिक रहमान के सामने सबसे बड़ी चुनौती

सांप्रदायिक सौहार्द की पुनर्स्थापना होगी। बांग्लादेश का सामाजिक ढांचा बहुलतावादी है, वहां अल्पसंख्यक समुदायों की सुरक्षा और सम्मान केवल नैतिक दायित्व नहीं, बल्कि लोकतांत्रिक विश्वसनीयता की कसौटी है। यदि नई सरकार कट्टरवाद से दूरी बनाकर विकासोन्मुखी एजेंडा अपनाती है, तो वह न केवल आंतरिक स्थिरता ला सकती है, बल्कि दक्षिण एशिया में एक सकारात्मक उदाहरण भी प्रस्तुत कर सकती है। पर यदि चुनावी विजय को वैचारिक वर्चस्व के रूप में प्रस्तुत किया गया, तो यह जनादेश अवसर से अधिक संकट में बदल सकता है।

आर्थिक मोर्चे पर बांग्लादेश ने पिछले दशक में उल्लेखनीय प्रगति की थी। वस्त्र उद्योग, निर्यात वृद्धि और महिला सशक्तिकरण जैसे क्षेत्रों में उसने मिसाल कायम की। किंतु राजनीतिक अस्थिरता और नीतिगत अनिश्चितता ने निवेशकों के विश्वास को झटका दिया। अब नई सरकार के लिए यह अनिवार्य है कि वह आर्थिक सुधारों को गति दे, रोजगार सृजन पर ध्यान केंद्रित करे और विदेशी निवेश के लिए अनुकूल वातावरण बनाए। विकास की नई गंगा तभी बहेगी जब शासन पारदर्शी, जवाबदेह और समावेशी होगा। केवल नारे या राष्ट्रवाद की तीखी ध्वनियां आर्थिक संकट का समाधान नहीं बन सकतीं।

भारत-बांग्लादेश संबंध इस चुनाव के सबसे महत्वपूर्ण आयामों में से एक हैं। दोनों देशों के बीच साझा इतिहास, सांस्कृतिक निकटता और आर्थिक परस्परता है। सीमा प्रबंधन, जल बंटवारा, व्यापार और सुरक्षा सहयोग जैसे मुद्दे परस्पर विश्वास से ही सुलझ सकते हैं। हाल के वर्षों में पाकिस्तान के साथ बढ़ती निकटता और भारत के प्रति संदेहपूर्ण बयानबाजी ने संबंधों में अनावश्यक तनाव पैदा किया। यदि नई सरकार क्षेत्रीय संतुलन की नीति अपनाते हुए भारत के साथ सौहार्दपूर्ण संवाद पुनः स्थापित करती है, तो यह दोनों देशों के हित में होगा। भारत ने बांग्लादेश के निर्माण और विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, उस ऐतिहासिक साझेदारी को भावनात्मक नहीं, व्यावहारिक आधार पर पुनर्जीवित करने की आवश्यकता है।

यह भी ध्यान रखना होगा कि दक्षिण एशिया की राजनीति अब केवल द्विपक्षीय समीकरणों तक सीमित नहीं है। चीन की बढ़ती उपस्थिति, अमेरिका की रणनीतिक रुचि और पाकिस्तान की पारंपरिक भूमिका-इन सबके बीच बांग्लादेश को संतुलित कूटनीति अपनानी होगी। यदि नई सरकार वैचारिक आग्रहों से ऊपर उठकर राष्ट्रीय हित को सर्वोपरि रखती है, तो वह क्षेत्रीय शक्ति संतुलन में एक परिपक्व भूमिका निभा सकती है। परंतु यदि विदेश नीति घरेलू राजनीति का विस्तार बन गई, तो अस्थिरता का चक्र फिर दोहराया जा सकता है।

इस चुनाव का एक और महत्वपूर्ण संकेत यह है कि बांग्लादेश का मतदाता अब निर्णायकता चाहता है। लंबे समय तक आंदोलन, विरोध और अंतरिम प्रयोगों से थका समाज स्थिर शासन की आकांक्षा रखता है। किंतु स्थिरता केवल बहुमत से नहीं आतीय वह संस्थाओं की मजबूती, न्यायपालिका की स्वतंत्रता और मीडिया की स्वायत्तता से आती है। नई सरकार को यह समझना होगा कि लोकतंत्र केवल चुनाव जीतने का नाम नहीं, बल्कि असहमति को सम्मान देने की संस्कृति का नाम है। यदि विपक्ष को हाशिये पर धकेला गया या आलोचना को देशविरोध का रूप दिया गया, तो लोकतांत्रिक ऊर्जा क्षीण हो जाएगी।

बांग्लादेश के लिए यह क्षण आत्ममंथन का भी है। क्या वह अपनी पहचान को केवल धार्मिक राष्ट्रवाद तक सीमित करेगा, या भाषा, संस्कृति और बहुलता की उस विरासत को आगे बढ़ाएगा जिसने उसे जन्म दिया? मुक्ति संग्राम की मूल भावना सामाजिक न्याय और समान अवसर की थी। यदि नई सत्ता उस भावना को पुनर्जीवित करती है, तो यह जनादेश ऐतिहासिक सिद्ध होगा। अन्यथा यह अवसर भी इतिहास की एक और चूकी हुई संभावना बन सकता है।

भारत की दृष्टि से भी यह चुनाव महत्वपूर्ण है। नई दिल्ली को प्रतिक्रिया में उतावलापन नहीं, बल्कि धैर्य और कूटनीतिक परिपक्वता दिखानी होगी। पड़ोसी देश की संप्रभुता और जनादेश का सम्मान करते हुए सहयोग का हाथ बढ़ाना ही दीर्घकालिक हित में है। सीमा पार आतंकवाद, अवैध घुसपैठ और तस्करी जैसे मुद्दों पर सख्ती के साथ-साथ आर्थिक और सांस्कृतिक संवाद को भी सुदृढ़ करना होगा। संबंधों में भावनात्मकता के बजाय व्यावहारिकता और पारस्परिक सम्मान की नींव आवश्यक है।

अंततः यह चुनाव बांग्लादेश के लिए निर्णायक इसलिए है क्योंकि यह केवल सरकार बदलने का अवसर नहीं, बल्कि शासन की शैली और राष्ट्रीय दिशा तय करने का क्षण है। यदि नई सरकार कट्टरवाद से मुक्त, समावेशी और विकासोन्मुखी नीति अपनाती है, तो वह बांग्लादेश को स्थिरता और समृद्धि के पथ पर अग्रसर कर सकती है। परंतु यदि वह अतीत की कटु स्मृतियों और वैचारिक आग्रहों में उलझी रही, तो जनादेश की सार्थकता संदिग्ध हो जाएगी। बांग्लादेश को अब नई संभावनाओं, नई सोच और नए संकल्पों के साथ आगे बढ़ना है। यही इस चुनाव का संदेश है और यही उसकी वास्तविक परीक्षा भी।

आज का इतिहास

1827 जॉन हेनरी पेस्टलोज़ी नामक स्वीज़रलैंड के बुद्धिजीवी का निधन हुआ।
1859 फ्रांसीसी नौसेना ने साइगोन के गढ़ पर कब्जा कर लिया, एक ऐसा किला जिसे 1,000 नगीने द्वारा संचालित किया गया था एन राजवंश के सैनिकों, साइगॉन और दक्षिणी वियतनाम के अन्य क्षेत्रों को जीतने के लिए मार्ग।
1865 अमेरिका में गृह युद्ध के दौरान कोलंबिया सुप्रीम कोर्ट को जला दिया गया।
1872 मारियानो गोमेज़, जोस बर्गोस, और जैसिंटो ज़मोरा, को सामूहिक रूप से गोमुर्ज़ा के रूप में जाना जाता है, मनीला, फिलिपींस में, 1872 कैरेट म्यूटिन से उत्पन्न होने वाले तोड़फोड़ के आरोपों में स्पेन के कोलोनियल अधिकारियों द्वारा निष्पादित किया गया था।
1878 सैन फ्रांसिस्को शहर में पहली बार टेलीफोन एक्सचेंज खोला गया।
1882 पहला टेस्ट क्रिकेट मैच सिडनी के क्रिकेट ग्राउंड पर खेला गया।
1883 महान क्रांतिकारी, स्वतंत्रता सेनानी और सामाजिक कार्यकर्ता वासुदेव बल वंत फडके का अदन की जेल में निधन हुआ।
1894 अमेरिकी डाकू जॉन वेस्ले हार्डिन को जेल से रिहा किया गया।
1904 इतालवी संगीतकार गियाकोमो पुक्किनी की मैडम बटरफ्लाई का मिलान में ला स्काला में प्रीमियर हुआ, जिससे नकारात्मक समीक्षा हुई जिसने उन्हें ओपेरा को फिर से लिखने के लिए मजबूर किया।
1913 न्यूयॉर्क शहर में अमेरिकी नेशनल गार्ड की 69 वीं रेजीमेंट आर्मरी में, आर्मरी शो खोला गया, जिसमें अमेरिकियों को अवेंट-गार्डे और ऑर्मोडर्न आर्ट से परिचित कराया गया।
1927 हवाई जहाज बनाने वाली विश्व की प्रथम कंपनी की स्थापना विलियम बोइंग और एल्बर्ट हबार्ड द्वारा की गयी।
1933 अमेरिका की साप्ताहिक पत्रिका 'न्यूजवीक' प्रकाशित हुई।
1944 द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान एनीवेटोक का युद्ध शुरू हुआ जिसमें अमेरिकी सैनिकों ने जीत हासिल की।
1947 सोवियत संघ में 'वायस ऑफ अमेरिका' का प्रसारण शुरू किया गया।
1949 चैम वीज़मैन ने इज़राइल के पहले राष्ट्रपति के रूप में अपना कार्यकाल शुरू किया।
1959 क्लाउड कवर वितरण को मापने के लिए पहला मौसम उपग्रह, वानगार्ड 2 लॉन्च किया गया था।
1962 जर्मनी के हैम्बर्ग में तूफान से 265 लोगों की मौत हुई।

क्यों हारी जमात, रहमान की जीत की इनसाइड स्टोरी

अभिनय आकाश

ये देश मुसलमानों का है, हिंदुओं का है, बौद्धों और ईसाइयों का भी है। 58 साल का शख्त जब ढाका के अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर अपने कदम रखता है तो हजरों लोगों की भीड़ के बीच अपनी मिट्टी को सिर से लगाते हुए कुछ अंदाज में अपनी वापसी का ऐलान करता नजर आता है। 17 साल का वनवास काट अपने देश में दाखिल होने के दो महीने से भी कम समय बाद अब उसी शख्स से सिर पर देश के प्रधानमंत्री का ताज सजने वाला है। बांग्लादेश के इतिहास में 12 फरवरी 2026 का दिन एक बड़े बदलाव के रूप में दर्ज हो गया। साल 2024 के छात्र आंदोलन और शेख हसीना के देश छोड़ने के बाद यह पहला मौका था जब देश में लोकतांत्रिक तरीके से नई सरकार चुनने के लिए मतदान हुआ। इस चुनाव को केवल नई संसद चुनने तक सीमित नहीं माना जा रहा बल्कि इसे देश के संविधान और शासन व्यवस्था में बड़े बदलाव की शुरुआत के रूप में देखा जा रहा है। यह चुनाव अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार और नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस की निगरानी में संपन्न हुआ। इस चुनाव की सबसे ख़ास बात यह रही कि मतदाताओं ने केवल उम्मीदवारों को ही नहीं चुना बल्कि जुलाई चार्टर नाम के जनमत संग्रह पर भी अपनी मोहर लगाई। इसमें संविधान में व्यापक बदलावों का प्रस्ताव रखा गया है। जिनका मकसद राजनीति को अधिक पारदर्शी और जवाबदेह बनाना है। शेख हसीना की पार्टी आवामी लीग के चुनाव से बाहर रहने के कारण मुख्य मुकाबला बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी यानी बीएनपी और जमात इस्लामी के गठबंधन के बीच रहा।

तकरीबन 17 साल बाद देश में बिना आवामी लीग के नेतृत्व के चुनाव हुए जिन्हें आवामी लीग ने दिखावा ही बताया। तारिक रहमान पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया के बेटे हैं। वह पिछले 17 वर्षों से लंदन में निर्वासन में रह रहे थे और चुनाव से ठीक पहले तारिक रहमान 2008 में तारिक रहमान इलाज के लिए लंदन गए थे। उस समय उनके खिलाफ कई आपराधिक और भ्रष्टाचार से जुड़े मामले चल रहे थे। राजनीतिक दबाव भी बढ़ा हुआ था। इसी वजह से वह लंबे समय तक ब्रिटेन में रहे। एक साल में उच्च अदालतो ने तारिक रहमान को बढ़े मामलों में बरी कर दिया, जिनमें 2004 का ग्रेनेड हमला और जिया ऑफेनेज ट्रस्ट मामला शामिल है। इसके बाद उनकी राजनीतिक वापसी के कानूनी रास्ते साफ हुए। उनकी वापसी और पार्टी की ऐतिहासिक जीत ने उन्हें देश के अगले प्रधानमंत्री पद का सबसे मजबूत दावेदार बना दिया है। समर्थकों का मानना है कि उनके नेतृत्व में बांग्लादेश में स्थिरता और विकास का नया दौर शुरू होगा। इस चुनाव के साथ हुए जनमत संग्रह में 72त्न से ज्यादा मतदाताओं ने जुलाई चार्टर के पक्ष में वोट किया। इसके तहत कई बड़े सुधार प्रस्तावित हैं। प्रधानमंत्री के कार्यकाल की सीमा तय करना, संसद में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाना, न्यायपालिका और पुलिस व्यवस्था में सुधार।

1971 से ही बांग्लादेश की नियति जीतने वाले के नक्शे कदम पर चलती रही है। जो जीतता है वह सब कुछ ले जाता है। जो हारता है उसे जेल की कोठरी देखनी पड़ सकती है। देश से भागना पड़ सकता है या फिर उसकी कब्र भी खोद सकती है। कहानी की शुरुआत 1975 से होती है। इसी बरस शेख हसीना के पिता मुजब उर रहमान की हत्या कर दी गई। उन्हें बंग बंधु के नाम से जाना जाता था। आजादी के बाद वह देश के पहले राष्ट्रपति बने थे। लेकिन उनके राज में हालात बिगड़ गए थे। युद्ध की वजह से खजाना खाली था। सरकारी तंत्र में भ्रष्टाचार फैल रहा था। 1972 में मुजीब ने विद्रोह रोकने के लिए रखी वाहिनी नाम की एक फोर्स बनाई। लेकिन उस फोर्स पर ही हत्या और रेप के इल्जाम लगे। जनता का मोह भंग उनसे होने लगा। फिर तारीख आई 14 अगस्त 1975 बांग्लादेश की फौज के कुछ बागी अफसरों ने मुजीब और उनके परिवार के 18 लोगों की हत्या कर दी। किस्मत से उनकी दो बेटियां शेख हसीना और शेख रिहाना उस वक्त जर्मनी में थी। इसके बाद सत्ता जियाउ रहमान के हाथ में आई। अगले दशक में देश ने एक और सैन्य शासक देखा हुसैन मोहम्मद इरशाद के हाथ में सत्ता गई। इन दोनों सैन्य शासकों ने एक ही एजेंडा चलाया। आवामी लीग का नामोनिशान मिटा दो। उन्होंने उन ताकतों को वापस जिंदा किया जो 1971 में आजादी के खिलाफ थी ताकि आवामी लीग की लोकप्रियता को टक्कर दी जा सके। 1990 के दशक के आखिर आखिर तक इरशाद के खिलाफ माहौल बनने लगा था। तब एक दिलचस्प वाकया हुआ। दो जानी दुश्मन एक साथ आ गई। शेख हसीना और खालिदा जिया दोनों ने मिलकर के इरशाद को गद्दी से उतार फेंका। लेकिन यह दोस्ती बस मतलब भर की थी। दोनों जब ताकतवर हुई तो 1991 से एक नया दौर शुरू हुआ जिसे बेगमों की जंग कहा जाता है। बैटल ऑफ द बेगम्स। एक ही ढर्रा था जो गद्दी पर बैठेगा वो सामने वाले का धंधा बंद करवा देगा। 1991 में खालिदा जीती। 1996 में हसीना जीती। 2001 में फिर खालिदा जिया जीत गई। 2006 आते-आते सड़कों पर खून खराबा शुरू हो गया था। जब नेताओं से बात नहीं संभली तो फौज ने कहा कि अब हम संभालेंगे। 2007 में इमरजेंसी लगा दी गई और हसीना खालिदा दोनों को जेल में डाल दिया गया। फिर 2008 में चुनाव हुए। शेख हसीना ने ऐसी वापसी की कि अगले 15 साल तक गद्दी पर बनी रहीं। इस दौरान जमात के नेताओं को फांसी हुई। 2018 में खालिदा जिया जेल गई।

देश के इतिहास में यह पहली बार है, जब शेख हसीना की पार्टी चुनाव में नहीं है। यह अवामी लीग का अपना फैसला नहीं था, बल्कि उस पर थोपा गया। जो पार्टी बांग्लादेश की मुक्ति से लेकर अभी तक, उसके हर राजनीतिक-सामाजिक बदलाव की साक्षी रही है, उसे लोकतांत्रिक प्रक्रिया से दूर करना सही तो नहीं कहा जा सकता। बीएनपी या जमात सत्ता में जो भी आए, उसके ऊपर सबसे बड़ी जिम्मेदारी होगी देश की जनता की ख्वाहिशों को पूरा करने की। अंतरिम सरकार आम लोगों में भरोसा जगाने में असफल रही है। चुनाव में बीएनपी की जीत तय मानी जा रही है। अगर ऐसा होता है तो उसके सामने जनता की कसौटी पर खरा उतरने की चुनौती होगी।

कृषि क्षेत्र में एआई की चुनौतियां भी कम नहीं

ऋषभ मिश्रा

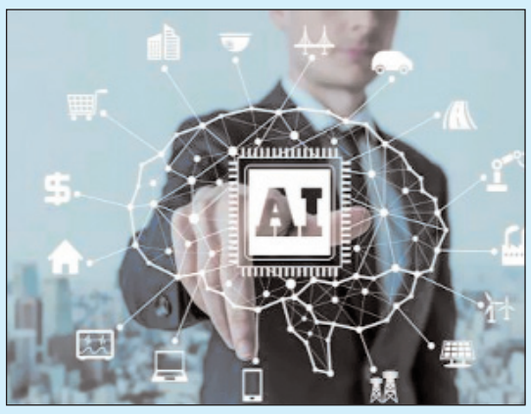

भारत की अर्थव्यवस्था की रीढ़ कहे जाने वाले कृषि क्षेत्र के लिए हाल ही में केंद्रीय बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) को एक गेम चेंजर के रूप में पेश किया है। सवाल यह है कि क्या यह तकनीकी हस्तक्षेप वाकई देश के 14 करोड़ किसानों की तस्वीर बदल सकेगा? बजट में कृषि क्षेत्र के लिए 1।62 लाख करोड़ रुपए से अधिक का आवंटन किया गया है, जो पिछले वर्ष से लगभग 7 फीसदी अधिक है। इसमें सबसे उल्लेखनीय है, भारत विस्तार प्लेटफार्म की स्थापना।

यह एक बहुभाषी एआई टूल है जो एग्रीस्टैक पोर्टल और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) की सत्यापित कृषि पद्धतियों को एआई सिस्टम के साथ एकीकृत करेगा। इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से किसानों को कई सुविधाएं मिलेंगी जैसे कि मिट्टी की गुणवत्ता, जलवायु परिस्थितियों और फसल के आधार पर विशिष्ट सुझाव, सटीक और स्थानीय मौसम की जानकारी, जो सिंचाई और बुआई के फैसलों में मदद करेगी, फसलों में लगने वाली बीमारियों की शीघ्र पहचान और समाधान, फसलों के सही दाम और बाजार की मांग की जानकारी, किसानों को उनकी अपनी भाषा में सलाह, जिससे डिजिटल विभाजन कम होगा।

इसके अतिरिक्त बजट में 'कृषि साथी' नामक एआई चैटबॉट की भी घोषणा की गई है, जो वॉयस और वीडियो के माध्यम से किसानों के सवालों का जवाब देगा। लेकिन एआई की सारी संभावनाओं के बावजूद, भारतीय कृषि क्षेत्र में इसके व्यापक कार्यान्वयन में कई गंभीर चुनौतियां हैं, जिन्हें नजरअंदाज नहीं किया जा सकता।

भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में खासकर छोटे और सीमांत किसानों में डिजिटल साक्षरता की गंभीर कमी है। जो किसान 85 फीसदी कृषक समुदाय का हिस्सा हैं, उनमें से अधिकांश स्मार्टफोन का बुनियादी उपयोग तो कर लेते हैं, लेकिन एआई आधारित जटिल एप्लीकेशन का इस्तेमाल करना उनके लिए चुनौतीपूर्ण है।

एक औसत भारतीय किसान की उम्र 50 वर्ष से अधिक है और उनमें से कई अनपढ़ या अर्ध-साक्षर हैं। यदि भारत विस्तार जैसे प्लेटफॉर्म को सफल बनना है तो सिर्फ बहुभाषी इंटरफेस काफी नहीं है। किसानों को इन तकनीकों के उपयोग का व्यापक प्रशिक्षण देना होगा, जिसके लिए जमीनी स्तर पर कृषि विस्तार कार्यकर्ताओं की बड़ी संख्या में आवश्यकता होगी।

भारत के बहुत से गांवों में अभी भी मोबाइल कनेक्टिविटी और इंटरनेट की सुविधा नहीं है और जहां है भी, वहां इसकी रफ्तार धीमी है। सरकार ने प्रधानमंत्री 'वाई-फाई एक्सेस नेटवर्क' इंटरफेस (पीएम वाणी) और भारतनेट परियोजना के माध्यम से ग्रामीण कनेक्टिविटी बढ़ाने की कोशिश की है, लेकिन जमीनी स्तर पर इनका कार्यान्वयन अभी भी अपर्याप्त है।

बीएमसी: मुंबई में तावड़े-नागपुर में ठाकरे, संदेश साफ

अमिताभ श्रीवास्तव

बृहन्मुंबई महानगर पालिका (बीएमसी) में ऋतु तावड़े के महापौर बनने के बाद महाराष्ट्र की लगभग सभी महानगर पालिकाओं में नेतृत्व की स्थितियां स्पष्ट हो गई हैं। चंद्रपुर के बड़े उलटफेर की चेतावनी का असर परभणी में दिखा है। ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (एआईएमआईएम) के उत्साह को मालेगांव मनपा ने ठंडा कर चुनाव की जमीनी सच्चाई सामने लाई है। हालांकि नागपुर और सबसे नई जालना जैसी राज्य की अनेक महानगर पालिकाओं में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के पास बहुमत था।

किंतु छत्रपति संभाजीनगर से लेकर ठाणे-अकोला से नासिक तक एकतरफा राजनीति का अवसर नहीं था। राज्य की 29 महानगर पालिकाओं के चुनाव के आरंभ में जिस प्रकार राजनीति के दांव-पेंच खेले गए, उसी के जवाब महापौर के चुनाव में मिले। मुंबई, नागपुर, पुणे मनपा को सबसे अधिक प्रतिष्ठा की नजर से देखा गया।

यहां तक कि शिवसेना के ठाकरे गुट का पूरा ध्यान मुंबई और आस-पास केंद्रित था। मगर पहले चुनाव परिणाम और बाद में महापौर के चयन ने स्थानीय राजनीति को राज्य से जोड़ने तथा एक समान बनाने के प्रयास सिरे से ठुकरा दिए। मोहल्ले की राजनीति को गली-कूचों में ही समझने का संदेश दिया। बीते लगभग दो साल में महाराष्ट्र ने देश से लेकर पास-पड़ोस तक का चुनाव देखा और सक्रिय भागीदारी निभाई।

वर्ष 2024 में जब लोकसभा का चुनाव हुआ, तब संविधान बदलने के मुद्दे को गर्माया गया। विपक्ष ने भाजपा के खिलाफ 'इंडिया' गठबंधन बनाकर नई रणनीति पर चलने का शंखनाद किया, जिसमें उसे सफलता भी मिली। उसने भाजपा के लगातार बढ़ते ग्राफ को रोक दिया। उस समय भाजपा को लोकसभा में जीत के लिए सीटों के लक्ष्य पर 'अबकी बार 400 पार' का नारा देना भारी पड़ा।

महाराष्ट्र में 23 सीटें जीतने वाली भाजपा नौ सीटों पर आ गई। हालांकि इस दौरान राज्य में दलीय स्तर पर अनेक विभाजन और गठबंधन की स्थितियां बदल गई थीं। मगर चुनाव परिणाम संविधान बदलने की सोच से जोड़कर देखे गए। कुछ हद तक भाजपा ने अपनी गलती और कमजोरी को स्वीकार कर विधानसभा चुनाव की तैयारी की। इस बार

मामला जातीय समीकरणों में उलझ गया।

एक तरफ मराठा आरक्षण आंदोलन और दूसरी तरफ अन्य पिछड़ा वर्ग का गुस्सा राज्य की महागठबंधन सरकार के लिए परेशानी का कारण था। इस बार चुनाव में कट्टर हिंदुत्व और लाड़ली बहन योजना से महिला मतों को एकतरफा कर चुनाव जीत लिया गया। चुनाव के बाद लोकसभा चुनाव की पराजय का हिसाब चुकता हुआ। दोनों के बाद स्थानीय निकायों के चुनावों की प्रतीक्षा की गई, जो कई साल से लंबित थे।

स्पष्ट था कि राज्य का विपक्ष विधानसभा चुनाव की पराजय से उबरने का प्रयास करेगा। उसने शुरुआत क्षेत्रीय अस्मिता और भ्रष्टाचार के आरोपों से की। किंतु दोनों ही मुद्दों को अधिक समय तक जीवित रखना संभव नहीं हुआ। नगर परिषद और नगर पंचायत के चुनावों में भाजपा के नेतृत्व में भगवा गठबंधन आगे रहा।

इसी के बाद महानगर पालिका चुनाव की घोषणा हुई, जिनमें विपक्ष ने नप चुनाव का पुराना राग कुछ और तेज आवाज में सुनाया। बड़े शहरों के बदलते सामाजिक ढांचे को मराठी मानुस से जोड़ने की कोशिश की। किंतु हर क्षेत्र की चुनावी हवा अपनी तरह चली। तय कर उछाले मुद्दे अपनी जगह रहे और क्षेत्रीय ताकतों- समीकरणों ने नतीजे तय कर दिए।

बावजूद इसके स्थानीय निकायों के चुनाव में जनसांख्यिकीय परिवर्तनों के भविष्य में होने वाले नतीजों को लेकर आवाज उठाई गई थी, वहां निकायों के मुखिया तक पर नजर थी। इस क्रम में मुंबई, नासिक, पुणे, नागपुर, मालेगांव, नांदेड़, छत्रपति संभाजीनगर और परभणी में महापौर के चयन ने सभी किस्म की चिंताओं को दूर करने का प्रयास किया।

बीएमसी की महापौर ऋतु तावड़े ने मुंबई में मराठी अस्मिता से जुड़ी चिंताओं को दूर किया, जबकि नागपुर में नीता ठाकरे को महापौर बनाकर मुंबई की 'ठाकरेशाही' को राज्य के दूसरे सिरे से संदेश दिया। मराठवाड़ा में मराठा आंदोलन की जड़ों को देखते हुए छत्रपति संभाजीनगर में समीर राजूरकर और नांदेड़ में कविता मुले को महापौर बनाया गया। इन स्थानों पर जातिगत आरक्षण नहीं होने से जातीय राजनीति को उत्तर देने की कोशिश की गई। चंद्रपुर में कांग्रेस का सत्ता का खेल पलटा गया और मालेगांव में सत्ता पाने वाले नए दल का उदय हुआ। पुणे में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (अजित पवार गुट) के साथ कड़वाहट चुनाव परिणामों के साथ कम हुई और महापौर चयन में कोई प्रश्न नहीं उठे।

प्रादेशिक अस्मिता पर राजनीति के लिए कोई जगह बाकी नहीं रही। फिर भी महापौर के नाम पर संदेश देने आवश्यक थे, जो बहुत ही स्पष्ट मिल चुके हैं। धर्म-जाति-समाज की ठेकेदारी से हटकर आरक्षण के अलावा हर समाज, संप्रदाय के प्रतिनिधित्व को महत्व मिल चुका है। अवश्य ही चुनावों में समाज के हर वर्ग का प्रतिनिधित्व महत्वपूर्ण होता है।

सामाजिक व्यवस्था अनुसार निर्वाचन प्रक्रिया में हिस्सेदारी तय की जाती है। किंतु इस बार वैमनस्य पैदा कर वोट बटोरने के नए फार्मूले को चलाने का प्रयत्न हुआ। मराठी-गैर मराठी विवाद को खड़ा करने की कोशिश हुई। मुंबई में गुजराती, दक्षिण भारतीय को अलग करने के प्रयास हुए। कभी धार्मिक विभाजन के आधार पर चुनाव लड़ने में माहिर नेताओं ने जातीय और प्रादेशिक स्तर पर विभाजन के बीज बोये। किंतु मतदाता ने हर चिंता से ऊपर उठकर अपनी आवश्यकता अनुसार मत दिया। अब राज्य की सभी महानगर पालिकाओं के महापौर के चयन के साथ साफ हो गया है कि किसी दल ने मजबूरी में और कहीं जरूरी परिस्थितियों में समीकरण बनाए गए। उनसे सत्ताधारी दल की मुंबई से नागपुर तक की नीति साफ हुई। विपक्ष के समक्ष नई रणनीति तैयार करने की चुनौती खड़ी हुई। फिलहाल जिला परिषद अध्यक्षों के चयन के अलावा आने वाले दिनों में कोई नए चुनाव की संभावना नहीं है। इसलिए चिंतन-मनन का अवसर है, जो संकीर्ण सोच से उबरने का अवसर भी है।

मणिपुर के नए मुख्यमंत्री के सामने अनेक चुनौतियां

आदिति फडणीस

मणिपुर के उखरुल जिले के लगभग 2,200 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में करीब 1,40,000 लोग रहते हैं। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार, जिले की साक्षरता दर 81 फीसदी है, लेकिन बेरोजगारी 60 फीसदी से अधिक है। कृषि योग्य भूमि कुल क्षेत्रफल का केवल 2.1 फीसदी है, लेकिन 70 फीसदी आबादी खेती से गुजर-बसर करती है। परिणामस्वरूप, भूमि के हर इंच पर कड़ी नजर रखी जाती है और उसको लेकर हिंसात्मक टकराव होता रहता है।

उखरुल भारत के सबसे अशांत जिलों में से एक है, जहां तंगखुल नागाओं का वर्चस्व है, लेकिन कुकी-जो जनजाति एक मुखर अल्पसंख्यक समूह है, उसे पड़ोसी म्यांमार से कई तरह की मदद के अलावा आर्थिक सहायता मिलती है। इस सप्ताह की शुरुआत में कुकी-जो और नागाओं के बीच हुई गोलीबारी से उखरुल में हिंसा भड़क उठी और पड़ोसी चुराचांदपुर तक फैल गई। यह झड़प उन सभी जनजातीय और सामाजिक-सांस्कृतिक विभाजनों का एक छोटा सा हिस्सा है, जिनका समाधान मणिपुर के नए मुख्यमंत्री युमनाम खेमचंद सिंह को करना होगा।

दिल्ली से हम इस समस्या पर केवल निरर्थक बहस ही कर सकते हैं। फरवरी 2025 से लागू राष्ट्रपति शासन की समाप्ति से कुछ घंटे पहले ही भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के विधायकों ने दिल्ली (इम्फाल नहीं) में सिंह को अपना नेता चुना। राज्य की लगभग 53 फीसदी आबादी वाले हिंदू समुदाय मैतेई से मुख्यमंत्री बनना कोई आश्चर्य की बात नहीं थी।

हालांकि, कुकी-जो और नागा जनजातियों के एक-एक प्रतिनिधि को भी उपमुख्यमंत्री के रूप में सरकार में शामिल किया गया, जो सामुदायिक सुलह और सकारात्मक छवि का संकेत था। लेकिन यह घटनाक्रम कुछ हद तक तब फीका पड़ गया जब उनमें से एक, मंत्री पद का अनुभव रखने वाली प्रमुख कुकी नेता नेमचा किपगेन ने अपनी सुरक्षा को लेकर आशंका जताते हुए इम्फाल जाने के बजाय दिल्ली के मणिपुर भवन से वर्चुअल रूप से शपथ ग्रहण करना बेहतर समझा।

कुकी-जो समुदाय के दो विधायकों-चुराचांदपुर के विधायक एलएम खौटे और तिपाईमुख के विधायक न्गुरसंगलुर सनाते ने भी वर्चुअल रूप से सरकार का समर्थन किया। मणिपुर विधान सभा के 60 सदस्यों में से चुने गए 10 कुकी विधायकों में से कोई भी मई 2023 के बाद से इम्फाल नहीं गया है, जबकि मैतेई समुदाय के लोग पहाड़ी इलाके में जाने से परहेज करते हैं। कुकी संगठनों ने सार्वजनिक रूप से अपने निर्वाचित प्रतिनिधियों के साथ सहयोग न करने की प्रतिज्ञा की है और उन्हें चेतावनी जारी की है।

मणिपुर में हिंसा भड़कने के लिए छोटी-छोटी बातें भी काफी होती हैं। हिंसा का ताजा दौर मार्च 2023 में उच्च न्यायालय के एक आदेश के कारण शुरू हुआ, जिसमें राज्य सरकार को मैतेई समुदाय को अनुसूचित जनजाति में शामिल करने पर विचार करने को कहा गया था। अनुसूचित जनजाति का दर्जा मिल जाने पर मैतेई समुदाय को कुकी और नागा बहुल पहाड़ी क्षेत्रों में जमीन खरीदने का अधिकार मिल जाता। हालांकि, बाद में इस आदेश में संशोधन कर दिया गया। इसके बावजूद बड़े पैमाने पर हिंसा भड़की जिसमें 200 से अधिक लोग मारे गए और राज्य के भीतर लोगों का विस्थापन हुआ। मणिपुर में विभिन्न समुदायों के लगभग 40,000 विस्थापित लोग शिविरों में रह रहे हैं। मूल मुद्दा कि क्या मैतेई समुदाय अनुसूचित जनजाति का दर्जा प्राप्त कर सकता है, अभी तक तय नहीं हुआ है क्योंकि राज्य सरकार को अभी भी केंद्र सरकार को इस पर अपनी राय देनी बाकी है। दो सवाल उठते हैं : युमनाम खेमचंद सिंह ही क्यों और अभी क्यों?

खेमचंद सिंह को आरएसएस से लंबे समय से जुड़े एक तटस्थ और विवादरहित भाजपा नेता के रूप में देखा जाता है। वह सिंगजामेई निर्वाचन क्षेत्र से दो बार 2017 और 2022 में विधायक रह चुके हैं। वर्ष 2022 तक वह विधान सभा अध्यक्ष रहे और बाद में 2025 तक बीरेन सिंह सरकार में मंत्री रहे। उन्होंने पिछले साल दिसंबर में कुकी विस्थापितों के शिविर का दौरा किया और इस सप्ताह की शुरुआत में मैतेई लोगों के शिविर में गए।

हालांकि, मणिपुर के समाज और राजनीति की जटिलता दिखावे और निष्पक्षता से कहीं अधिक है। म्यांमार में हाल ही में चुनाव संपन्न हुए हैं, जिसमें सैन्य समर्थित राजनीतिक दल का सत्ता में आना अपेक्षित था। लेकिन देश के विशाल भूभाग, जिनमें मणिपुर से सटी सीमा पर स्थित सागाइंग प्रांत के कुछ हिस्से भी शामिल हैं, सैन्य सरकार के नियंत्रण से बाहर हैं। म्यांमार की उथल-पुथल अब उसकी सीमाओं तक ही सीमित नहीं है। केंद्र सरकार का मानना है कि मणिपुर में निर्वाचित सरकार सीमा पर व्याप्त अशांति से उत्पन्न राजनीतिक मुद्दों से बेहतर ढंग से निपट सकेगी।

मणिपुर, विशेष रूप से उखरुल राष्ट्रीय समाजवादी परिषद ऑफ नागालैंड (एनएससीएन) का गढ़ है, जिसके साथ केंद्र सरकार लंबे समय से संयुक्त नागालैंड की मांग को लेकर बातचीत करती रही है। इस बीच, हालांकि सरकार ने एनएससीएन के सर्वोच्च नेता मुइवा के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, लेकिन हाल ही में उसने पूर्वी नागालैंड पीपल्स ऑर्गनाइजेशन (ईएनपीओ) के साथ नागालैंड के पूर्वी हिस्सों में एक स्वायत्त प्राधिकरण बनाने की दिशा में काम करने के लिए एक समझौते की घोषणा की है। इससे नागालैंड को एकजुट करने के एनएससीएन के लक्ष्य को झटका लगा है और मणिपुर में नागाओं की अशांति को बढ़ावा मिला है।

खेमचंद सिंह के सामने सबसे बड़ी चुनौतियां हैं कानून-व्यवस्था बहाल करना, विशेषकर हथियारों की बेरोकटोक आवाजाही को रोकना, बेरोजगारी की समस्या का समाधान करने के लिए बुनियादी ढांचागत विकास करना और उन संस्थानों में विश्वास बहाल करना जिनका उद्देश्य लोगों को सुरक्षित महसूस कराना है। कई सवाल अभी भी बने हुए हैं।

बांग्लादेश ने डेढ़-दो साल में बहुत कुछ देख लिया

नीरज कुमार दुबे

बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (बीएनपी) ने देश के संसदीय चुनावों में ऐतिहासिक जीत हासिल करके दो दशक के अंतराल के बाद सत्ता में वापसी कर ली है। बीएनपी के अध्यक्ष और पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया के बेटे तारिक रहमान देश के नए प्रधानमंत्री होंगे। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज तारिक रहमान से फोन पर बात कर उन्हें जीत की बधाई दी। इससे पहले मोदी ने सुबह ही बीएनपी को जीत की बधाई देते हुए ट्वीट कर दिया था। देखा जाये तो बांग्लादेश चुनाव के परिणाम से केवल सत्ता परिवर्तन नहीं हुआ है बल्कि संभवत: उस दौर का भी अंत हुआ है जो लंबे समय तक शेख हसीना और उनकी अवामी लीग के इर्द-गिर्द घूमता रहा। छात्र आंदोलन, आर्थिक ठहराव, भ्रष्टाचार के आरोप और फिर हिंसक टकरावों के बाद बनी राजनीतिक खाली जगह को इस चुनाव ने भरा है। इन चुनावों का महत्व इसलिए भी ज्यादा है क्योंकि यह उस उथल पुथल के बाद हुए हैं जिसने शेख हसीना की पंद्रह साल पुरानी सरकार को गिरा दिया था। छात्र आंदोलन पर सख्त कार्रवाई, बड़ी संख्या में जान हानि और उसके बाद हसीना का देश छोड़ना बांग्लादेश के लोकतांत्रिक इतिहास की बड़ी घटनाएं बन चुकी हैं। अंतरिम सरकार के रूप में नोबेल सम्मान पा चुके मुहम्मद यूनुस ने देश को चुनाव तक पहुंचाया, लेकिन उनका कार्यकाल भी तमाम तरह के विवादों से भरा रहा। चुनाव परिणामों में बीएनपी के नेतृत्व वाले गठबंधन ने 297 सीटों में से 212 सीटें जीत कर साफ बहुमत हासिल कर लिया है। जमात ए इस्लामी के नेतृत्व वाले गठबंधन को 77 सीटें मिलीं, जबकि बाकी सीटें निर्दलीय और छोटे दलों के खाते में गईं। यह भी उल्लेखनीय है कि तीन दशक में पहली बार शेख हसीना की पार्टी अवामी लीग का चुनाव चिह्न नाव मतपत्र पर नहीं था, क्योंकि पार्टी को चुनाव लड़ने से रोक दिया गया। इससे साफ है कि बांग्लादेश की राजनीति अब दो पुराने ध्रुवों की सीधी टक्कर से आगे बढ़कर नए समीकरण बना रही है। तारिक रहमान की वापसी भी अपने आप में एक अलग राजनीतिक कथा है। कभी निर्वासन में रहे रहमान अब साठ वर्ष की उम्र में देश की बागडोर संभालने जा रहे हैं। अपनी मां और पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया के निधन के तुरंत बाद उन्होंने पार्टी की कमान संभाली थी और अब जीत को उनके नाम पर समर्पित करते हुए जश्न टालने की अपील की है। बीएनपी ने चुनाव परिणाम को लोकतंत्र की जीत बताया है और अपने कार्यकर्ताओं के बलिदान को याद किया है। साथ ही तारिक रहमान का 31 सूत्रीय विकास कार्यक्रम एक कल्याणकारी सरकार बनाने की बात करता है, जिससे साफ है कि वह केवल सत्ता नहीं बल्कि नीति आधारित वैधता भी चाहते हैं। सामाजिक स्तर पर भी यह चुनाव अहम रहा। मतदान के दिन सुबह से लंबी कतारों में खड़े मतदाताओं ने यह संकेत दिया था कि लोग पारदर्शी चुनाव और स्थिर शासन चाहते हैं। साथ ही अल्पसंख्यक समुदाय खासकर हिंदू समाज पर हमलों की खबरों के बीच ढाका से बीएनपी के हिंदू नेता गायेश्वर चंद्र राय की जीत प्रतीकात्मक महत्व रखती है। यह नई सरकार के लिए एक संदेश भी है कि उसे अल्पसंख्यक सुरक्षा पर ठोस कदम उठाने होंगे। भारत पहले ही इस मुद्दे पर चिंता जता चुका है। अब बात भारत बांग्लादेश संबंधों की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद फोन कर तारिक रहमान को बधाई दी और दोनों देशों की शांति, प्रगति और समृद्धि के लिए साथ काम करने की बात कही। यह कदम कूटनीतिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण है। भारत ने संकेत दिया है कि वह बांग्लादेश की जनता के जनादेश का सम्मान करता है और नई सरकार के साथ काम करने को तैयार है, चाहे उसका राजनीतिक झुकाव कुछ भी हो। आने वाले दिनों में इसके कई असर दिख सकते हैं। सीमा सुरक्षा और अवैध घुसपैठ जैसे मुद्दों पर संवाद जारी रह सकता है, क्योंकि यह दोनों देशों की साझा चिंता है। साथ ही व्यापार और संपर्क परियोजनाएं, जैसे सड़क, रेल और नदी मार्ग सहयोग, नई सरकार के लिए भी महत्वपूर्ण मुद्दे हैं, इसलिए इन पर चर्चा जारी रहने की संभावना है। इसके अलावा, अगर नई सरकार अल्पसंख्यक सुरक्षा पर भरोसा जगाती है तो द्विपक्षीय भरोसा और गहरा होगा।

हनुमानजी अपनी शक्ति क्यों भूल गए थे?

श्री सीता हरण के बाद हनुमानजी और श्रीराम का मिलन हुआ और हनुमानजी ने श्रीराम को सुग्रीव, जामवंत आदि वानरयूथों से मिलाया। फिर जब लंका जाने के लिए रामसेतु बनाया गया तो श्रीराम ने हनुमानजी को लंका जाने का आदेश दिया, परंतु हनुमानजी ने लंका जाने में अपनी असमर्थता जताई तब जामवंतजी ने हनुमानजी को उनकी शक्तियों की याद दिलाई। परंतु सवाल यह है कि हनुमानजी अपनी शक्ति क्यों भूल गए थे? दरअसल, हनुमानजी को कई देवताओं ने विभिन्न प्रकार के वरदान और अस्त्र-शस्त्र दिए थे। इन वरदानों और अस्त्र-शस्त्र के कारण बचपन में हनुमानजी उधम मचाने लगे थे। खासकर वे ऋषियों के बगीचे में घुसकर फल, फूल खाते थे और बगीचा उजाड़ देते थे। वे तपस्यारत मुनियों को तंग करते थे। उनकी शरारतें बढ़ती गई तो मुनियों ने उनकी शिकायत उनके पिता केसरी से की। माता-पिता में खूब समझाया कि बेटा ऐसा नहीं करते, परंतु हनुमानजी शरारत करने से नहीं रुके तो एक दिन अंगिरा और भृगुवंश के ऋषियों ने कुपित होकर उन्हें श्राप दे दिया कि वे अपने शक्तियों और बल को भूल जाएंगे परंतु उचित समय पर उन्हें उनकी शक्तियों को कोई याद दिलाएगा तो याद आ जाएगी। फिर जब हनुमानजी को श्रीराम का कार्य करना था तो जामवंत जी का हनुमानजी के साथ लंबा संवाद होता है। इस संवाद में वे हनुमानजी के गुणों का बखान करते हैं और तब हनुमानजी को अपनी शक्तियों का आभास होने लगता है। अपनी शक्तियों का आभास होते ही हनुमानजी विराट रूप धारण करते हैं और समुद्र को पार करने के लिए उड़ जाते हैं।

छठी इंद्री क्या होती है, इसे कैसे जागृत किया जा सकता है

- छठी इंद्री को अंग्रेजी में सिक्स्थ सेंस कहते हैं। यह क्या होती है, कहां होती है और कैसे इसे जाग्रत किया जा सकता है यह जानना भी जरूरी है। इसे जाग्रत करने के लिए वेद, उपनिषद, योग आदि हिन्दू ग्रंथों में अनेक उपाय बताए गए हैं। नास्त्रेदमस इसी तरह के उपायों से भविष्यवक्ता बने थे।
- मस्तिष्क के भीतर कपाल के नीचे एक छिद्र है, उसे ब्रह्मरंध्र कहते हैं, वहीं से सुषुम्ना नाड़ी सहस्त्रकार के जुड़कर रीढ़ से होती हुई मूलाधार तक गई है। इसी नाड़ी के बायीं ओर इड़ा और दायीं ओर पिंगला नाड़ी स्थित है। दोनों के बीच सुप्तावस्था में छठी इंद्री स्थित है।
- यह छठी इंद्री ही हमें हर वक्त आने वाले खतरे या भविष्य में होने वाली घटनाओं का आभास करती रहती है लेकिन कुछ लोग इसे स्पष्ट समझ लेते हैं और कुछ नहीं। यदि आप इसे समझें तो आपके साथ घटने वाली घटनाओं के प्रति ये इंद्री आपको सजग कर देगी।
- छठी इंद्री जाग्रत होने से व्यक्ति में भूत और भविष्य में झांकने की क्षमता आ जाती है। ऐसा व्यक्ति मीलों दूर बैठे व्यक्ति की बातें सुन सकता और उसे देख भी सकता है। दूसरों के मन की बात जान ही नहीं सकता बल्की उनका मन बदल भी सकता है और दूसरों की बीमारी दूर की जा सकती है।
- वैज्ञानिकों के अनुसार छठी इंद्री कल्पना नहीं, वास्तविकता है, जो हमें किसी घटित होने वाली घटना का पूर्वाभास कराती है। यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिटिश कोलंबिया के रॉन रेसिक के अनुसार छठी इंद्रिय के कारण ही हमें भविष्य में होने वाली घटनाओं का पूर्वाभास होता है।
- छठी इंद्री को जाग्रत करने का बहुत ही सरल तरीका है। तीन माह के लिए खुद को परिवार और दुनिया से काटकर आपको योग की शरण में जाना होगा। यम, नियम, प्राणायम और योगासन करते हुए लगातार ध्यान करना होगा।
- प्राणायाम सबसे उत्तम उपाय इसलिए माना जाता है क्योंकि हमारी दोनों भौहों के बीच छठी इंद्री होती है। सुषुम्ना नाड़ी के जाग्रत होने से ही छठी इंद्री जाग्रत हो जाती है। प्राणायम के माध्यम से छठी इंद्री को जाग्रत किया जा सकता है।
- मेस्मेरिज्म या हिप्नोटिज्म जैसी अनेक विद्याएं इस छठी इंद्री को जाग्रत करने का सरल और शॉर्टकट रास्ता है लेकिन इसके खतरे भी हैं। हिप्नोटिज्म को सम्मोहन कहते हैं। सम्मोहन विद्या को ही प्राचीन समय से 'प्राण विद्या' या 'त्रिकालविद्या' के नाम से पुकारा जाता रहा है।
- मन के कई स्तर होते हैं। उनमें से एक है सुक्ष्म शरीर से जुड़ा हुआ आदिम आत्म चेतन मन। यह मन हमें आने वाले रोग या खतरें का संकेत देकर उससे बचने के तरीके भी बताता है। इस मन को प्राणायाम या सम्मोहन से साधा जा सकता है।
- त्राटक क्रिया से भी इस छठी इंद्री को जाग्रत कर सकते हैं। आप बिना पलक गिराए किसी एक बिंदु, क्रिस्टल बॉल, मोमबत्ती या घी के दीपक की ज्योति पर देखते रहिए। इसके बाद आंखें बंद कर ध्यान करें। कुछ समय तक इसका अभ्यास करें। इससे धीरे-धीरे छठी इंद्री जाग्रत होने लगेगी।
- ऐसा कई बार देखा गया है कि कई लोगों ने अंतिम समय में अपनी बस, ट्रेन अथवा हवाई यात्रा को कैंसिल कर दिया और वे चमत्कारिक रूप से किसी दुर्घटना का शिकार होने से बच गए। बस यही छठी इंद्री का कमाल है। आप इसे पहचानें क्योंकि यह सभी संवेदनशील लोगों के भीतर होती है।
- यदि आपको यह आभास होता है कि पीछे कोई चल रहा है या दरवाजे पर कोई खड़ा है। कुछ होनी-अनहोनी होने वाली है या कोई खुशी का समाचार मिलने वाला है तो आप अपनी इस क्षमता पर लगातार गौर करें और ध्यान देंगे तो यह विकसित होने लगेगी। जैसे-जैसे अभ्यास गहराएगा आपकी छठी इंद्री जाग्रत होने लगेगी और आप भविष्यवक्ता बन जाएंगे।

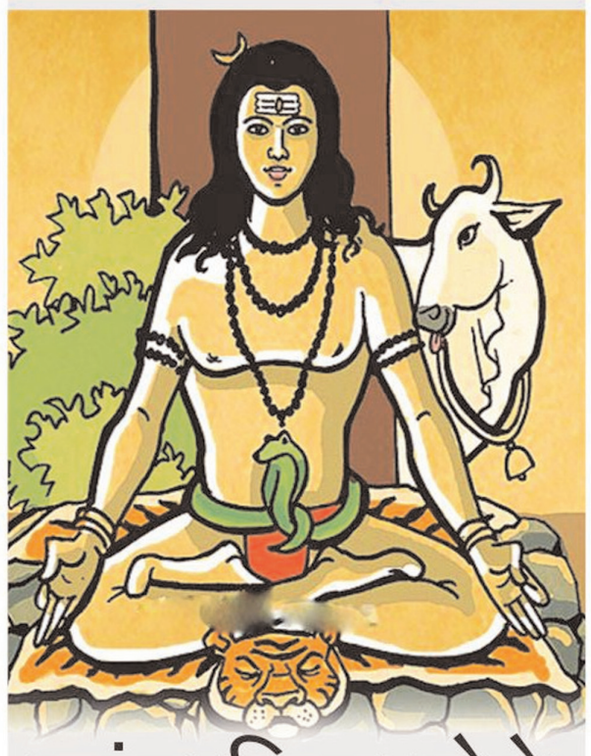

तुरंत सिद्ध होते हैं साबर मंत्र

वैदिक अथवा तांत्रोक्त अनेक ऐसे मंत्र हैं, जिसमें साधना करने के लिए अत्यंत सावधानी की जरूरत होती है। असावधानी से कार्य करने पर प्रभाव प्राप्त नहीं होता अथवा सारा श्रम व्यर्थ चला जाता है, परंतु शाबर मंत्रों की साधना या सिद्धि में ऐसी कोई आशंका नहीं होती। यह सही है कि इनकी भाषा सरल और सामान्य होती है।

माना जाता है कि लगभग सभी साबर साधनाओं और मंत्रों का अविष्कार गुरु गोरखनाथ ने किया है। यह मंत्र बहुत जल्दी ही सिद्ध भी हो जाते हैं और इनकी साधनाएं बहुत ही सरल होती हैं। ओम गुरुजी को आदेश गुरजी को प्रणाम, धरती माता धरती पिता, धरती धरे ना धीरबाजे श्रींगी बाजे तुरतुरि आया गोरखनाथमीन का पुत मुंज का छड़ा लोहे का कड़ा हमारी पीठ पीछे यति हनुमंत खड़ा, शब्द सांचा पिंड काचास्फुरो मन्त्र ईश्वरो वाचा।।

इस मन्त्र को सात बार पढ़ कर चाकू से अपने चारों तरफ रक्षा रेखा खींच ले गोलाकार, स्वयं हनुमानजी साधक की रक्षा करते हैं। शर्त यह है कि मंत्र को विधि विधान से पढ़ा गया हो। साबर मंत्रों को पढ़ने पर ऐसा कुछ भी अनुभव नहीं होता कि इनमें कुछ विशेष प्रभाव है, परंतु मंत्रों का जप किया जाता है तो असाधारण सफलता दृष्टिगोचर होती है। कुछ मंत्र तो ऐसे हैं कि जिनको सिद्ध करने की जरूरत ही नहीं है, केवल कुछ समय उच्चारण करने से ही उसका प्रभाव स्पष्ट दिखाई देने लगता है। यदि किसी मंत्र की संख्या निर्धारित नहीं है तो मात्र 1008 बार मंत्र जप करने से उस मंत्र को सिद्ध समझना चाहिए। दूसरी बात शाबर मंत्रों की सिद्धि के लिए मन में दृढ़ संकल्प और इच्छा शक्ति का होना आवश्यक है। जिस प्रकार की इच्छा शक्ति साधक के मन में होती है, उसी प्रकार का लाभ उसे मिल जाता है। यदि मन में दृढ़ इच्छा शक्ति है तो अन्य किसी भी बाह्य परिस्थितियों एवं कुविचारों का उस पर प्रभाव नहीं पड़ता।

9 प्रमुख मणियां किस मणि को धारण करने से क्या होता है

आपने पारस मणि, नागमणि, कौस्तुभ मणि, चंद्रकांता मणि, नीलमणि, स्यमंतक मणि, स्फटिक मणि आदि का नाम तो सुना ही होगा, परंतु ही यहां निम्नलिखित नौ मणियों की बात कर रहे हैं- घृत मणि, तैल मणि, भीष्मक मणि, उपलक मणि, स्फटिक मणि, पारस मणि, उलूक मणि, लाजावर्त मणि, मासर मणि। आओ जानते हैं कि इन मणियों को धारण करने से क्या होता है। हालांकि यह सभी बातें मान्यता पर आधारित हैं।

- घृत मणि की माला धारण कराने से बच्चों को नजर से बचाया जा सकता है।
- स्फटिक मणि को धारण करने से कभी भी लक्ष्मी नहीं रूठती।
- तैल मणि को धारण करने से बल-पौरूष की वृद्धि होती है।
- भीष्मक मणि धन-धान्य वृद्धि में सहायक है।
- उपलक मणि को धारण करने वाला व्यक्ति भक्ति व योग को प्राप्त करता है।
- उलूक मणि को धारण करने से नेत्र रोग दूर हो जाते हैं।
- लाजावर्त मणि को धारण करने से बुद्धि में वृद्धि होती है।
- मासर मणि को धारण करने से पानी और अग्नि का प्रभाव कम होता है।

तेलमणि को धारण करने से होती हैं सभी मनोकामनाएं पूर्ण

आपने पारस मणि, नागमणि, कौस्तुभ मणि, चंद्रकांता मणि, नीलमणि, स्यमंतक मणि, स्फटिक मणि आदि का नाम तो सुना ही होगा, परंतु ही यहां निम्नलिखित नौ मणियों की बात कर रहे हैं- घृत मणि, तैल मणि, भीष्मक मणि, उपलक मणि, स्फटिक मणि, पारस मणि, उलूक मणि, लाजावर्त मणि, मासर मणि। आओ जानते हैं कि तेलमणि को धारण करने से क्या होता है। हालांकि यह सभी बातें मान्यता पर आधारित हैं।

- तेलमणि को उदउक, उदोक भी कहते हैं और अंग्रेजी में टूर्मेलीन कहा जाता है।
- लाल रंग की आभा लिए हुए श्वेत, पीत व कृष्ण वर्ण की होती है तेलमणि और स्पर्श करने से तेल जैसा चिकना ज्ञात होता है।
- कहते हैं कि श्वेत रंग की तेलमणि को अग्नि में डालने पर ही पीत वर्ण की तथा कपड़े में लपेट कर रखने पर तीसरे दिन पीत वर्ण की हो जाती है। लेकिन बाहर निकालकर हवा में रखने से कुछ समय बाद ही यह पुनः अपने असली रंग में बदल जाती है।
- इस मणि को धारण करने से भक्ति भाव, वैराग्य तथा आत्म ज्ञान प्राप्त होकर सभी तरह की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं।
- कहते हैं कि रोहिणी नक्षत्र, पूर्णिमा या मंगलवार के दिन तेलमणि को जिस खेत में 4-5 हाथ गहरे गड्ढे में खोदकर दबा दिया जाए और मिट्टी से ढंककर सींचा जाए तो सामान्य से बहुत अधिक अन्न उत्पन्न होता है।

इन कारणों से दिखाई देते हैं हमें अच्छे या बुरे सपने

मनोविज्ञान, आयुर्वेद, ज्योतिष और योग में अच्छे या बुरे सपने दिखाई देने के कई कारण बताए गए हैं। जब हम कोई स्वप्न देखते हैं तो जरूरी नहीं कि प्रत्येक सपने का अच्छा या बुरा फल होता है। आओ जानते हैं कि सपने किन कारणों से दिखाई देते हैं।

अधिकतर सपने हमें हमारी दिनचर्या में किए गए कार्य से प्राप्त होते हैं। कार्य का अर्थ हमने जो देखा, सुनना, समझा, इच्छा किया और भोगा वह हमारे चित में विराजित होकर रात में स्वप्नों के रूप में दिखाई देता है। यह सब बदले स्वरूप में इसलिए भी होते हैं क्योंकि वे हमारे शरीर में स्थित भोजन और पानी की स्थिति और अवस्था से भी संचालित होते हैं। निम्नलिखित बातों से आप समझ सकते हैं। इन कारणों से दिखाई देते हैं स्वप्न :-

- दृष्ट- जो जाग्रत अवस्था में देखा गया हो उसे स्वप्न में देखना।
- श्रुत- सोने से पूर्व सुनी गई बातों को स्वप्न में देखना।
- अनुभूत- जो जागते हुए अनुभव किया हो उसे देखना।
- प्रार्थित- जाग्रत अवस्था में की गई प्रार्थना की इच्छा को स्वप्न में देखना।
- दोषजन्य- वात, पित्त आदि दूषित होने से स्वप्न देखना।
- भाविक- जो भविष्य में घटित होना है, उसे देखना।

अतः अब आप जान सकते हैं कि आपने जो सपने देंखे हैं वे किस श्रेणी के हैं। इससे आप यह भी अनुमान लगा सकते हैं कि आपका सपना शुभ होगा या अशुभ।

हिन्दू धर्म में सफेद वस्त्र का क्या है महत्व

हिन्दू धर्म में सफेद वस्त्र का बहुत महत्व है। सफेद रंग हर तरह से शुभ माना गया है, लेकिन वक्त के साथ लोगों ने इस रंग का मांगलिक कार्यों में इस्तेमाल बंद कर दिया। हालांकि प्राचीनकाल में सभी तरह के मांगलिक कार्यों में इस रंग के वस्त्रों का उपयोग किया जाता था। यह रंग शांति, शुभता, पवित्रता और मोक्ष का रंग है।

लक्ष्मी का वस्त्र : सच तो यह है कि सफेद रंग सभी रंगों में अधिक शुभ माना गया है इसीलिए कहते हैं कि लक्ष्मी हमेशा सफेद कपड़ों में निवास करती है।

मांगलिक वस्त्र : 20-25 वर्षों पहले तक लाल जोड़े में सजी दुल्हन को सफेद ओढ़नी ओढ़ाई जाती थी। इसका यह मतलब कि दुल्हन ससुराल में पहला कदम रखे तो उसके सफेद वस्त्रों में लक्ष्मी का वास हो। आज भी ग्रामीण क्षेत्र में सफेद ओढ़नी की परंपरा का पालन किया जाता है।

यज्ञकर्ता का वस्त्र : प्राचीन काल में जब भी यज्ञ किया जाता था तो पुरुष और महिला दोनों ही सफेद वस्त्र ही धारण करके बैठते थे। पुरोहित वर्ग इसी तरह के वस्त्र पहनकर यज्ञ करते थे। दूसरी ओर आज भी किसी भी सम्मान समारोह आदि में सफेद कुर्ता और धोती पहनने का रिवाज है।

विधावा का वस्त्र : यदि किसी का पति मर गया तो उसे विधवा और किसी की पत्नी मर गई है तो उसे विधुर कहा जाता है। शास्त्रों के अनुसार पति की मृत्यु के नौवें दिन उसे दुनियाभर के रंगों को त्यागकर सफेद साड़ी पहननी होती है, वह किसी भी प्रकार के आभूषण एवं श्रृंगार नहीं कर सकती। स्त्री को उसके पति के निधन के कुछ सालों बाद तक केवल सफेद वस्त्र ही पहनने होते हैं और उसके बाद यदि वह रंग बदलना चाहे तो बेहद हल्के रंग के वस्त्र पहन सकती है। मध्यकाल में हिन्दू धर्म में कई तरह की बुराइयां सम्मलित हुई उसमें एक यह भी थी कि कोई स्त्री यदि विधवा हो जाती थी तो वह दूसरा विवाह नहीं कर पाती थी। हालांकि आज भी उत्तर भारत के ग्रामीण इलाकों में विधवा विवाह का प्रचलन है जिसे नाता कहा जाता है। कोई स्त्री पुनर्विवाह का निर्णय लेती है, तो इसके लिए वह स्त्रतंत्र है। आज समाज का स्वरूप बदल रहा है। विधवाएं रंगीन वस्त्र भी पहन रही है और शादी भी कर रही हैं। वेदों में एक विधवा को सभी अधिकार देने एवं दूसरा विवाह करने का अधिकार भी दिया गया है। वेदों में एक कथन शामिल है-

'उदीरष्व नार्यभि जीवलोकं
गतासुमेतमुप शेष एहि।
हस्तग्राभस्य दिधिषोस्तवेदं
पत्युर्जनित्वमभि सम्बभूथ।'

अर्थात पति की मृत्यु के बाद उसकी विधवा उसकी याद में अपना सारा जीवन व्यतीत कर दे, ऐसा कोई धर्म नहीं कहता। उस स्त्री को पूरा अधिकार है कि वह आगे बढ़कर किसी अन्य पुरुष से विवाह करके अपना जीवन सफल बनाए। चार कारणों से विधवा महिलाओं को सफेद वस्त्र दिए गए। पहला यह कि यह रंग कोई रंग नहीं बल्कि रंगों के अनुपस्थिति है। मतलब यह कि अब जीवन में कोई रंग नहीं बचा। दूसरा यह कि इससे महिला की एक अलग पहचान बन जाती है और लोग उसे सहानुभूति एवं संवेदना रखते हैं। तीसरा यह कि सफेद रंग आत्मविश्वास, सात्विक और शांति का रंग है। इसके साथ ही सफेद वस्त्र विधवा स्त्री को प्रभु में अपना ध्यान लगाने में मदद करते हैं। चौथा कराण यह कि इससे महिला का कहीं ध्यान नहीं भटकता है और उसे हर वक्त इसका अहसास होता है कि वह पवित्र है। पांचवां कारण यह कि यदि महिला के कोई पुत्र या पुत्री है तो वह अपने भीतर नैतिकता और जिम्मेदारी का अहसास करती रहे ताकि वह दूसरा विवाह नहीं करें। दोबारा शादी नहीं करने से पुत्र पुत्रियों के जीवन पर विपरित या प्रतिकुल असर नहीं पड़ता है।

राष्ट्रीय/अंतरराष्ट्रीय
प्रमुख समाचार

दिल्ली पुलिस के 79वें स्थापना दिवस परेड में शामिल हुए शाह

नईदिल्ली। सोमवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह दिल्ली पुलिस के 79वें स्थापना दिवस परेड में समारोह में पहुंचे। यहां उन्होंने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा आने वाले समय में देश में तीन नए आपराधिक कानून लागू हो जाएंगे। इससे देश में आपराधिक मामलों में सजा की दर 80 फीसदी बढ़ जाएगी। उन्होंने कहा माओवादी हिंसा के खिलाफ लड़ाई अपने आखिरी दौर में है और इस वर्ष मार्च तक यह खतरा हमेशा के लिए खत्म होने का भरोसा जताया। उन्होंने आगे बताया कि पिछले 11 वर्षों में देश ने बहुत कुछ हासिल किया है। इसमें ये तीन नए न्याय आधारित आपराधिक कानून भी शमिल हैं। यह कानून लागू होने के बाद मामलों का निपटारा करने और सजा की दर को बढ़ाने में मददगार साबित होंगे। गृह मंत्री ने तीन नए आपराधिक कानूनों भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम का जिक्र भी किया।

केरल चुनाव से पहले अय्यर ने कराई कांग्रेस की किरकिरी

तिरुवनंतपुरम। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री मणिशंकर अय्यर ने विश्वास जताया है कि पिनारयी विजयन केरल के मुख्यमंत्री बने रहेंगे। उनका यह बयान ऐसे समय आया है जब कांग्रेस पार्टी राज्य में आगामी विधानसभा चुनावों की तैयारियों में जुटी है। अय्यर ने यह टिप्पणी रविवार को विजन 2031: विकास और लोकतंत्र शीर्षक वाले अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन में बोलते हुए की, जिसका उद्घाटन स्वयं मुख्यमंत्री पिनारयी विजयन ने किया। अपने संबोधन में अय्यर ने विजयन की प्रशंसा की और सुझाव दिया कि पंचायती राज व्यवस्था में केरल की स्थिति को मजबूत करने के लिए संशोधन किए जाने चाहिए। उन्होंने इस बात पर भी सुझाव दिए कि राज्य स्थानीय प्रशासन में अपनी अग्रणी भूमिका को कानूनी रूप से कैसे सुरक्षित कर सकता है। मुख्यमंत्री की उपस्थिति में जो मुझे पूरा विश्वास है कि अगले मुख्यमंत्री होंगे। कांग्रेस का कहना है कि अय्यर किसी पद पर नहीं हैं। अय्यर की टिप्पणी से कांग्रेस में बेचैनी फैल गई।

कांग्रेस असम इकाई के पूर्व अध्यक्ष भूपेन ने दिया इस्तीफा

नई दिल्ली। असम विधानसभा चुनाव 120 दिन के बाद होने वाला है। इस बीच पूर्वोत्तर राज्य असम में राहुल गांधी को बड़ा झटका लगा है। सूत्रों के हवाले से सोमवार को बताया कि असम प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पूर्व अध्यक्ष रिपुन बोरा ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। बोरा असम में कांग्रेस का एक प्रमुख चेहरा रहे हैं। राज्यसभा सांसद भी रह चुके हैं। पार्टी नेतृत्व को अपने इस फैसले से अवगत करा दिया है, हालांकि उनके इस्तीफे के कारणों की अभी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। ऐसी संभावना है कि बीजेपी में शामिल हो सकते हैं? उनका इस्तीफा ऐसे समय में आया है जब कांग्रेस आगामी राजनीतिक मुकाबलों से पहले पूर्वोत्तर में अपनी रणनीति को नए सिरे से तैयार कर रही है। सूत्रों के अनुसार, बोरा ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे को अपना त्यागपत्र भेज दिया है। खरगे को लिखे पत्र में उन्होंने दावा किया है कि पार्टी नेतृत्व द्वारा उनकी अनदेखी की जा रही है और उन्हें उचित स्थान नहीं दिया जा रहा है।

कांग्रेस नेता का भाजपा पर टीपू सुल्तान को लेकर बड़ा हमला

नईदिल्ली। छत्रपति शिवाजी महाराज और टीपू सुल्तान पर उनकी टिप्पणियों को लेकर चल रहे विवाद के बीच, महाराष्ट्र कांग्रेस प्रमुख हर्षवर्धन सपकाल ने दावा किया कि भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) बुनियादी मुद्दों और एपस्टीन फाइलों की सामग्री से ध्यान भटकाने के लिए उनके बयानों की आलोचना कर रही है। राज्य कांग्रेस प्रमुख को छत्रपति शिवाजी महाराज और 18वीं शताब्दी के मैसूर शासक टीपू सुल्तान की वीरता की तुलना करने पर भाजपा की ओर से भारी आलोचना का सामना करना पड़ा। सपकाल ने रविवार को कहा कि उन्होंने भाजपा पर शरारत करने का आरोप लगाते हुए अपने पहले के बयान पर स्पष्टीकरण दे दिया है। उन्होंने कहा कि भाजपा मेरे बयान को लेकर जहर उगल रही है। मैं विनम्रतापूर्वक और उतने ही गर्व के साथ उन्हें स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं कि उन्हें शिवाजी महाराज के बारे में हमें सिखाने की जरूरत नहीं है।

डेरेक ओ ब्रायन ने प्रधानमंत्री मोदी पर साधा निशाना

कोलकाता। तृणमूल कांग्रेस के नेता डेरेक ओ ब्रायन ने सोमवार को पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए खोखले शब्द का इस्तेमाल किया। राज्यसभा में टीएमसी नेता ने भी प्रधानमंत्री पर तंज कसते हुए उन्हें टेलीप्रॉम्प्टर टाइकून कहा। उन्होंने कहा पीएम मोदी, उर्फ टेलीप्रॉम्प्टर टाइकून, जो संसद में बोलने से भागते हैं, उनके और भी खोखले शब्द हैं। लोकसभा ने हाल ही में खत्म हुए बजट सेशन के दौरान विपक्षी सदस्यों की लगातार नारेबाजी के बीच प्रधानमंत्री के हमेशा की तरह जवाब के बिना ही मोशन ऑफ थैंक्स पास कर दिया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने बाद में कहा कि उनके पास पक्की जानकारी है कि कांग्रेस के कई सदस्य प्रधानमंत्री मोदी की सीट की ओर बढ़ सकते हैं। जिसके चलते उन्होंने पीएम से राष्ट्रपति के भाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा का जवाब देने के लिए सदन में न आने का अनुरोध किया था। मोदी ने राज्यसभा में धन्यवाद प्रस्ताव पर बहस का जवाब दिया था।

भारत मंडपम में जुटेंगे दुनिया के टेक दिग्गज

सुंदर पिचाई, बिल गेट्स, सैम ऑल्टमैन समेत कई हस्तियां होंगी शामिल

नई दिल्ली। इस हफ्ते नई दिल्ली में आयोजित होने जा रहे इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 में पूरी दुनिया की नजर रहेगी। ब्रिटेन, दक्षिण कोरिया और फ्रांस के बाद इस साल भारत इस वैश्विक मंच की मेजबानी कर रहा है। इस आयोजन से यह साबित होता है कि वैश्विक बाजार में भारत की अहमियत अब पहले से कहीं ज्यादा बढ़ गई है। नई दिल्ली के भारत मंडपम और सुषमा स्वराज भवन समेत कई स्थलों में समिट का आयोजन 16 से 20 फरवरी तक किया जाएगा। इस इवेंट में 100 से ज्यादा देशों की भागीदारी होगी, जिनमें 30 से अधिक देशों की 300 से ज्यादा कंपनियां अपनी तकनीकों का प्रदर्शन करेंगी।

एआई इम्पैक्ट समिट में ग्लोबल टेक इंडस्ट्री की कई प्रमुख और प्रभावशाली हस्तियां शामिल होने जा रही है-

सुंदर पिचाई- सीईओ, गूगल और अल्फाबेट, सैम ऑल्टमैन - सीईओ, ओपनएआई, मुकेश डी अंबानी - चेयरमैन एवं प्रबंध निदेशक, रिलायंस इंडस्ट्रीज, बिल गेट्स - चेयर, गेट्स फाउंडेशन, सर डेमिस हैसबिस - सह-संस्थापक एवं सीईओ, गूगल डीपमाइंड, यान लेकुन - प्रोफेसर, न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी (एनवाईयू) एवं एग्जीक्यूटिव चेयरमैन, एएमआई लैब्स, योशुआ बेंगियो - संस्थापक एवं चेयर, मिला इंस्टीट्यूट, डारियो अमोडेई - सीईओ, एंथ्रोपिक, क्रिस्टियानो आमोन - सीईओ, क्वालकॉम, ब्रैड स्मिथ - प्रेसिडेंट एवं वाइस चेयर, माइक्रोसॉफ्ट, जूली स्वीट - चेयर एवं सीईओ, एक्सेंचर, जय पुरी - एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट, एनवीडिया, एन. चंद्रशेखरन - चेयरमैन, टाटा संस, के. कृतिवासन - सीईओ एवं प्रबंध निदेशक, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज (टीसीएस), सी. विजयकुमार - सीईओ एवं प्रबंध निदेशक, एचसीएल टेक, सलील पारेख - सीईओ एवं प्रबंध निदेशक, इंफोसिसश अरुंधति भट्टाचार्य - चेयरपर्सन एवं सीईओ, सेल्सफोर्स इंडिया, नीकेश अरोड़ा - चेयरमैन एवं सीईओ, पालो ऑल्टो नेटवर्क्स, शांतनु नारायण - चेयर एवं सीईओ, एडोबी, रॉय जैकोब्स - सीईओ, रॉयल फिलिप्स, बोर्ये एकहोम - प्रेसिडेंट एवं सीईओ, एरिक्सन, मार्टिन श्रोएटर - चेयरमैन एवं सीईओ, काइंड्रिल, मैथ्यू प्रिंस - सीईओ, क्लाउडफ्लेयर, जय चौधरी - सीईओ एवं संस्थापक, ज़ीस्केलर, विशाल सिक्का - संस्थापक एवं सीईओ, वियानाई सिस्टम्स, रवि कुमार एस - सीईओ, कॉग्निजेंट, नंदन नीलेकणि - सह-संस्थापक एवं चेयरमैन इंफोसिस,

सुनील भारती मित्तल - संस्थापक एवं चेयरमैन भारती एंटरप्राइजेज, टोनी ब्लेयर - एग्जीक्यूटिव चेयरमैन, टोनी ब्लेयर इंस्टीट्यूट फॉर ग्लोबल चेंज, एलेक्जेंडर वांग - चीफ एआई ऑफिसर, मेटा, आर्थर मेंश - सह-संस्थापक एवं सीईओ, मिस्ट्राल एआई, बिपुल सिन्हा - सीईओ एवं सह-संस्थापक, रुब्रिक, बोर्ये ब्रेंडे - प्रेसिडेंट एवं सीईओ, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, अमित जावेरी - प्रेसिडेंट एवं सीओओ, सर्विसनाउ, एना पाउला असिस - सीनियर वाइस प्रेसिडेंट एवं चेयर (एशिया पैसिफिक और ईएमईए) आईबीएम, अपर्णा बावा - सीओओ, जूम, बीवीआर मोहन रेड्डी - संस्थापक एवं चेयरमैन, साइएंट लिमिटेड।

हालांकि, एनवीडिया के सीईओ जेन्सन हुआंग, जिनके आने की पूरी उम्मीद थी, लेकिन उन्होंने आखिरी समय में कुछ कारणों के वजह से अपना दौरा रद्द कर दिया। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समिट में टेक लीडर्स का स्वागत करेंगे। टेक दिग्गजों के अलावा, इवेंट में 20 देशों के राष्ट्राध्यक्ष भी शामिल होगें, जिनमें फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों और ब्राजील के राष्ट्रपति लुला डी सिल्वा शामिल हैं।

पिछले कुछ वर्षों में मोदी सरकार ने साफ संकेत दिए हैं कि वह भारत को वैश्विक टेक सुपरपावर बनाना चाहती है। सरकार ने 18 अरब डॉलर (16 लाख करोड़ रुपये) से अधिक के सेमीकंडक्टर प्रोजेक्ट्स को मंजूरी दी है, ताकि देश में चिप निर्माण और सप्लाई चेन मजबूत हो सके। इसी का नतीजा है कि माइक्रोसॉफ्ट ने भारत में एआई इन्फ्रास्ट्रक्चर के लिए 17.5 अरब (करीब 1.45 लाख करोड़ रुपये) के निवेश का वादा किया है। वहीं, सरकार डेटा सेंटर्स को 21 साल की टैक्स छूट दे रही है, जिससे एनवीडिया जैसी कंपनियां यहां निवेश के लिए उत्साहित हैं।

हाल ही के कुछ वर्षों में स्टार्टअप्स में वेंचर कैपिटल निवेश बढ़ रहा है और भारतीय शेयर बाजार में आईपीओ की संख्या में उछाल देखा जा रहा है। एआई कंपनी एंथ्रोपिक ने भारत में अपने संचालन के लिए पूर्व माइक्रोसॉफ्ट इंडिया प्रमुख इरीना घोष को नियुक्त किया है। ओपन एआई ने भी भारत में अलग सेल्स डिवीजन शुरू किया है। गूगल ने सरकार और फिजिक्स वाला के साथ मिलकर शिक्षा में एआई को बढ़ावा देने की साझेदारी की है।

यह समिट सिर्फ बंद कमरों की मीटिंग तक सीमित नहीं है। यह समिट में लगने वाला एक्सपो 70,000 वर्ग मीटर में फैला होगा, जिसमें 30 देशों की 300 से ज्यादा कंपनियां अपनी तकनीक का प्रदर्शन करेंगी। खास बात यह है कि इस आयोजन में किसानों और जमीनी स्तर पर काम करने वाले लोगों को भी जोड़ा गया है। समिट के लिए अब तक दो लाख से ज्यादा लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया है।

एआई क्रांति में दुनिया का नेतृत्व कर रहा है भारत, पीएम मोदी का संदेश

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने सोमवार को विश्वास जताया कि 1.4 अरब भारतीयों की शक्ति के साथ भारत वैश्विक स्तर पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) के क्षेत्र में आ रहे बदलावों का नेतृत्व कर रहा है। दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित होने वाले 'इंडिया एआई इम्पैक्ट एक्सपो' 2026 के उद्घाटन से पहले पीएम मोदी ने कहा कि एआई के क्षेत्र में भारत की प्रगति महत्वाकांक्षा और दायित्व दोनों का प्रतिबिंब है। मोदी की यह टिप्पणी उस दिन आई है जब वह यहां भारत मंडपम में 'इंडिया एआई इम्पैक्ट एक्सपो' 2026 का उद्घाटन करने वाले हैं। 'इंडिया एआई इम्पैक्ट एक्सपो' 2026 का आयोजन 16 से 20 फरवरी तक भारत मंडपम में 'इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट' के साथ किया जाएगा। मोदी ने 'एक्स' पर एक पोस्ट में कहा, '' एआई पर चर्चा करने के लिए दुनिया को एक साथ ला रहे हैं! आज से, भारत दिल्ली के भारत मंडपम में एआई इम्पैक्ट समिट की मेजबानी कर रहा है। मैं इस शिखर सम्मेलन में दुनिया भर के नेताओं, उद्योगपतियों, नवोन्मेषकों, नीति निर्माताओं, शोधकर्ताओं और प्रौद्योगिकी प्रेमियों का हार्दिक स्वागत करता हूं।'' उन्होंने कहा कि शिखर सम्मेलन का विषय ''सर्वजन हिताय, सर्वजन सुखाय'' है, जो मानव-केंद्रित प्रगति के लिए कृत्रिम मेधा का उपयोग करने की ''हमारी साझा प्रतिबद्धता'' को दर्शाता है।

राहुल को संसद चलाने में रूचि नहीं: रिजिजू

एनजीओ ने सिखाया- कांग्रेस के अच्छे दिन आएंगे, लेकिन...

नई दिल्ली। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने एक बार फिर एनजीओ का हवाला देते हुए लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी को घेरा है। रिजिजू ने कहा कि लोकसभा में विपक्ष के नेता संसद के सुचारू संचालन में रुचि नहीं रखते। इतना ही नहीं रिजिजू ने अपने बयान में कहा कि कुछ गैर सरकारी संगठनों (एनजीओ) ने उन्हें सिखाया है कि उनकी पार्टी के लिए %अच्छे दिन% आएंगे और इसीलिए वे सदन को बाधित कर रहे हैं।

किरेन रिजिजू ने यह भी कहा कि सरकार संसद में स्थिति को शांत करने के लिए कांग्रेस को लेकर कोई और अतिरिक्त कदम नहीं उठाने जा रही है, क्योंकि उन्होंने सदन के सुचारू रूप से चलने के लिए %कई प्रयास% किए थे, लेकिन वे व्यर्थ रहे। न्यूज एजेंसी पीटीआई को दिए एक साक्षात्कार में किरेन रिजिजू ने संसद में चले गतिरोध और राहुल गांधी को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी।

उन्होंने कहा, %राहुल गांधी को सदन चलाने में कोई दिलचस्पी नहीं है। उन्हें सिर्फ मुद्दे बनाने में दिलचस्पी है। कुछ गैर सरकारी संगठनों ने राहुल गांधी को सिखाया है कि तुम्हारा समय आएगा, लेकिन उनका समय नहीं आएगा। अगले चुनावों में लोकसभा में उनकी सीटों की संख्या और भी कम हो जाएगी।% उन्होंने कहा कि कांग्रेस हताश है, क्योंकि पार्टी लगातार चुनाव हार रही है। वे स्थिति को बदलने के लिए बेताब हैं।

अरुणाचल पश्चिम स्थित अपने लोकसभा क्षेत्र के दौरे पर गए रिजिजू ने कहा कि एनडीए को विपक्ष के सदन को बाधित करने से कोई समस्या नहीं है, क्योंकि उन्होंने वरिष्ठ कांग्रेस नेता केसी वेणुगोपाल और कुछ अन्य लोगों से बात करने सहित स्थिति को शांत करने के कई प्रयास किए थे। केंद्रीय मंत्री ने दावा किया कि संसद में छोटी पार्टियों द्वारा कांग्रेस पर सदन को बाधित न करने का दबाव था।

केंद्रीय मंत्री ने दावा किया कि संसद में छोटी पार्टियों की तरफ से कांग्रेस पर दबाव था कि वह सदन में रुकावट न डाले, क्योंकि इससे उन्हें बोलने का समय नहीं मिलता। उन्होंने कहा, %सारा विपक्ष कांग्रेस के साथ नहीं है। छोटी पार्टियां अपनी-अपनी पार्टी के समय का इस्तेमाल नहीं कर पा रही हैं। छोटी पार्टियां राहुल गांधी से नाखुश हैं। उनमें से कुछ ने तो स्पीकर के खिलाफ प्रस्ताव पर साइन भी नहीं किया।

रिजिजू ने कहा कि अन्य राजनीतिक दलों के कुछ सदस्य उनसे लगातार कह रहे थे कि वे चाहते हैं कि सदन का कामकाज जारी रहे। बता दें कि लोकसभा में बजट सत्र के पहले भाग के अधिकांश दिनों में व्यवधान और स्थगन देखने को मिले, जब अध्यक्ष ने गांधी को पूर्व सेना प्रमुख एमएम नरवणे के %अप्रकाशित संस्मरण% के अंशों पर आधारित एक लेख का हवाला देने से रोक दिया, जिसमें 2020 के भारत-चीन संघर्ष का जिक्र है। सदन में अनुशासनहीन व्यवहार के लिए विपक्ष के आठ सदस्यों को बजट सत्र के शेष समय के लिए निलंबित कर दिया गया है। वहीं विपक्ष ने स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव भी पेश किया और उन्हें पद से हटाने की मांग करते हुए आरोप लगाया कि उन्होंने 卐स्पष्ट रूप से पक्षपातपूर्ण卐 तरीके से काम किया है। अब संसद का सत्र 9 मार्च को फिर से शुरू होगा और 2 अप्रैल को समाप्त होगा।

खेल
प्रमुख समाचार

अफगानिस्तान ने विश्व कप में यूएई को 5 विकेट से हराया

नई दिल्ली। सलामी बल्लेबाज इब्राहिम जादरान और अजमातुल्लाह ओमरजई की शानदार बल्लेबाजी से अफगानिस्तान ने यूएई को पांच विकेट से हराया। अफगानिस्तान ने इस तरह टी20 विश्व कप में जीत का खाता खोला और सुपर आठ चरण के लिए अपनी उम्मीदें जीवंत रखी है। यूएई ने पहले बल्लेबाजी करते हुए सोहेब खान के अर्धशतक की मदद से 20 ओवर में नौ विकेट पर 160 रन बनाए। जवाब में अफगानिस्तान ने 19.2 ओवर में पांच विकेट पर 162 रन बनाकर मैच जीता।

अफगानिस्तान और यूएई के बीच मैच के बाद ग्रुप डी की अंक तालिका का हाल बदल गया है। अफगानिस्तान की टीम तीन मैचों में दो अंक लेकर तीसरे स्थान पर पहुंच गई है, जबकि यूएई की टीम भी इतने मैचों में समान अंक लेकर चौथे स्थान पर खिसक गई है।

लक्ष्य का पीछा करने उतरे अफगानिस्तान ने मैच की दूसरी ही गेंद पर रहमानुल्लाह गुरबाज (00) का विकेट गंवा दिया जिन्होंने जुनैद की गेंद पर शोएब को कैच थमाया। जादरान ने चौथे ओवर में हैदर अली को निशाना बनाते हुए उनके ओवर में तीन चौकों और एक छक्के से 18 रन जुटाए। गुलबदिन नईब (13) ने भी मोहम्मद जवादुल्लाह पर छक्का और चौका मारा लेकिन अगले ओवर में मोहम्मद अरफान की गेंद को प्वाइंट पर हर्षिक कौशिक को कैच दे बैठे।

अफगानिस्तान ने पावरप्ले में दो विकेट पर 41 रन बनाए। सेदिकुल्लाह अटल (16) ने अरफान पर चौके के साथ आठवें ओवर में टीम के रनों का अर्धशतक पूरा किया और फिर अगले ओवर में सिमरनजीत सिंह पर छक्का जड़ा लेकिन जवादुल्लाह ने यॉर्कर पर उनके विकेट उखाड़ दिए। जादरान ने सिमरनजीत पर चौके और फिर दो रन के साथ 37 गेंद में अर्धशतक पूरा किया।

आर्थिक/वाणिज्य/विज्ञान/
प्रमुख समाचार

सेंसेक्स 650 अंक चढ़ा निफ्टी 25682 पर बंद

नईदिल्ली। एशियाई बाजारों से मिलेजुले रुख के बीच भारतीय शेयर बाजार हफ्ते के पहले ट्रेडिंग सेशन यानी सोमवार (16 फरवरी) को बढ़त में बंद हुए। सपाट शुरुआत के बाद कारोबार के दूसरे हाफ में निचले स्तर पर खरीदारी से बाजार को सपोर्ट मिला। इससे पहले शुरुआती कारोबार में सीमित दायरे में कारोबार देखने को मिला। तीस शेयरों वाला बीएसई सेंसेक्स गिरावट के साथ 82,480 अंक पर खुला। खुलने के बाद इंडेक्स में सीमित दायरे में कारोबार दिखा। लेकिन अंत में 650.39 अंक या 0.79 प्रतिशत की बढ़त लेकर 83,277.15 पर बंद हुआ। इसी तरह, नैशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी-50 भी गिरावट लेकर 25,423.60 पर था। शुरुआत में इंडेक्स लाल और हरे निशान के बीच डोलता रहा। लेकिन अंत में 211.65 अंक या 0.83 प्रतिशत की बढ़त के साथ 25,682 पर बंद हुआ।

जनवरी में बढ़ी थोक मूल्य मुद्रास्फीति, 1.81% पर पहुंची

नई दिल्ली। सरकारी आंकड़ों के अनुसार थोक मूल्य सूचकांक आधारित महंगाई दर में लगातार तीसरे महीने में बढ़ोतरी दर्ज की गई। जनवरी 2026 में यह 1.81 प्रतिशत रही। यह वृद्धि खाद्य वस्तुओं, गैर-खाद्य वस्तुओं और विनिर्मित उत्पादों की कीमतों में महीने-दर-महीने आई तेजी के कारण हुई। पिछले वर्ष जनवरी में डब्ल्यूपीआई महंगाई 2.51% थी, जबकि दिसंबर 2025 में यह 0.83 प्रतिशत दर्ज की गई थी। उद्योग मंत्रालय के बयान के मुताबिक जनवरी 2026 में सकारात्मक महंगाई दर का मुख्य कारण बेसिक मेटल, अन्य विनिर्माण, गैर-खाद्य वस्तुओं, खाद्य पदार्थों और वस्त्रों की कीमतों में बढ़ोतरी रहा। विश्व खाद्य प्रौद्योगिकी आयोग (डब्ल्यूपीआई) के आंकड़ों के अनुसार, जनवरी में खाद्य पदार्थों की मुद्रास्फीति 1.55 प्रतिशत थी, जबकि दिसंबर में यह 0.43 प्रतिशत थी।

देश का चीनी निर्यात 2025-26 में फरवरी तक 2.01 लाख टन

नई दिल्ली। भारत ने चालू वर्ष 2025-26 के विपणन वर्ष में फरवरी तक 2,01,547 टन चीनी का निर्यात किया। इसमें संयुक्त अरब अमीरात शीर्ष निर्यात गंतव्य रहा। अखिल भारतीय चीनी व्यापार संघ (एआईएसटीए) ने सोमवार को यह जानकारी दी। चीनी निर्यात पर सरकार का नियंत्रण बना हुआ है जिसके तहत मिल के बीच आनुपातिक रूप से कोटा वितरित किया जाता है। केंद्र सरकार ने 2025-26 विपणन वर्ष (अक्टूबर-सितंबर) के लिए कुल 20 लाख टन निर्यात को मंजूरी दी है जिसमें हाल ही में स्वीकृत अतिरिक्त पांच लाख टन भी शामिल है। एआईएसटीए ने बयान में कहा कि कुल निर्यात में सफेद चीनी की हिस्सेदारी 163,000 टन रही जबकि परिष्कृत चीनी की हिस्सेदारी 37,638 टन थी। संयुक्त अरब अमीरात को सबसे अधिक 47,006 टन चीनी निर्यात की गई। इसके बाद अफगानिस्तान को 46,163 टन चीनी निर्यात हुई।

एआई से खत्म हो जाएगा आईटी फर्म्स का दबदबा?

नईदिल्ली। निफ्टी आईटी इंडेक्स 2026 में अब तक करीब 15 प्रतिशत गिर चुका है। यह साल 2025 में आईटी इंडेक्स में आई 12.6 प्रतिशत गिरावट से भी ज्यादा है। हालिया गिरावट के बाद फरवरी में आईटी सेक्टर की 10 कंपनियों का कुल मार्केट कैप 50 अरब डॉलर से ज्यादा घट गया। आईटी शेयरों का भारतीय बाजार में करीब 10 प्रतिशत हिस्सा है और इनका असर निफ्टी और सेंसेक्स जैसे बड़े इंडेक्स पर काफी ज्यादा पड़ता है। जानकारों का कहना है कि निवेशकों को चिंता है कि भारतीय आईटी कंपनियां अपनी कमाई और प्रोडक्टिविटी बनाए रख पाएंगी या नहीं। ऐसा इसलिए क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कारण काम ऑटोमेट हो सकता है और प्रोजेक्ट जल्दी पूरे हो सकते हैं। ये घरेलू आईटी कंपनियों के बिजनेस मॉडल के लिए बड़ी चुनौती है।

रूसी तेल से टैरिफ तक, भारत-अमेरिका व्यापार डील पर बड़े सवाल

पी. चिदंबरम

एक बड़ा प्रश्न है कि 6 फरवरी, 2026 को भारत और अमेरिका सरकार द्वारा दिया गया संयुक्त बयान आखिर है क्या? यह पतंग है, पक्षी है या फिर हवाई जहाज है? संयुक्त बयान ने कई अटकलों को जन्म दिया है। ऊपर से सरकार के टालमटोल और अस्पष्ट रवैये से संदेह के बादल और गहरा गए हैं। व्यापार सौदे की शर्तें तय करने वाले कार्ड डोनाल्ड ट्रंप के हाथ में हैं, इसलिए अमेरिका के लिए यह बयान शायद ज्यादा अहमियत न रखता हो, लेकिन भारत के लिए निश्चित रूप से चिंता का विषय है।

सच्चाई यह है कि यह संयुक्त बयान भ्रामक आधार पर सामने आया है। साल 2025 में भारतीय वार्ताकार बार-बार दावा करते रहे कि वे अमेरिका के साथ एक द्विपक्षीय व्यापार समझौते पर बातचीत कर रहे हैं। वाणिज्य मंत्री ने कई मौकों पर कहा कि समझौता जल्द ही हो जाएगा, बल्कि साल के अंत तक पूरा होने की बात भी कही गई। लेकिन जब संयुक्त बयान सामने आया तो सच्चाई कुछ और ही निकली। यह न तो पूरी तरह से द्विपक्षीय व्यापार समझौता (बीटीए) है, न ही कोई अंतरिम समझौता। यह केवल एक अंतरिम समझौते का ढांचा भर है। मामला खोदा पहाड़, निकली चुहिया जैसी है!

संयुक्त बयान के बाद दोनों देशों ने दावा किया कि समझौता पारस्परिक है। यह दावा आम आदमी की समझ से परे है। संयुक्त बयान को सरसरी तौर पर देखने से साफ हो जाता है कि यह पारस्परिकता के सिद्धांत पर आधारित नहीं है। संयुक्त बयान के हिस्सों पर गौर करने की जरूरत है।

जहां भारत अमेरिका के सभी औद्योगिक उत्पादों और बड़ी संख्या में खाद्य व कृषि

उत्पादों पर शुल्क पूरी तरह खत्म करेगा या घटाएगा, वहीं अमेरिका भारत से आने वाली वस्तुओं पर 18 प्रतिशत का पारस्परिक शुल्क लगाएगा (जो 2 अप्रैल, 2025 को लगाए गए 25 प्रतिशत शुल्क से कम किया गया है)। इसमें कपड़े व परिधान, चमड़ा व जूते, प्लास्टिक व रबर, ऑर्गेनिक केमिकल्स, होम डेकोर, हस्तशिल्प उत्पाद और कुछ मशीनरी शामिल हैं। अमेरिका जेनेरिक दवाइयों, रत्न-हीरों और विमान के पुर्जों समेत कई वस्तुओं पर लगाया गया यह पारस्परिक शुल्क तभी हटाएगा, जब अंतरिम समझौता सफलतापूर्वक पूरा हो जाएगा। यहां 0 प्रतिशत बनाम 18 प्रतिशत में पारस्परिकता कहां है?

भारत अमेरिका के चिकित्सा उपकरणों के व्यापार में लंबे समय से चली आ रही बाधाओं को दूर करने और अमेरिकी आईसीटी उत्पादों के बाजार में आने में देरी करने वाली कड़ी आयात लाइसेंस प्रक्रियाओं को खत्म करने पर सहमत हुआ है। भारत अमेरिका के खाद्य और कृषि उत्पादों के व्यापार में मौजूद गैर-शुल्कीय बाधाओं को भी दूर करने पर राजी हुआ है। इसके बदले अमेरिका पर कोई समान बाध्यता नहीं है। फिर गैर-शुल्कीय अवरोधों के मामले में दायित्व बनाम बिना दायित्व के बीच पारस्परिकता कहां है?भारत अगले पांच वर्षों में अमेरिका से 500 अरब डॉलर के ऊर्जा उत्पाद, विमान व उनके पुर्जे, कीमती धातुएं, तकनीकी उत्पाद और कोकिंग कोयला खरीदने की इच्छा रखता है। दोनों सरकारें तकनीकी उत्पादों के व्यापार को काफी बढ़ाएंगी, जिनमें डाटा सेंटरों में इस्तेमाल होने वाले ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट्स जैसे उत्पाद शामिल हैं। इस पूरे अनुच्छेद में जिन वस्तुओं का जिक्र है, वे सभी अमेरिकी निर्यात की वस्तुएं हैं। ऐसी कोई भारतीय वस्तु नहीं बताई गई, जिसे अमेरिका खरीदने जा रहा हो, तो फिर पारस्परिकता कहां है? संयुक्त बयान के साथ जारी एक कार्यकारी आदेश में डोनाल्ड ट्रंप ने भारत द्वारा उठाए गए महत्वपूर्ण कदमों का उल्लेख किया- रूस से सीधे या परोक्ष रूप से तेल आयात बंद करने की भारत की प्रतिबद्धता, अमेरिका से ऊर्जा उत्पाद खरीदने का आश्वासन और रक्षा सहयोग बढ़ाने को लेकर दोनों देशों के बीच समझौता। इन तीन वादों के आधार पर ट्रंप ने 6 अगस्त, 2025 को लगाए गए अतिरिक्त दंडात्मक शुल्क (25%) को हटाने का फैसला किया।

प्रधानमंत्री मोदी की एक और गारंटी हुई पूरी

महिला स्व सहायता समूहों ने शुरू किया रेडी-टू-ईट का उत्पादन

रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य में कुपोषण दूर करने और महिला सशक्तिकरण के लिए रेडी-टू-ईट फूड निर्माण का काम महिला स्व-सहायता समूहों को सौंपते हुए 6 जिलों में पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया है। इस पहल के तहत रायगढ़, बस्तर, दंतेवाड़ा, बलौदाबाजार, कोरबा, और सूरजपुर जिलों में आंगनबाड़ियों के लिए पौष्टिक आहार निर्माण का कार्य महिला समूहों को मिला है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि राज्य सरकार ने आंगनबाड़ी केंद्रों के लिए पूरक पोषण आहार (रेडी टू ईट) के निर्माण और वितरण का कार्य महिला स्वसहायता समूहों को सौंपने का फैसला किया। राज्य के 6 जिले के 42 महिला स्व-सहायता समूहों को रेडी टू ईट के निर्माण और वितरण का कार्य सौंपा गया है।

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में महिला सशक्तिकरण और कुपोषण मुक्ति के इस मिशन को प्रथम चरण में प्रदेश के 6 जिलों - बस्तर, दंतेवाड़ा, बलौदाबाजार, कोरबा, रायगढ़ एवं सूरजपुर में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में लागू किया जा रहा है। वहीं रायगढ़ प्रदेश का पहला जिला बन गया है, जहां महिला समूहों ने 'रेडी-टू-ईट' उत्पादन प्रारंभ किया है। यह पहल महिलाओं की आर्थिक समृद्धि और बच्चों के स्वास्थ्यकृदोनों को नई दिशा प्रदान करेगी। महिला एवं बाल विकास विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार कोरबा-10 स्व-सहायता समूह को रेडी-टू-ईट निमाण का कार्य सौंपा जा चुका है। इसी प्रकार रायगढ़-10 स्व-सहायता समूह, सूरजपुर और बलौदाबाजार-भाठापारा जिला में 7-7 स्व- सहायता समूह को, बस्तर जिले में 6 स्व-सहायता समूह और दंतेवाड़ा में 2 महिला स्व-सहायता समूह को रेडी-टू-ईट निमाण का कार्य सौंपा जा चुका है। न स्व-सहायता समूहों के द्वारा आंगनबाड़ी केंद्रों के लिए पूरक पोषण आहार का निर्माण और वितरण का कार्य किया जा रहा है। महिला एवं बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े ने कहा कि इन समूहों की बहनें अब आंगनबाड़ी के बच्चों को पौष्टिक आहार उपलब्ध कराने के साथ-साथ इस कार्य से अपनी आमदनी भी बढ़ाएंगी, जिससे वे आर्थिक रूप से सशक्त बनेंगी। यह योजना महिलाओं को स्व-रोजगार के साथ-साथ सामाजिक और आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में भी एक बड़ा कदम है।

प्रख्यात कलाकार अरुण गोविल ने दी सुनो श्री राम कहानी की भावपूर्ण प्रस्तुति

■ आस्था, संस्कृति और रामकथा से आलोकित हुआ राजिम कुंभ कल्प 2026

रायपुर । छत्तीसगढ़ के प्रयाग राजिम की पावन धरा पर आयोजित राजिम कुंभ कल्प 2026 में आस्था, संस्कृति और अध्यात्म का अद्भुत संगम देखने को मिला। त्रिवेणी संगम के पावन तट पर आयोजित सांस्कृतिक संध्या में सुप्रसिद्ध कलाकार एवं भगवान श्रीराम की भूमिका से जनमानस में विशेष पहचान रखने वाले श्री अरुण गोविल ने सुनो श्री राम कहानी की भावपूर्ण प्रस्तुति दी, जिससे संपूर्ण परिसर भक्ति और श्रद्धा के दिव्य वातावरण से ओतप्रोत हो उठा।

इस अवसर पर श्री अरुण गोविल ने मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय से आत्मीय भेंट की तथा राजिम कुंभ कल्प के भव्य आयोजन और उत्कृष्ट व्यवस्थाओं की सराहना की। मुख्यमंत्री श्री साय ने उन्हें स्मृति-चिह्न भेंट कर सम्मानित किया। श्री गोविल ने कहा कि छत्तीसगढ़ की सांस्कृतिक विरासत, जनआस्था और लोगों का आत्मीय स्नेह उनके लिए अविस्मरणीय अनुभव रहा।

मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने कहा कि राजिम कुंभ कल्प केवल धार्मिक आयोजन नहीं, बल्कि हमारी सनातन परंपरा, सांस्कृतिक विरासत और आध्यात्मिक चेतना का जीवंत उत्सव है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार आस्था, संस्कृति और पर्यटन के संरक्षण-संवर्धन के लिए निरंतर प्रतिबद्ध है तथा ऐसे आयोजनों के माध्यम से छत्तीसगढ़ की पहचान राष्ट्रीय स्तर पर और सशक्त हो रही है।

कार्यक्रम में खाद्य मंत्री श्री दयाल दास बघेल, संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री श्री राजेश अग्रवाल, महासमुंद सांसद श्रीमती रूपकुमारी चौधरी, राजिम विधायक श्री रोहित साहू सहित अनेक जनप्रतिनिधियों, संत-महात्माओं एवं श्रद्धालुओं की गरिमामयी उपस्थिति थी।

मुख्यमंत्री साय ने लोकतंत्र सेनानी से की मुलाकात

रायपुर। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय आज बैकुंठपुर निवासी 92 वर्षीय लोकतंत्र सेनानी डॉ. निर्मल घोष के निवास पहुंचे और उनसे सौजन्य भेंट कर उनका कुशलक्षेम जाना। मुख्यमंत्री साय ने डॉ. घोष का शॉल और फल से सम्मानित किया। साथ ही उनके परिजनों से आत्मीय चर्चा की। मुख्यमंत्री साय ने कहा डॉ. घोष का संघर्ष, राष्ट्रप्रेम और जीवटता आज भी हमारे लिए प्रेरणादायी है। इस आयु में भी उनकी स्मरण शक्ति और ज्ञान हम सभी के लिए अनुकरणीय है। लोकतंत्र सेनानी से मिलना और उनका आशीर्वाद प्राप्त करना मेरे लिए सौभाग्य की बात है।

इस अवसर पर डॉ. घोष ने वर्ष 1975 में लगाए गए आपातकाल के दौरान के अपने अनुभव मुख्यमंत्री से साझा किए। उन्होंने बताया कि आपातकाल के समय उन्हें लगभग 19 माह तक विभिन्न जेलों में निरुद्ध रखा गया था। डॉ. घोष ने अपने छात्र जीवन की स्मृतियों को साझा करते हुए बताया कि उन्होंने मिशन स्कूल, माधव राव सप्रे स्कूल तथा नागपुर में अध्ययन किया। वर्ष 1955 में वे आयुर्वेदिक कॉलेज में प्रवेश लिए और सागर विश्वविद्यालय से बीएमएस की डिग्री प्राप्त की। सरकारी सेवा में न जाकर उन्होंने वर्ष 1960 में बैकुंठपुर में निजी चिकित्सालय प्रारंभ किया और लंबे समय तक जनसेवा करते रहे। इस मौके पर कृषि मंत्री राम विचार नेताम, स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल, भइया लाल राजवाड़े सहित अन्य जनप्रतिनिधिगण उपस्थित थे।

मुख्य सचिव ने मंत्रालय महानदी भवन में नवा अंजोर विजन 2047 मॉनिटरिंग पोर्टल की समीक्षा की

रायपुर। मुख्य सचिव श्री विकासशील ने आज मंत्रालय महानदी भवन में आयोजित बैठक में छत्तीसगढ़ नवा अंजोर विजनञ्ज 2047 मॉनिटरिंग पोर्टल की विस्तृत समीक्षा की। बैठक में राज्य शासन के विभिन्न विभागों के सचिव उपस्थित रहे।

मुख्य सचिव ने नवा अंजोर विजनञ्ज 2047 के अंतर्गत निर्धारित इंडिकेटर्स की राज्य स्तरीय समीक्षा करते हुए सभी विभागीय सचिवों को निर्देशित किया कि वे अपने-अपने विभाग से संबंधित योजनाओं एवं कार्यक्रमों की प्रगति, निर्धारित लक्ष्यों की नियतकालिक उपलब्धि तथा अद्यतन जानकारी मॉनिटरिंग पोर्टल में समय-समय पर दर्ज करना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि पोर्टल के माध्यम से योजनाओं की प्रगति की प्रभावी निगरानी एवं मूल्यांकन संभव है, जिससे राज्य के विकास लक्ष्यों की प्राप्ति में गति आएगी।

मुख्य सचिव ने सभी विभागीय सचिवों को अपने विभागीय डैशबोर्ड पर ऑनलाइन प्रगति की नियमित समीक्षा करने तथा निर्धारित इंडिकेटर्स के अनुरूप कार्यों में तेजी लाने के निर्देश भी दिए।बैठक में विजन 2047 के लक्ष्यों की समयबद्ध पूर्ति हेतु समन्वित एवं परिणामोन्मुख कार्यवाही पर विशेष जोर दिया गया।

भाजपा के लिए राजनीति केवल सत्ता का साधन नहीं: पारख

रायपुर। भारतीय जनता पार्टी के मुख्य प्रवक्ता और सांसद संतोष पाण्डेय ने कहा है कि भाजपा में नए पदाधिकारियों के निर्वाचन और नियुक्ति के बाद उन्हें पार्टी की कार्यशैली से अवगत कराना एक अनिवार्य प्रक्रिया है। पार्टी हर स्तर पर पदाधिकारियों को चुस्त-दुरुस्त और प्रशिक्षित करने के लिए निरंतर कार्यशालाएँ आयोजित करती है। इन प्रशिक्षणों का मुख्य उद्देश्य डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी के राष्ट्रवाद के विचारों और पंडित दीनदयाल उपाध्याय के अंत्योदय के संकल्प को बूथ स्तर तक ले जाना है। इन प्रशिक्षण कार्यशालाओं में कार्यकर्ताओं को बताया जाता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक कैसे प्रभावी ढंग से पहुँचाया जाए? श्री पाण्डेय सोमवार को कुशाभाऊ ठाकरे परिसर स्थित भाजपा प्रदेश कार्यालय में पत्रकारों से चर्चा कर रहे थे।

पाण्डेय ने कहा कि भाजपा के लिए राजनीति केवल सत्ता का साधन नहीं, बल्कि विचारधारा के विस्तार और जनसेवा का माध्यम है। मिशन 2028 और चुनावी तैयारियों को लेकर श्री पाण्डेय ने कहा कि भाजपा एक जीवंत संगठन है। हमारे यहाँ एक चुनाव संपन्न होने के अगले ही दिन से आगामी चुनाव की तैयारी शुरू हो जाती है। यह कहना गलत नहीं होगा कि भाजपा केवल युद्ध काल में ही सक्रिय नहीं रहती, बल्कि हम शांति काल में भी युद्ध (संगठनात्मक समर) की पूरी तैयारी रखते हैं। बलरामपुर की घटना के परिप्रेक्ष्य में कांग्रेस के आरोपों पर पलटवार कर श्री पाण्डेय ने कहा कि सरकार और प्रशासन पूरी संवेदनशीलता के साथ इस मामले की जाँच कर रहे हैं।

छत्तीसगढ़/राजधानी

प्रमुख समाचार

भाजपा सरकार में प्रशासनिक आतंकवाद चरम पर: बैज

रायपुर। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने बलरामपुर जिला के कुसमी के मृतक किसान को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि एसडीएम सहित सभी दोषियों पर हत्या का मुकदमा दर्ज करने एवं मृतक किसान के परिवार को एक करोड़ रुपया मुआवजा देने एवं घायलों का उचित ईलाज कराने व घटना की उच्चस्तरीय जांच की मांग की। उन्होंने कहा भाजपा सरकार में प्रशासनिक आतंकवाद चरम पर है।

खनिज तस्करों को भाजपा सरकार का खुला संरक्षण है। प्रशासनिक अधिकारी तस्करों को रोकने के बजाय खनिज तस्करी का विरोध कर रहे लोगों के साथ मारपीट कर रहे है, उन्हें जख्मी कर रहे है, उनकी हत्या कर दी जा रही है। ये घटना सरकार और तस्करों की सांठगांठ का परिणाम है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि भाजपा सरकार बनने के बाद प्रदेश खनिज तस्करों का गढ़ बन गया है। सरकार के संरक्षण में खुलेआम बॉक्ससाईड, आयरन ओर, कोयला, रेत की तस्करी हो रही है। प्रदेश की खनिज संपदा को लूटा जा रहा है जिसका विरोध जनता लगातर कर रही है। दुर्भाग्य की बात है सरकार तस्करों पर कार्यवाही करने के बजाय तस्करी रोकने वाली जनता पर लाठियां भांज रही है, फर्जी मुकदमे दर्ज कर रही है। एक ओर तस्करों के गुर्गे जनता को अवैध हथियार से गोली चलाकर डरा रही है।

शिक्षा स्वास्थ रोजगार की दुर्गति हो गई कर्ज बढ़ा: ठाकुर

रायपुर। कांग्रेस ने प्रदेश में आने वाले बजट में जनता को भ्रमित करने वाला भारी भरकम आधारहीन आंकड़ो की जादूगरी वाला छद्म बजट के अलावा कुछ नही होगा। प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर ने कहा कि वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने पिछली दो बार के बजट को ज्ञान और गति नाम दिया था, लेकिन ज्ञान और गति कही दिखा नही। उल्टा बजट के बाद प्रदेश की विकास

थम गई, शिक्षा, स्वास्थ, रोजगार कानून व्यवस्था की दुर्गति हो गई। स्थिति यह है सरकार को 3500 करोड़ रुपया प्रति महीना कर्ज लेना पड़ रहा है। प्रदेश पर 1 लाख 25 हजार करोड़ से अधिक का कर्ज चढ़ गया। प्रत्येक नागरिक 65 हजार रु के कर्जदार बन गये। बजट में खर्च करने लायक राशि भी नहीं दी गई। प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर ने कहा वित्त मंत्री बताये पिछली बजट में जो घोषणाये हुई थी वो पूरा क्यो नही हुई? 20 हजार शिक्षकों की भर्तियां क्यो नही हुई। मोदी की गारंटी 18 लाख नया पीएम आवास देने की थी उसमें से एक भी आवास स्वीकृत क्यो नही हुई? जिन पीएम आवास का निर्माण कांग्रेस सरकार में शुरू हो चुका था उसकी दूसरी तीसरी क़िस्त क्यो नही दिया गया? किसानों को बोवाई के समय पर्याप्त मात्रा में मंगनुसार खाद क्यो नही दिया गया।

पूरक पोषण आहार यूनिट का शुभारंभ

रायपुर। महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े ने आज सूरजपुर जिले के विकासखंड ओड़गी अंतर्गत ग्राम पालदनौली में पूरक पोषण आहार निर्माण यूनिट का विधिवत शुभारंभ किया। इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार बच्चों, गर्भवती महिलाओं एवं धात्री माताओं के बेहतर स्वास्थ्य और पोषण सुरक्षा के लिए सतत रूप से कार्य कर रही है। यह यूनिट कुपोषण उन्मूलन की दिशा में एक महत्वपूर्ण और परिणामोन्मुखी पहल है। मंत्री राजवाड़े ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के सुपोषित भारत के संकल्प तथा मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ सरकार कुपोषण के विरुद्ध व्यापक अभियान चला रही है। पालदनौली में स्थापित यह यूनिट स्थानीय स्तर पर ताजा, गुणवत्तापूर्ण एवं पोषक आहार की उपलब्धता सुनिश्चित करेगी, जिससे बच्चों और माताओं के स्वास्थ्य में सकारात्मक सुधार आएगा। इस यूनिट में मीठा शक्ति आहार एवं नमकीन पौष्टिक दलिया का निर्माण किया जाएगा। यूनिट का संचालन राधे महिला स्वयं सहायता समूह, पालदनौली द्वारा किया जाएगा। स्थानीय स्तर पर उपलब्ध पौष्टिक सामग्रियों से तैयार आहार आंगनबाड़ी केंद्रों के माध्यम से 6 माह से 6 वर्ष तक के बच्चों, गर्भवती महिलाओं एवं धात्री माताओं को नियमित रूप से उपलब्ध कराया जाएगा।

मिड डे मील योजना बंद होने के कगार पर : वंदना राजपूत

रायपुर। कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता वंदना राजपूत ने भारतीय जनता पार्टी सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि मिड डे मील योजना को बंद करने का भाजपा सरकार षड्यंत्र कर रही है। पिछले 40 दिनों से बच्चों को पोषण आहार नहीं मिल रहा है जिसके कारण बच्चों की स्कूलों में उपस्थिति कम होती जा रही है। मिड डे मील योजना स्कूली बच्चों में कुपोषण, भूख और शिक्षा की कमी जैसे समस्याओं

के समाधान के लिए शुरू किया गया था, जिसमें सरकार को सफलता भी मिल रही थी लेकिन वर्तमान भाजपा के सरकार में स्पष्ट नीति नहीं होने के कारण मध्यान भोजन बंद होने के कगार पर आ गया है। पिछले लगभग 40 दिनों से बच्चों को मध्यान्ह भोजन नहीं मिल पा रहा है। कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता वंदना राजपूत ने कहा कि रसोईया संघ प्रदेश व्यापी हड़ताल पर पिछले लगभग 40 दिनों से है। हड़ताल के दौरान दो महिलाओं की मौत हो जाती है, कई महिलाओं की स्थिति भी चिंताजनक बताई जा रही है। भाजपा, भाषण में महिला सशक्तिकरण पर बड़ी-बड़ी और लुभावने बातें करते हैं लेकिन धरातल पर महिलाएं अपने अधिकार की लड़ाई लड़ते-लड़ते मर रही है। दो महिलाओं की मौत के बाद भी सरकार नींद से नहीं जागी और न जाने कितने मौत का इंतजार कर रही है।

भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाने से घबराई सरकार: साहू

रायपुर। आम आदमी पार्टी, नारायणपुर के जिला अध्यक्ष एवं विधानसभा के पूर्व प्रत्याशी नरेंद्र नाग लंबे समय से क्षेत्र के लोगों के हक और अधिकारों के लिए निरंतर संघर्ष कर रहे हैं। इसके बावजूद प्रशासन द्वारा लगातार उपेक्षा और दमनात्मक रवैया अपनाया जा रहा है। आज पार्टी के कई नेताओं को घर से उठाकर हिरासत में लिया गया है, परंतु उन्हें कहां रखा गया है इसकी स्पष्ट

जानकारी तक नहीं दी जा रही है, जो लोकतांत्रिक मूल्यों के विरुद्ध है। आम आदमी पार्टी के नेता समीर खान ने कहा कि यदि सरकार और प्रशासन अपनी-अपनी जिम्मेदारियों का ईमानदारी से निर्वहन करें तो क्षेत्र की समस्याओं का समाधान संभव है। परंतु बस्तर संभाग में स्थिति इसके विपरीत दिखाई दे रही है। जब भी कोई व्यक्ति या संगठन भ्रष्टाचार और जनहित के मुद्दों को उजागर करता है, तो उसे परेशान किया जाता है और आंदोलनों को दबाने का प्रयास किया जाता है। पार्टी का स्पष्ट मत है कि लोकतंत्र में प्रत्येक नागरिक और राजनीतिक दल को शांतिपूर्ण आंदोलन एवं धरना-प्रदर्शन करने का संवैधानिक अधिकार है। किंतु दक्षिण बस्तर में पुलिस प्रशासन की दमनकारी नीति के कारण लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन हो रहा है।

राजधानी रायपुर में पुलिस आयुक्त प्रणाली की शुरुआत

रायपुर पुलिस कमिश्नरेट में शुरू हुई कोर्ट की प्रोसिडिंग

रायपुर। रायपुर में पुलिस आयुक्त प्रणाली की शुरुआत होने के साथ ही अब दंडाधिकारी शक्तियां कमिश्नरी में निहित हो गई हैं। अब कार्यपालिका दंडाधिकारियों की जगह पुलिस कमिश्नरेट के सहायक आयुक्त अधिकारी कोर्ट की शुरुआत करेंगे। सेंट्रल जोन डीपी उमेश गुप्ता के मार्गदर्शन में आज से कमिश्नरी व्यवस्था में न्यायालयीन सख्ती की दमदार शुरुआत हो गई है। पहले दिन एसीपी कोतवाली और एसीपी सिविल लाइन कोर्ट का प्रथम दिवस रहा।

रायपुर में कमिश्नरी व्यवस्था लागू होने के पश्चात सेंट्रल जोन अंतर्गत न्यायालयीन कार्यवाही का प्रभावी शुभारंभ आज 16 फरवरी से किया गया। इस अवसर पर सहायक पुलिस आयुक्तों द्वारा कार्यपालक दंडाधिकारी की शक्तियों का प्रयोग करते हुए लोक शांति एवं कानून-व्यवस्था बनाए रखने की दिशा में त्वरित एवं सख्त कदम उठाए गए।

इसी क्रम में सहायक पुलिस आयुक्त कोतवाली दीपक मिश्रा द्वारा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 170, 126 एवं 135(3) के अंतर्गत एक प्रकरण में 02 अनावेदकों के विरुद्ध कार्यवाही करते हुए जेल वारंट तैयार किए गए। साथ ही दोनों अनावेदकों को कारण बताओ नोटिस विधिवत तामील कराए गए। इसके अतिरिक्त धारा 126 एवं 135(3) भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के अंतर्गत 05 प्रकरणों में कुल 13 अनावेदकों को कारण बताओ नोटिस एवं समन जारी किए गए, जिन्हें कमिश्नरी प्रणाली के तहत त्वरित रूप से तामील कराया गया।

वहीं सहायक पुलिस आयुक्त सिविल लाइन रमाकांत साहू द्वारा भी लोक शांति भंग होने की आशंका के दृष्टिगत धारा 126 एवं 135(3) भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के तहत 06 अनावेदकों को कारण बताओ नोटिस जारी किए गए। कमिश्नरी प्रणाली के अंतर्गत की गई इस कार्यवाही में सभी समन एवं नोटिस समयबद्ध रूप से तामील कराए गए। कमिश्नरेट व्यवस्था के अंतर्गत यह न्यायालयीन कार्यवाही कानून-व्यवस्था को सुदृढ़ करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है, जिससे यह स्पष्ट संदेश गया है कि सार्वजनिक स्थानों पर उपद्रव, झगड़ा अथवा लोक शांति भंग करने वालों के विरुद्ध अब त्वरित, विधिसम्मत एवं सख्त कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।

परीक्षा को बनाये मन की इच्छा परिणाम इच्छानुसार मिलेंगे : चोपड़ा

रायपुर। जैन संवेदना ट्रस्ट द्वारा बच्चों से बच्चों की बात कार्यशाला का आयोजन श्री आदिश्वर जैन माध्यमिक शाला व वर्धमान इंग्लिश मीडियम स्कूल सदर बाजार में किया गया। ट्रस्ट के अध्यक्ष महेन्द्र कोचर ने बताया कि बच्चों के मन में वार्षिक परीक्षा के डर को दूर करने व परीक्षा में सफलता के लक्ष्य निर्धारण हेतु मोटिवेशनल कार्यशाला आयोजित की जा रही है। आज की कार्यशाला में प्रसिद्ध शिक्षाविद विजय चोपड़ा ने कैसी हो भयमुक्त परीक्षा की तैयारी विषय पर बच्चों को मोटिवेशनल स्पीच देते हुए कहा कि परीक्षा में अच्छे परिणाम के लिए सही प्लानिंग, व्यवस्थित प्रिपरेशन व कड़ा परिश्रम बहुत जरूरी है। चोपड़ा ने अच्छे परिणाम के लिये प्लानिंग , प्रिपरेशन व परिश्रम को विस्तारित करते हुए कहा कि प्रिपरेशन के पूर्व अच्छी प्लानिंग करें। कुल विषयों को परीक्षा के बचे दिन से भाग देकर प्रत्येक विषय के लिये दिन निर्धारित करें। प्रत्येक विषय को तीन श्रेणी में बांट लें। वस्तुनिष्ठ प्रश्न , मन पसंद सरल प्रश्न व कठिन प्रश्न। तैयारी करते समय सरल प्रश्न से आरम्भ कर आगे बढ़ेंगे तो आत्मविश्वास भी बढ़ेगा। कठिन प्रश्नों की तैयारी के लिए प्रातः काल ब्रम्हमुहूर्त का समय बेहतर होगा। इस तरह के प्रयास अच्छे परिणाम देंगे।

परीक्षा की तैयारी को स्वयं की इच्छा बनाएं फिर सफलता सौ प्रतिशत तय है। परीक्षा को बोझ या हव्वा न मानें बल्कि परीक्षा पर हावी होकर तैयारी में जुट जाएं। लगन , मेहनत , अनुशासन व आत्मविश्वास से ही पूर्ण सफलता प्राप्त होती है। इसे मूलमंत्र बनाएं , पूर्ण मनोभावों से किये परिश्रम से ही अच्छे परिणाम सामने आते हैं। अभी परीक्षा में एक पखवाड़े का समय शेष है , एक बात तय है कि सफलता का कोई शॉर्टकट नही होता सो विषयों के अनुसार टाईम टेबल सेट करें , ऊँचा लक्ष्य निर्धारित करें अपनी क्षमता पर विश्वास करें व प्लानिंग से तैयारी आरम्भ कर देवें।

आर.एन.आई.रजि. क्र. CHHHIN/2021/80529, स्वत्वाधिकारी, मुद्रक एवं प्रकाशक- शशांक शर्मा द्वारा मिशन मीडिया प्रा. लि., प्रेस कॉम्प्लेक्स, रजबंधा मैदान, रायपुर (छ.ग.) 492001 से मुद्रित एवं 29/1110, सेवती स्मृति, आजाद चौक, रायपुर (छ.ग.) 492001 से प्रकाशित। संपादक-शशांक शर्मा, मो. 94255-20531.